हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

आम बजट - 2026

जैसा था वैसा

- इनकम टैक्स
- एलपीजी गैस सिलेंडर
- बिजली बिल
- मोबाइल रिचार्ज
- स्कूल फीस

बजट का 'पावर बूस्टर'

- **पूंजीगत निवेश** 12.2 लाख करोड़
- **फोकस** नई सड़कें, पुल और औद्योगिक बुनियादी ढांचा
- **लक्ष्य** विकास की रफ्तार को टॉप गियर में डालना

■ टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं ■ 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा

रक्षा, शिक्षा, हेल्थ पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम, फिर भी बाजार धड़ाम!

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए लोकलुभावन योजनाओं से परहेज किया और 'सुधार एक्सप्रेस' को जारी रखने की घोषणा की। सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए किसानों, युवाओं और छोटी कंपनियों पर विशेष ध्यान देने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दिया और सुधारों का खाका पेश किया। कुल मिलाकर, यह बजट आत्मनिर्भरता, तेज विकास और चुनावी राज्यों में निवेश पर केंद्रित है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, रोजगार बढ़ेगा और भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत बनेगा। इधर, बजट को बाजार समझ नहीं पाया और धड़ाम हो गया। कुछ ही पल में निवेशकों ने लाखों करोड़ रुपए डूब गए।

किसे कितना बजट

रक्षा मंत्रालय
7,84,678.28 करोड़
गृह मंत्रालय
2,55,233.53 करोड़
आयुष मंत्रालय
4,408.93 करोड़
रेल मंत्रालय
2,77,830 करोड़
कृषि मंत्रालय
1,62,671 करोड़
स्वास्थ्य मंत्रालय
1,06,530.42 करोड़
खेल मंत्रालय
4479.88 करोड़

बजट में खास

- 85 मिनट के भाषण में सीतारमण ने इस बार नहीं किया किसी कवि और कविता का उल्लेख
- नई ग्रामीण रोजगार योजना 'वीबी-जी राम जी' के लिए 95,000 करोड़ आवंटित
- वित्त मंत्री ने पांच चिकित्सकीय पर्यटन केंद्र स्थापित करने का रखा प्रस्ताव
- संशोधित आयकर रिटर्न जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव

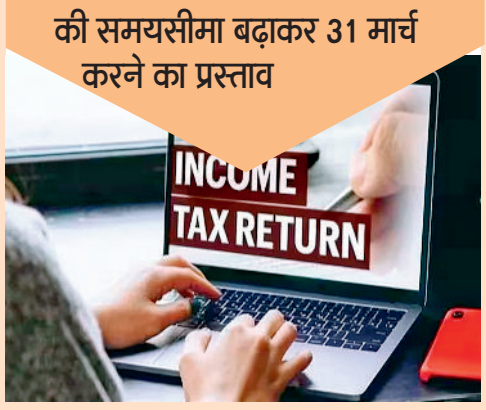

- बजट में छोटे करदाताओं के लिए छह महीने की विदेशी संपत्ति खुलासा योजना की घोषणा
- पुनर्खरीद से होने वाली प्राप्ति पर अब लगेगा 'पूंजीगत लाभ कर'
- बजट में अगले पांच साल में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव
- केंद्र सरकार प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के पास पांच विवि टाउनशिप स्थापित करेगी
- मंत्रियों, मंत्रिमंडल सचिवालय और पीएमओ के खर्च के लिए 1,102 करोड़
- बाबुओं के प्रशिक्षण के लिए 299 करोड़ रुपए, प्रशासनिक सुधारों को 65 करोड़

किसानों के लिए खास

कोकोनट प्रमोशन स्कीम

नई स्कीम का उद्देश्य नारियल का उत्पादन बढ़ाना। इस योजना के तहत प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में कम उत्पादक पेड़ों को नए, उच्च उपज देने वाले पौधों से बदलने जैसे कदम उठाए जाएंगे।

पशुपालन और डेयरी

पशुपालन क्षेत्र में सरकार ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करेगी। इसके साथ ही किसानों के उत्पादक संगठन बनाने पर काम किया जाएगा।

काजू-कोको और चंदन

काजू और कोको सेक्टर को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की। चंदन के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकरबढ़ावा देगी।

हरिभूमि न्यूज ▶▶| नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिर्माण पर जोर देने के साथ पूंजीगत व्यय लक्ष्य बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जो चालू वित्त वर्ष के लिए 11.2 लाख करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री ने लगभग सवा घंटा के अपने बजट भाषण में सुधारों का खाका पेश करते हुए 'विकसित भारत' के लिए बैंकों को तैयार करने को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति के गठन का भी प्रस्ताव किया। उन्होंने वृद्धि के प्रमुख इंजन के रूप में एमएसएमई के महत्व को रेखांकित करते हुए 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास कोष का प्रस्ताव रखा। इसका मकसद क्षेत्र में भविष्य के 'चैंपियन' तैयार करना और उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। बजट का ताना-बाना 'तीन कर्तव्यों' यानी आर्थिक वृद्धि को गति देने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और 'सबका साथ, सबका विकास' के इर्द-गिर्द बुना गया है। बजट में किसानों की आय बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य से 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास करने, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को मजबूती प्रदान करने तथा स्टार्टअप एवं महिलाओं की अगुवाई वाले समूह को मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों के साथ शामिल करते हुए बाजार से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। सीतारमण ने तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों में सहायता प्रदान कर उच्च मूल्य वाली खेतीबाड़ी पर जोर दिया। बजट में आयकर की दरों एवं संरचना के मोर्चे पर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब | गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती

महंगा

मिनरल्स स्क्रैप शराब

सस्ता

- लेदर
- कपड़ा
- सिंथेटिक फुटवियर
- विदेशी यात्रा
- कैंसर की 17 दवाएं
- माइक्रोवेव ओवन
- जूते
- एयरक्राफ्ट निर्माण से जुड़ी चीजें
- ईवी बैटरी
- शुगर की दवाएं
- चमड़े और कपड़े का निर्यात
- बायोगैस मिक्स्ड सीएनसी
- सोलर ग्लास
- मिक्स्ड गैस सीएनजी
- विमानों का ईंधन

चुनावी राज्यों पर फोकस

- तमिलनाडु और केरल में रेयर अर्थ कॉरिडोर से खनन और इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा
- पश्चिम बंगाल में वाराणसी-सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी
- असम और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी

सरकार के तीन कर्तव्य

- अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता बनाए रखकर आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना
- जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं को मजबूत करना और उन्हें भारत की समृद्धि की यात्रा में सक्रिय भागीदार बनाना।
- 'सबका साथ, सबका विकास' सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य परिवार, समुदाय और क्षेत्र को संसाधन प्रदान करना है।

इनकम टैक्स चोरी पर जेल नहीं, जुर्माना

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है, तो अब उसे जेल की सजा नहीं होगी। ऐसे मामलों में केवल जुर्माना भरकर मामला रफा-दफा किया जा सकेगा। यह नया बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 'नए इनकम टैक्स एक्ट' का हिस्सा होगा। साथ ही, जिनके पास विदेशों में अघोषित संपत्ति है, उन्हें भी एक मौका दिया गया है। वे अगले 6 महीनों के भीतर डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपनी संपत्ति की जानकारी दे सकते हैं।

सीतारमण का 'बजट लुक'

इस बार बैंगनी रंग की साड़ी: बैंगनी रंग महिला सशक्तीकरण, गरिमा, न्याय और समानता का प्रतीक माना जाता है। यह रंग अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और नारी अधिकार आंदोलन से भी जुड़ा रहा है। यह इशारा है कि बजट में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य या आर्थिक सहायता पर फोकस रहा।

विकसित भारत के लिए स्पष्ट रूपरेखा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को 'ऐतिहासिक' बताते हुए कहा कि यह

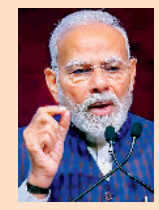

140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है। विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि बजट में 'अवसरों की अपार संभावनाएं' हैं।

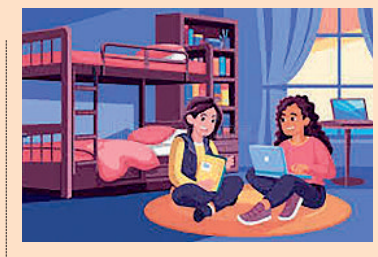

हर जिले में बालिका छात्रावास

- देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल स्थापित करने की घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं। गर्ल्स हॉस्टल के बन जाने के बाद लड़कियों को घर से बाहर सुरक्षित और आसान निवास की सुविधा मिलेगी।

5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप

- देश में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का विकास होगा। इन टाउनशिप में पढ़ाई, रिसर्च, हॉस्टल, खेल और स्टार्टअप जैसी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही देश में 5 नए विश्वविद्यालय खोले जाने की भी घोषणा की गई।

युवाओं को क्या मिला

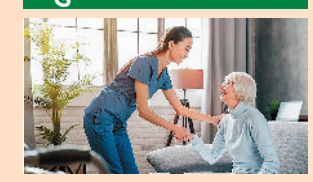

1.5 लाख केयरगिवर्स की ट्रेनिंग

सरकार देश में तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी और स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले एक साल में 1.5 लाख केयरगिवर को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। यह ट्रेनिंग मुख्य रूप से योग, वेलनेस और चिकित्सा उपकरणों के संचालन से संबंधित होगी।

किसने क्या कहा

संकटों से मूंद ली आंखें

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्रीय बजट में भारत के सामने

मौजूद वास्तविक संकटों से आंख मूंद ली गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, विनिर्माण गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत घट रही है, किसान संकट में हैं। आसन्न वैश्विक झटके, सभी को नजरअंदाज कर दिया गया।

साय बोले- ऐतिहासिक बजट

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विकसित और सुनहरे भारत की नींव रखने वाला ऐतिहासिक

बजट बताया। उन्होंने कहा, यह बजट आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति के तीन प्रमुख कर्तव्यों को केंद्र में रखता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

देश को विकसित करने वाला बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए केंद्रीय बजट पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी

चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्ट विजन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मजबूत वित्तीय क्रियान्वयन के कारण यह बजट विकसित भारत के रोडमैप को मजबूती देने वाला है। निर्मला सीतारमण देश की नारी शक्ति की प्रतीक हैं, जिन्होंने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर इतिहास रच दिया है।

जनविरोधी नीतियों का दस्तावेज

छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने केंद्रीय बजट 2026 को पूरी तरह से

दिशाहीन और जनविरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल सत्ता को सुरक्षित रखने का एक माध्यम है, जिसमें देश के किसान, युवा और मध्यम वर्ग के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया है। डॉ. महंत ने कहा कि बजट में एमएसपी की कानूनी गारंटी पर चुप्पी साधना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है।

घोर निराशाजनक बजट

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यह बजट शेखचिल्ली का शोरबा है। शेखी बघारते रहे कि

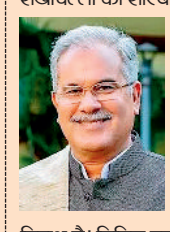

विश्व में फलां नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई, विश्व गुरु हो गए, पर बजट ने कलई खोल कर रख दी। श्री बघेल ने कहा, आम जनता के लिए घोर निराशाजनक बजट है। मोदी सरकार के बजट से देश का हर वर्ग निराश है। मिडिल क्लास, लोअर मिडल क्लास, गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है।

हरिभूमि के लिए ...

केंद्रीय बजट पर देशभर के अलग अलग विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए

4 **प्रो.ओमप्रकाश व्यास** डायरेक्टर, ट्रिपलआईटी, रायपुर — पहला बजट जो एआई और आईटी को समर्पित

4 **प्रो.ए के गुप्ता** आईआईएम अहमदाबाद — पशु चिकित्सक की व्यवस्था सार्थक निर्णय

5 **-प्रो. आर एस मीना** वाणिज्य संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी — चुनौती जमीनी स्तर पर समय पर क्रियान्वयन

6 **जवाहर सुरिसेट्टी** प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक, कुलपति, रूंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनीवर्सिटी — परिणाम आधारित रोजगार पर ध्यान

7 **मोहिनी मोहन मिश्र** अखिल भारतीय महामंत्री भारतीय किसान संघ — किसान हितैषी मंशा पर खरा नहीं उतरा बजट

8 **रविन्द्र के. ब्रम्हे** प्रोफेसर अर्थशास्त्र पं. रविवि, रायपुर — विकास के लिए मजबूत आधार का निर्माण

क्या मीम्स बनाने वालों को बजट समझ आया?

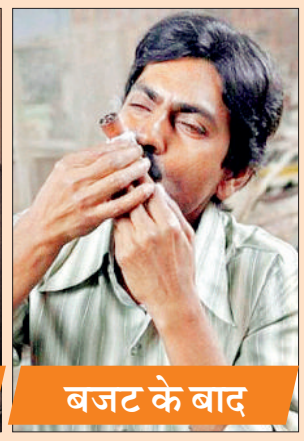

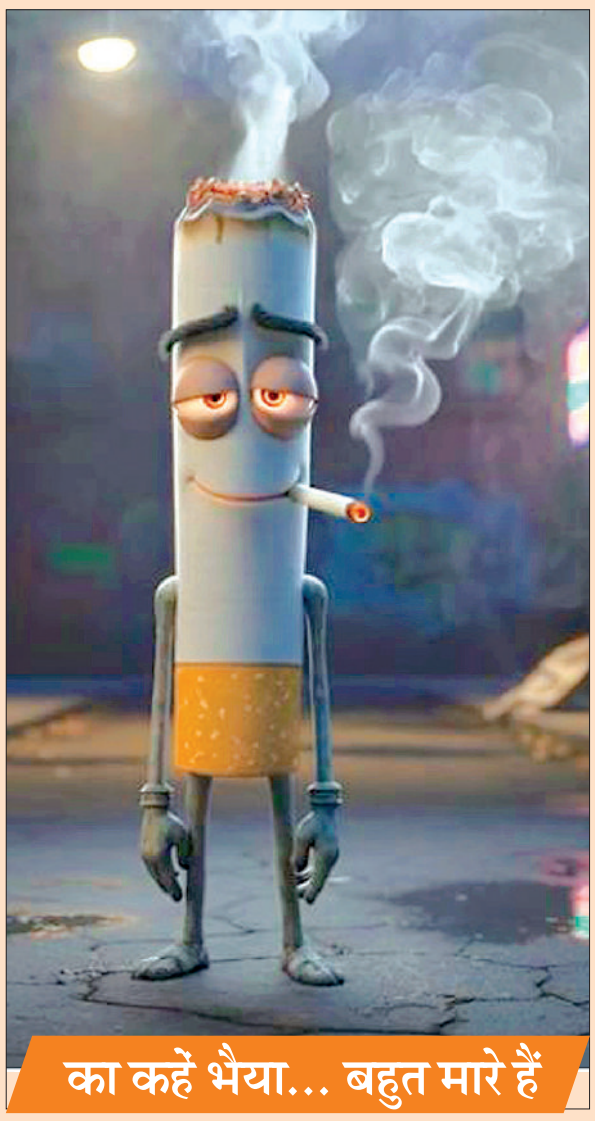

वैसे तो हर बजट पर मीम्स बनते हैं। पर, इस बार मीम्स की बाढ़ नहीं आई क्योंकि, बजट तत्काल प्रभाव देने वाला नहीं है। वह दूरगामी प्रभाव का बजट है। इसलिए, मीम्स कम्युनिटी को बजट जल्दी और ठीक से समझ नहीं आया। यानि, हमारी वित्त मंत्री मीम्स वालों की तीखी प्रतिक्रियाओं से फिलहाल बच गईं। पर, जितना भी बजट समझ आया, इन मीम्स वालों ने उसका अपने अंदाज में आनंद लिया। आप भी लीजिएगा।

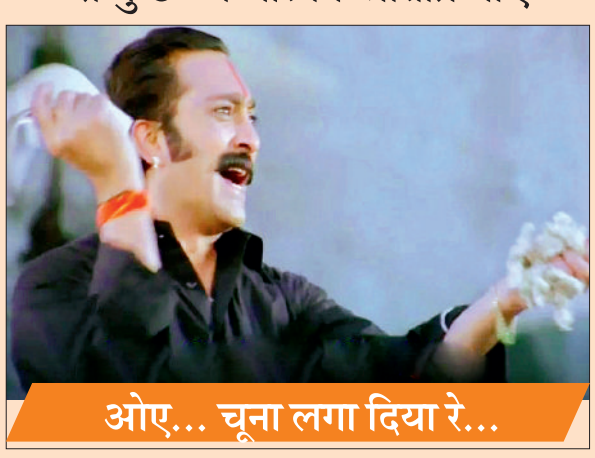

बजट के बाद बीड़ीबाजों की हालत में भी परिवर्तन दिखाई दिया

बजट से पहले

बजट के बाद

ये... ले और चाहिए तो बता देना बहुत माल है... अपने पास....

अब तो पैसा ही पैसा है भैया

सिगरेट पर 40% जीएसटी

का कहें भैया... बहुत मारे हैं

मैं तो टैक्स लूंगी, मेरा थैला तो भर गया, अब तुम जानो भैया

अब तो बल्ले-बल्ले आएगा ही आएगा

बजट-2026 पर मीम्स के माध्यम से कुछ व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाएं

ओए... चूना लगा दिया रे...

सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री सीतारमण का प्रतीकात्मक मीम्स दिनभर वायरल होता रहा। लोगों ने देखा और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दीं कहा- दीदी कह रही हैं लो अब आप जानो

आज पूरे दिन निर्मला ताई ही चर्चा में रहीं हैं क्यों?

बल्ले-बल्ले

यही तो...

ज्यादा भौंक रहे हो,बताऊं क्या....

ये मीम्स भी खूब वायरल हुआ। कुत्तों का झुंड भौंकने लगा तो फायरिंग कर चुप करा दिया

बजट से किस पर क्या असर होगा

चांदी में निवेश करने वाले | सोने में निवेश करने वाले

निवेशकों पर बजट का असर

दैनिक कारोबारियों का हाल भी कुछ इस तरह बयां किया गया

लंबे समय तक निवेश करने वालों की हालत इस तरह दिखी

उद्योगपति मुकेश अंबानी बजट पर शर्माए, निर्मला बोली-ठीक

कवियों की नजर में बजट

विकसित भारत के लक्ष्य की बात

नीतेश व्यास
भोपाल

विकसित भारत के
लक्ष्य की बात।

2026 के बजट में
सरकार की सौगात।

आत्मनिर्भर भारत की
संकल्पित चाह।

राष्ट्रीय फाइबर
योजना से बनेगी राह।

कैंसर जैसी दुर्लभ
बीमारियों से जल्द मिले
आराम।

नए बजट में सरकार
ने सस्ते किए दवाओं
के दाम।

इलेक्ट्रिकल व्हीकल
सोलर पैनल ग्रीन
एनर्जी को मिला दम।

ऐसे उपकरणों के
उत्पादन बढ़े इसलिए
हुई ड्यूटी कम।

महात्मा गांधी ग्राम
स्वराज शुरू करने का
प्रस्ताव।

खादी, हथकरघा,
हस्तशिल्प कला की
मजबूती में दिखेगा
प्रभाव।

न्यूक्लियर पावर
प्रोजेक्ट्स में भी
दिखेगी ब्यूटी।

आयातित उपकरणों
पर नहीं लगी कस्टम
ड्यूटी।

बजट न डराता है, न हंसाता है

डॉ.संदीप शर्मा
धार

*बजट ऐसा आया है कि न टैक्स पूरी तरह डराता है
न पूरी तरह हंसाता है
मध्यम वर्ग की आदत के अनुसार संयम में
खुश रहना सिखाता है
फिर जेब हल्की होने की तैयारी है
पर हां - इरादे बहुत भारी हैं
पीड़ा पर कर का भार नहीं है
कम यह भी उपहार नहीं है
सस्ते रेशम, जूट की बात
राहें कठिन, पर सस्ते बूट की सौगात
यह नहीं कह सकते कि विकास का मौका नहीं है
सपने बढ़े हैं इरादों में धोखा नहीं है*

बजट में खास

कॉरपोरेट कर में न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) घटाकर 14%

होटल में रहने व ठहरने पर टीडीएस अब कुल व्यय राशि का सिर्फ 2%

भूमि अधिग्रहण से प्राप्त आय पर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को विशिष्ट छूट प्रदान की जाएगी

वायुसेना के आयातित इंजनों सहित एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट के पार्टों पर सीमा शुल्क शून्य किया

चबाने वाला तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू कर 25% से बढ़कर 60%

मिश्रित कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) में प्रयुक्त बायोगैस/कम्प्रेस्ड बायोगैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट

क्रिप्टो करंसी के संबंध में गलत विवरण देने पर अर्थदंड प्रतिदिन 200 रुपए, विवरण ठीक न करने पर 50,000

रिटर्न अपडेट में एक्स्ट्रा आय बताने पर दंड नहीं लगाए जाने का प्रस्ताव

विवरण प्रस्तुत करने में भूल पर 7 साल के बजाए 2 वर्ष की सजा

- वित्तीय लेन-देन या रिपोर्ट किए जाने योग्य खाते के लिए विवरण प्रस्तुत करने में चूक के लिए अर्थदंड को अधिकतम सीमा के अधीन चूक के प्रत्येक दिन के लिए प्रभारित शुल्क में बदलने का प्रस्ताव है।
- लेखा और दस्तावेज प्रस्तुत करने, और नकद में किए गए भुगतान के लिए कटौतीकर्ता से टीडीएस का भुगतान सुनिश्चित करने की अपेक्षा को पूरी तरह अपराध से बाहर करने का प्रस्ताव है।
- सभी अभियोजनों को युक्तिसंगत करते हुए सश्रम कारावास से बदल कर साधारण कारावास किया जाएगा।
- किसी अपराध (बार-बार के अपराध को छोड़कर) के लिए अधिकतम अधिकतम दंड को 7 वर्ष से कम करके 2 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- ऐसे मामलों में जहां वर्तमान में अधिकतम दंड दो वर्ष है, वहां दंड को जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना तथा न्यूनतम कारावास की सीमा से रहित करते हुए कम करके 06 माह कर दिया गया है।
- यह भी प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम 2025 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन बचाई गई कर की राशि के आधार पर होगा और दंड अपराध की गंभीरता के अनुपात में होगा। ऐसे मामलों में कारावास के अधिकतम दंड की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है और अनिवार्य जुर्माने की अपेक्षा को शिथिल करके वैकल्पिक बना दिया गया है।
- यह भी प्रस्ताव है कि गौण अपराध के लिए दंड के रूप में केवल जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।

हर साल नया अंदाज...

साल 2019 | साल 2020 | साल 2021 | साल 2022

साल 2023 | 2024 अंतरिम | साल 2024 | साल 2025

साल 2026

आम आदमी छात्र और बुजुर्गों को वित्त मंत्री ने दिए ये खास तोहफे

इनकम टैक्स स्लैब जस के तस, थोड़ी फीस से 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न

मध्यमवर्गीय लोगों के लिए टैक्स भरने की प्रक्रियाएं हुई सरल

विदेश पढ़ाई खर्च पर टीसीएस घटाकर 2% किया

नई और पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं

आम बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई और पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की आय ही आयकर से मुक्त रहेगी। हालांकि, आयकर अधिनियम के सेक्शन 87ए के तहत आप 5 लाख तक की आय पर कर बचा सकते हैं। वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 4 लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं देना होगा। इसमें आयकर अधिनियम के सेक्शन 87ए के तहत वेतन प्राप्त करने वालों को 12.75 लाख रुपए तक की आय पर और अन्य 12 लाख तक की आय पर कर छूट पा सकते हैं।

टैक्स को लेकर ये बड़े बदलाव

- **1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून:** केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को बदलकर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें टैक्स रेट्स या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, इसके जरिए सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी।
- **विदेश यात्रा करना हुआ सस्ता:** बजट में आम आदमी का विदेश घूमना हुआ सस्ता विदेश यात्रा करने वालों के लिए ओवरसीज टूर पैकेज पर टीसीएस अब सिर्फ 2% होगा, जो पहले 5% और कुछ मामलों में 20% तक था। इससे घूमने-फिरने का खर्च तुरंत बढ़ने से बचेगा।
- **31 मार्च तक फाइल कर सकेंगे रिवाइज्ड रिटर्न** इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) में सुधार करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब मामूली फीस देकर 31 दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जा सकेगा।

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026-25 में इनकम टैक्स को लेकर किसी तरह की राहत नहीं दी है। बजट में इनकम टैक्स को लेकर को कोई बड़ी घाोषणा नहीं हुई है। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च की गई है। वहीं, विदेश रुपए भेजने पर अब 5% के बदले 2% टैक्स लगेगा। कर विशेषज्ञों के अनुसार सरकार ने पिछले बजट में ही न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स छूट को 7 लाख बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया था। ऐसे में इस साल बदलाव होने की संभावना न के बराबर ही थी। हालांकि, बजट 2026 में आम आदमी, मध्यमवर्गीय परिवारों, छात्रों और बुजुर्गों के लिए कई अहम राहत भरे कदम उठाए गए हैं। बजट में इन पर टैक्स का बोझ कम, आसान नियम और सुरक्षित, बचत के लिए नियम लाए हैं। सरकार ने इसे 'परिवारों की समृद्धि से राष्ट्र की मजबूती' के लक्ष्य से जोड़ा है। अब विदेश से यात्रा के दौरान एक लैपटॉप को पर्सनल सामान के साथ लाने पर स्पष्ट नियम तय कर दिए गए हैं। साथ ही अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए कस्टम डिक्लेरेशन और ड्यूटी पेमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिससे एयरपोर्ट पर लगने वाला समय और तनाव दोनों कम होंगे।

छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए आसान मौका

- विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों और उनके परिवारों के लिए बजट राहत लेकर आया है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्चों के लिए भेजी जाने वाली राशि पर टीसीएस घटाकर 2% कर दिया गया है, जो पहले 5% होता था। इससे छात्रों पर शुरुआती वित्तीय बोझ कम होगा, एजुकेशन लोन पर निर्भरता घटेगी और इंपोर्टेड स्टडी मटेरियल या पार्सल की क्लियरेंस भी तेज होगी।

टीडीएस की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड

- छोटे करदाताओं के लिए लोअर या निल टीडीएस सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड होगी। अब अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- स्वास्थ्य के मोर्चे पर बड़ी राहत देते हुए 17 कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म की गई है। वहीं 7 और दुर्लभ बीमारियों के इलाज से जुड़े दवाइयों और विशेष भोजन को भी ड्यूटी-फ्री किया गया है। यह छूट बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।

इन चीजों को समझिए

पुरानी में 2.5 लाख और नए में 12 लाख रुपए तक की आयकर छूट

सवाल 1: पुरानी और नई टैक्स रिजीम में क्या अंतर है?
जवाब: नए टैक्स रिजीम में 4 लाख रुपए तक की कमाई आय कर मुक्त रहती है, लेकिन इसमें टैक्स डिडक्शन नहीं मिलते हैं। वहीं, अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।

सवाल 2: पुरानी टैक्स रिजीम में किस तरह की छूट मिलती है?
जवाब: अगर आप ईपीएफ, पीपीएफ और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश करते हैं। तो आपकी कुल कर योग्य आय में से ये आय कम हो जाएगी। वहीं, मेडिकल पॉलिसी पर किए गए खर्च, होम लोन पर चुकाए गए ब्याज और नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश किए गए रुपए भी आपकी कर योग्य आय से घट जाते हैं।

सवाल 3: पुरानी टैक्स रिजीम किन लोगों के लिए बेहतर है?
जवाब: अगर आप निवेश और टैक्स छूट का फायदा लेना चाहते हैं, तो पुरानी टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। वहीं अगर आप कम टैक्स रेट और टैक्स डिडक्शन के झंझटों से बचना चाहते हैं तो नई टैक्स रिजीम आपके लिए सही हो सकती है।

टीडीएस के लिए अब आवेदन नहीं

- **टीडीएस न कटवाने के लिए आवेदन की जरूरत नहीं:** टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) नहीं कटवाने के लिए अलग से आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। नियमों के अनुसार अब अगर आप पर इनकम टैक्स नहीं बनता है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अभी इसके लिए फॉर्म 15जी (60 साल से कम वालों के लिए) या फॉर्म 15एच (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) जमा करना होता था।
- **फ्यूचर-ऑप्शंस ट्रेडिंग करना महंगा:** सरकार ने फ्यूचर ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया है। ऑप्शंस पर भी एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% किया गया है। इसे ट्रेडिंग करना महंगा हो जाएगा।

अत्यधिक सट्टेबाजी रोकने के लिए वित्त मंत्री ने सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ाया

शेयर बाजार के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एसटीटी बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया

निफ्टी 25500 के नीचे गया और बाद में 25800 के ऊपर क्लोज हुआ

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

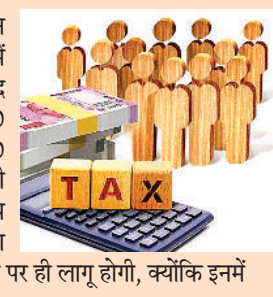

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान जैसे ही शेयर बाजार के फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एसटीटी टैक्स को बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद ही मार्केट में गिरावट हावी हो गई। इंट्रा में निफ्टी 25500 के नीचे चला गया और उतार-चढ़ाव के बाद 25800 के ऊपर क्लोज हुआ। वित्त मंत्री ने बताया कि एसटीटी में बढ़ोतरी मामूली है और इसका एकमात्र उद्देश्य अत्यधिक सट्टेबाजी को रोकना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसटीटी में वृद्धि केवल वायदा और विकल्प सौदों पर ही लागू होगी, क्योंकि इनमें अत्यधिक सट्टेबाजी और जोखिम शामिल है।

क्या होता है एसटीटी?

एसटीटी (सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स) एक प्रकार का टैक्स है जो शेयर बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री पर लगता है। शेयर, डेरिवेटिव्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदते या बेचते समय यह टैक्स लागू होता है। इस टैक्स को सरकार ने साल 2004 में शुरू किया था ताकि शेयर बाजार में सट्टेबाजी कम हो और सरकार को टैक्स से कमाई हो सके। फ्यूचर सेगमेंट में एसटीटी को पहले के 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। वहीं, ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है, जो कि पहले 0.10 फीसदी था।

करों से 44,04,086 करोड़ की आय

वर्ष 2026-27 में सरकार को टैक्स से कुल 44,04,086 करोड़ की आय होने का अनुमान है। इसमें इनकम टैक्स से 14,66,000 करोड़, कंपनियों पर लगने वाले टैक्स से 12,31,000 करोड़, जीएसटी से 10,19,020 करोड़, एक्साइज ड्यूटी से 3,88,910 करोड़ और कस्टम ड्यूटी से 2,71,200 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि जीडीपी की तुलना में टैक्स रेवेन्यू घटने की आशंका है। 2026-27 में 11.2% रहने का अनुमान है।

लागत कम कर उत्पादन बढ़ाने पर जोर

नवकरणीय और नाभिकीय उर्जा विमान के इंजन, पुर्जों पर 0 टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनपुट लागत कम करने, घरेलू विनिर्माण पर बल देने तथा निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखत मदों पर सीमा-शुल्क डयूटी कम किए जाने का प्रस्ताव रखा है। महत्वपूर्ण खनिज मोनाजाइट पर मूल सीमा शुल्क ड्यूटी की दर 2.5% से घटाकर शून्य कर दी गई है। एअरक्रॉफ्टों और एअरक्रॉफ्टों के विनिर्माण के लिए एअरक्रॉफ्ट के इंजनों सहित उसके घटक या पार्ट पर सीमा शुल्क पूरी तरह से शून्य किए जाने का प्रस्ताव है।

सौर ग्लास पर सीमा शुल्क शून्य

नवकरणीय ऊर्जा के तहत सौर ग्लास के विनिर्माण में उपयोग हेतु सोडियम एंटीमोनेट 7.5% से कम करके शून्य, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की बैटरियों के लिए लिथियम ऑयन सेलों के विनिर्माण में उपयोग हेतु वस्तुएं शून्य कर पर उपलब्ध होंगी। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित वस्तुएं पर सीमा शुल्क ड्यटी शून्य कर दी गई है।

आम बजट पर विशेषज्ञों का नजरिया

शिक्षा पर समग्र दृष्टिकोण, तकनीकी कौशल के साथ युवाओं को रोजगार

डॉ. भूपेंद्र सुल्लेरे
शिक्षाविद
भोपाल

केंद्रीय बजट में शिक्षा को मानव पूंजी का मूल आधार मानते हुए स्कूली, तकनीकी और उच्च शिक्षा दोनों में निवेश और सुधार पर बल दिया गया है। बजट में सरकारी स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब तथा डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे कदमों से सीखने की गुणवत्ता और तकनीकी कौशल को बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवा आधुनिक रोजगार के अवसरों के लिए तैयार होंगे। साथ ही, हर जिले में लड़कियों के होस्टल और नए डिज़ाइन/ क्रिएटिव संस्थान जैसे उच्च शिक्षा संवर्धन प्रस्ताव हैं, जो लिंग समानता और समावेशी शिक्षा को मजबूत करेंगे। बजट में नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप, उन्नत तकनीकी पाठ्यक्रम, शोध-उन्मुख केंद्रों और विद्यालय-विश्वविद्यालय लिंकिंग को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है, जिससे भारत वैश्विक शिक्षा-केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एजुकेशन टू इम्प्लॉयमेंट कमेटी जैसे संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव रखा है, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच पुल मजबूत होगा।

स्थिर नीति, संतुलित आर्थिक संकेत और राजकोषीय अनुशासन से विश्वास बढ़ा

प्रो. हिमांशु राय
निदेशक
आईआईएम, इंदौर

केंद्रीय बजट 2026 की एक उल्लेखनीय विशेषता इसकी नीतिगत स्थिरता और पूर्वानुमेय आर्थिक दिशा है। सरकार ने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि विकास को कर्ज-आधारित विस्तार के बजाए संतुलित संसाधन प्रबंधन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। यह दृष्टिकोण सार्वजनिक वित्त की विश्वसनीयता को मजबूत करता है और दीर्घकालिक आर्थिक योजना के लिए आवश्यक आधार तैयार करता है। पूंजीगत व्यय को रूपए 12.2 लाख करोड़ तक बनाए रखना यह दर्शाता है कि सरकार अल्पकालिक लोकप्रिय निर्णयों के बजाय आर्थिक क्षमता के निर्माण पर ध्यान दे रही है। बेहतर अवसंरचना और स्थिर नीतिगत माहौल का प्रत्यक्ष लाभ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिल सकता है, जो कम लागत, बेहतर संपर्कऔर अधिक भरोसेमंद मांग वातावरण में विस्तार करने में सक्षम होंगे। नीति निरंतरता से इन उद्यमों के लिए निवेश और उत्पादन संबंधी निर्णय लेना सरल होता है। इस व्यापक आर्थिक ढांचे में शिक्षा को एक केंद्रीय स्तंभ के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा के लिए 1.28 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन दर्शाता है कि सरकार मानव पूंजी में प्राथमिकता दे रही है।

हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, मेडिकल में बढ़ी सुविधा
तीन आयुर्वेदिक एम्स, पांच चिकित्सकीय पर्यटन केन्द्र

बजट 2026-27 में शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें 55,727 लाख करोड़ रुपये उच्च शिक्षा विभाग और 83,562 लाख करोड़ रुपये स्कूल और साक्षरता विभाग के लिए हैं। इस बार शिक्षा के लिए आवंटित बजट पिछले वर्ष की तुलना में 8.27 फीसदी अधिक रहा। सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए बजटीय प्रावधान करते हुए भविष्य की तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कौशल विकास और मेडिकल शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। साथ ही, देश के हर जिले में महिला छात्रावास खोलने की भी घोषणा की गई है। बजट में टियर-2 और टियर-3 कस्बों में कॉर्पोरेट मित्र बनाने की भी घोषणा की गई है, जिससे पेशेवर संस्थानों को सुविधा और प्रशिक्षण मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

शिक्षा बजट 8.27% बढ़कर हुआ 1.39 लाख करोड़ रुपये

पिछले वर्ष से 8.27% अधिक आवंटन

2026-27 के लिए शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं 2025-26 के बजट में शिक्षा मंत्रालय के लिए कुल 1,28,650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

दवा उत्पादन के लिए दस हजार करोड़ किए जाएंगे खर्च

बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत के दवा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए अगले 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में हम दुर्लभ दवाओं के लिए विदेशों पर निर्भर है लेकिन इस पहल से अब भारत में ही आधुनिक दवाओं का निर्माण होगा और भारत दुनिया को दवाई सप्लाई कर सकेगा। देश में ऐसे पहले से ही 7 संस्थान मौजूद हैं और इन्हें भी आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। जिला अस्पताल आधुनिक तकनीक से लैस होंगे तथा इमरजेंसी वार्ड की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी।

क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा

वित्त मंत्री ने दवाओं के साथ उसके विशेषज्ञों की भी जरूरत पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पूरे देश में 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके जरिए थेरेपी और दवाओं की जांच जल्दी से हो जाएगी। ऐसे में देश में तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोले जाने की घोषणा हुई है।

स्कूलों व कॉलेजों में 'कन्टेंट क्रिएटर लैब' बनेंगी

सरकार ने माना है कि भविष्य 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'डिजिटल कंटेंट' का है। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कन्टेंट क्रिएटर लैब' बनाने का फैसला लिया गया है। युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए 'एआई एप्लीकेशन' पर आधारित विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जिससे देश की युवा शक्ति डिजिटल युग के लिए पूरी तरह तैयार हो सके।

गर्ल्स हॉस्टल और जिला अस्पतालों का कायाकल्प

महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश के हर जिले में एक 'गर्ल्स हॉस्टल' बनाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला अस्पतालों की क्षमता में 50% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। लघु उद्योगों की मदद के लिए सरकार एक अनूठी योजना लेकर आई । सीए, सीएस और सीएमए जैसे संस्थान अब शॉर्ट टर्म कोर्स तैयार करेंगे, जिससे देश में 'कॉर्पोरेट मित्र' तैयार होंगे। ये एक्सपर्ट्स विशेष रूप से छोटे शहरों के व्यापारियों और उद्योगों को प्रोफेशनल मदद देंगे। आईआईएम की मदद से 10 हजार टूरिस्ट गाइड्स तैयार किए जाएंगे।

बेटियों की पढ़ाई में अब नहीं आएगी कोई रुकावट

अक्सर देखा जाता है कि गांव या छोटे शहर की लड़कियों को बड़े कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन वहां रहने का इंतजाम करना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। बजट में लिया गया यह फैसला लड़कियों को कॉलेज तक पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होगा। जब हर जिले में अपना एक हॉस्टल होगा, तो मां-बाप भी बिना किसी डर के अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए भेज सकेंगे। इससे न केवल पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या कम होगी, बल्कि लड़कियां खुद को ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगी। यह कदम महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की तरह देखा जा रहा है।

7 दवाओं से कस्टम ड्यूटी खत्म

सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके अलावा, कई दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे उन परिवारों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी जो इलाज के लिए महंगी विदेशी दवाओं पर निर्भर हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत के दवा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए अगले 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में हम दुर्लभ दवाओं के लिए विदेशों पर निर्भर है लेकिन इस पहल से अब भारत में ही आधुनिक दवाओं का निर्माण होगा और भारत दुनिया को दवाई सप्लाई कर सकेगा। देश में ऐसे पहले से ही 7 संस्थान मौजूद हैं और इन्हें भी आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।

युवाओं पर फोकस

युवाओं के सपनों को पांव रफ्तार से दौड़ेगा देश

सरकार ने आम बजट में सबसे बड़ी धुरी 'युवा शक्ति' और 'आधुनिक तकनीक' को बनाया है। सरकार ने इस बजट के जरिए न केवल शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की कोशिश की है, बल्कि रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए बायो-फार्मा और एआई जैसे उभरते क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार युवाओं को 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब क्रिएटर' बनाना चाहती है। बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास के लिए भी विशेष रोडमैप तैयार किया गया है जो रोजगार व व्यापार में सहायक बनेंगे। बायो-फार्मा व एआई क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

बायो-फार्मा और मेडिकल सेक्टर में आएगी क्रांति

सरकार ने भारत को दुनिया का मेडिकल हब बनाने के लिए सरकार ने 'बायो फार्मा शक्ति' योजना का ऐलान किया है। अगले पांच सालों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत तीन नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च खुलेंगे। वहीं 7 पुराने संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, पशुपालन के क्षेत्र में भी 20 हजार नए वेटरनरी प्रोफेशनल तैयार करने के लिए विशेष कॉलेज खोले जाएंगे।

बुजुर्गों को रेल यात्रा में नहीं मिली छूट बाकी सब यथावत

भारतीय रेलवे ने कोरोना महामारी के बाद से बुजुर्गों को सफर में मिलने वाली रियायत खत्म कर दी थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वित्त मंत्री अपने पिटारे से यह तोहफा जरूर देंगी लेकिन ऐसी किसी भी प्रकार की घोषणा इस बजट में नहीं की गई जिससे बुजुर्गों को निराशा हाथ लगी। वहीं बुजुर्गों के लिए इनकम टैक्स की मौजूदा छूट सीमा भी पूर्व जैसे ही यानी 60 से 79 साल की उम्र वालों के लिए टैक्स छूट 3 लाख रुपये और 80 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपये ही रहेगी।

महिलाओं को मिला शी-मार्ट का तोहफा

ग्रामीण महिलाओं के लिए स्व-सहायता उपक्रम शी-मार्ट का ऐलान

भारत- विस्तार एआई टूल्स से कृषि उत्पादन में होगी सहायता

पीएम दिव्यांशा केंद्रों को बनाया जाएगा मजबूत

रोजगार के क्षेत्र में घोषणा

- 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' योजना
- खादी हथकरघा क्षेत्र को दिया जाएगा बढ़ावा
- निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण को मजबूती देने का लक्ष्य

केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए एक नई पहल शी-मार्ट की घोषणा की है। यह योजना महिलाओं के व्यवसाय और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है। ताकि महिलाओं को और अधिक आर्थिक अवसर मिल सकें। शी-मार्ट्स समुदाय-संचालित रिटेल आउटलेट होंगे जहां स्व सहायता समूह की महिलाएं खुद का कारोबार चला सकेंगी।

महिलाओं की वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपए हो

वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की वह महिला सदस्य होती है जिसकी वार्षिक घरेलू आय कम से कम एक लाख रुपये हो। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, अब तक दो करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और लक्ष्य 2027 तक तीन करोड़ महिला एसएचजी सदस्यों की वार्षिक आय को एक लाख रुपये तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उधार पर निर्भर रहकर काम करने की बजाय स्वयं के व्यवसाय की मालिक बनने में सहायता देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता (लोन) भी उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि वे अपने व्यापार को मजबूत कर सकें। बजट 2026 में महिलाओं के लिए यह नई पहल उनके आर्थिक सशक्तिकरण, उद्यमिता और स्वयं-का व्यवसाय चलाने वाली क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कदम है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इसे स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के लिए 'उद्यमों के मालिक' बनने की दिशा में "अगला कदम" बताया।

आम बजट पर आम नजरिया

पहला बजट जो एआई और आईटी को समर्पित

बजट एआई और आईटी को भारत के भविष्य के विकास की प्रमुख शक्ति के रूप में रेखांकित करता है। एआई समेत उभरती तकनीकों के रोजगार पर प्रभाव और कौशल आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए एक विशेष समिति के गठन का सुझाव दिया गया है, जो कौशल विकास और रोजगार तैयारियों को दिशा देगी। सरकारी सेवाओं में एआई आधारित समाधानों के उपयोग, डिजिटल अवसंरचना के विस्तार तथा राज्य-स्तरीय डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से सेवाओं को सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को भी प्रमुखता दी गई है, जो चिप डिजाइन तथा निर्माण क्षमता को मजबूत कर इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई-आधारित उपकरणों के लिए अवसंरचना तैयार करेगा। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण कार्यक्रमों के लिए 8,000 करोड़ का आवंटन भी बढ़ाया गया है, जो घरेलू उर्ध्वाधर क्षमता के निर्माण में सहायक होगा।

इसके अतिरिक्त मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का कुल बजटीय आवंटन बढ़कर 21,633 करोड़ किए जाने से एआई, डेटा प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं केंद्रित परियोजनाओं को बल मिलेगा। इंडिया एआई मिशन को विस्तारित करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ का विशेष भाग निर्धारित किया गया है। डिजिटल कौशल कार्यक्रम और कंटेंट निर्माता लैब्स (15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में) की घोषणा की गई है। इससे एआई-आईटी आधारित रोजगारों और नवोन्मेषी कौशल के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। भारत की वैश्विक डिजिटल सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक हिस्सेदारी को 2047 तक 10% तक पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी।

- **प्रो.ओमप्रकाश व्यास**, डायरेक्टर, ट्रिपलआईटी, रायपुर

पशु चिकित्सक की व्यवस्था सार्थक निर्णय

पशुधन की रक्षा के लिए पशु चिकित्सक की व्यवस्था को सुलभ बनाना बहुत सार्थक निर्णय है। महिला लघु उद्यमी के सहज बाजार लगाना बहुत ही अच्छा कदम है। मछुआरों की तरफ भी ध्यान दिया गया, ये सराहनीय है। कृषि क्षेत्र में किसानों को और नए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद थी। उद्यमियों को निर्यात के लिए थोड़ा अधिक प्रोत्साहन मिलना था। डीबीटी में कुछ परिवर्तन हो और केवल गरीबों को ही किसान सम्मान राशि प्रदान किया जाना था। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में शोध के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद थी। यह पूरी हुई। एआई और आईटी के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया है। बहनों में उद्यमिता बढ़ाने और भूमि के स्वास्थ्य सुधार के लिए थोड़े अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त नवचारों पर खर्च बढ़ाने के लिए उद्योग को नई छूट की उम्मीद एक वर्ग को थी। कुछ सीमा तक यह भी पूरी हुई है।

- **प्रो.एके गुप्ता**, आईआईएम, अहमदाबाद (पद्म पुरस्कार प्राप्त, गुजरात ग्रासरूट्स इनोवेशन ऑग्मेंटेशन नेटवर्क के संस्थापक)

बजट में खास

शिक्षा के क्षेत्र को सौगात

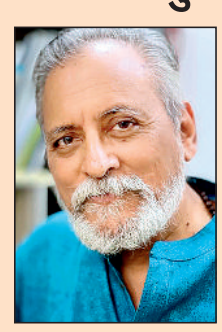

- 01 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
- 05 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापना की घोषणा
- 04 टेलीस्कोप/खगोल विज्ञान सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी
- 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना
- 15000 माध्य. स्कूलों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना
- डिजिटल नॉलेज ग्रिड खोले जाएंगे
- हर जिले में छात्राओं के लिए होगी गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना

स्वास्थ्य क्षेत्र में ये नए संस्थान खोलने की घोषणा

- 05 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापना की घोषणा
- 02 नए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान खुलेंगे
- 03 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनेंगे
- 17 लाइफ सेविंग ड्रग्स पर कस्टम ड्यूटी खत्म
- 1,000 क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा
- 07 नए आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव
- 07 पहले से मौजूद संस्थान होंगे अपडेट
- 17 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी खत्म
- कैंसर व शुगर की दवाइयां होंगी सस्ती
- एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के नए संस्थान बनेंगे
- वेटनरी और पैरा-वेट कॉलेज/अस्पताल की स्थापना

बजट में खास

दिल्ली-वाराणसी समेत कुछ मार्गों पर दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 के साथ-साथ रेल बजट भी पेश किया है। इसमें एक ऐसी बड़ी घोषणा की गई है, जिससे रेलवे का सफर बिना रुकावट वाली तीव्र यात्रा बनने जा रही है। केंद्रीय बजट 2026 में हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का बनाने का ऐलान किया गया है। ये सात प्राइम रेल कोरिडोर्स होंगी जो सात रेल रूट्स को कनेक्ट करेंगी। इसके सबसे बड़ी बात ये होगी, कि ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होंगे.. जिन पर सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रेनें दौड़ेंगी। इससे इन शहरों के बीच रेल सफर की आम समय सीमा घट जाएगी।

7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर

लोगों की यात्रा आसान करने बनाया जा रहा है तेज रेल नेटवर्क

ये हैं सात कॉरिडोर

- मुंबई-पुणे-महाराष्ट्र के इन दो बड़े शहरों के बीच सफर अब बहुत तेज होगा
- पुणे-हैदराबाद-महाराष्ट्र और तेलंगाना को जोड़ेगा
- हैदराबाद-चेन्नई – दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करेगा
- हैदराबाद-बेंगलुरु – आईटी हब बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच तेज कनेक्शन
- चेन्नई-बेंगलुरु – तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच हाई-स्पीड लिंक
- दिल्ली-वाराणसी – राजधानी दिल्ली को उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी से जोड़ेगा। इससे पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा।
- वाराणसी-सिलीगुड़ी – पूर्वी भारत को मजबूत कनेक्टिविटी देगा, खासकर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए फायदेमंद

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में 7 नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। जो मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगे। ये कॉरिडोर भारत के प्रमुख शहरों को तेज और बेहतर तरीके से जोड़ेंगे। इससे यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री ने इन हाईस्पीड रेल मार्गों को 'ग्रोथ कनेक्टर्स' यानी विकास के जोड़ने वाले बताया है। ये पर्यावरण के अनुकूल होंगे और लंबी दूरी की यात्रा को तेज, सुरक्षित और कम कार्बन वाला बनाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) पर जोर देने का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि देश में तेज रेल नेटवर्क बढ़ाकर लोगों की यात्रा आसान हो। व्यापार तेज हो और रोजगार के मौके बढ़ें। फिलहाल मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अब इन 7 नए कॉरिडोर से भारत का रेल नेटवर्क और आधुनिक बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स देश को तेज विकास की राह पर ले जाएंगे। इससे शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। यह कदम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

सरकार सीप्लेन के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए देगी प्रोत्साहन

सीप्लेन वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव

विमानों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव

मोदी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए बड़े कदम

पूर्वोत्तर के छह राज्यों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने विशेष योजना

पर्यटन स्थलों के पास होगी इंटरप्रिटेशन सेंटर्स की स्थापना

पर्यटन स्थलों को मिलेंगी 4,000 ई-बसें

पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स के लिए विशेष कोर्स

15 पुरातात्विक स्थलों होंगे जीवंत तरीके से विकसित

बनाया जाएगा राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड

खेलो इंडिया प्रोग्राम को मिलेगी नई धार

कोच और सपोर्ट स्टाफ का सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से विकास

स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने और प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग।

यूनियन बजट 2026-27 में सरकार ने बढ़ाया रक्षा खर्च

रक्षा बजट में 1 लाख करोड़ का इजाफा

वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए ऐलान किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में युद्ध और रक्षा रणनीति की अहमियत और प्राथमिकता और बढ़ी है। जिसका असर हमें बजट में देखने को मिला। इस बजट में सरकार ने रक्षा खर्च बढ़ा दिया है। सरकार ने यूनियन बजट 2026-27 में रक्षा खर्च बढ़ा दिया है, इस सेक्टर के लिए 7,84,678 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

विमान और एयरो इंजन में इतना किया जाएगा खर्च

कैपिटल खर्च की बात करें तो विमान और एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपये और नौसेना बेड़े के लिए 25,023 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। 2025-26 के लिए रक्षा बजट 6,81,210 करोड़ रुपये तय किया गया था, जिसमें कैपिटल खर्च 1,80,000 करोड़ रुपये था, जिसे बाद में संशोधित अनुमानों के चरण में 1,86,454 करोड़ रुपये कर दिया गया था। भाषण में सीतारमण ने रक्षा क्षेत्र की यूनिट्स द्वारा रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए इस्तेमाल होने वाले विमान पार्ट्स के निर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ करने की भी घोषणा की।

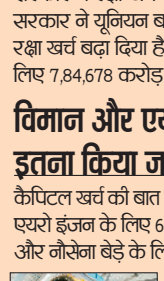

20 नए जलमार्गों का भी ऐलान

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में देश में 20 नए जलमार्गों का ऐलान किया है। इसमें दानकुनी से सूरत तक नया फ्रेट कॉरिडोर भी शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि कार्गो के पर्यावरण-अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में दानकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ने वाले नए समर्पित माल गलियारे स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्गों को चालू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से होगी। इसके अतिरिक्त, अंतर्देशीय जलमार्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाराणसी और पटना में एक जहाज मरम्मत इकोसिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। रेल और सड़क से जलमार्गों की ओर माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम शुरू करेगी। इसका लक्ष्य 2047 तक इंलैंड वॉटरवेज और कोस्टल शिपिंग की हिस्सेदारी को मौजूदा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करना है।

परमाणु परियोजनाओं के लिए कई चीजें ड्यूटी-फ्री

सितंबर 2035 तक कस्टम्स में रजिस्टर्ड सभी परमाणु परियोजनाओं के लिए न्यूक्लियर जनरेशन इक्विपमेंट, एब्जॉर्बर रॉड्स और प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स को ड्यूटी-फ्री कर दिया गया है।

एविएशन सेक्टर में रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयात किए जाने वाले एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इंजन और एमआरओ इनपुट्स पर भी कस्टम ड्यूटी हटाई गई है।

न्यूक्लियर और एविएशन सेक्टर को बड़ी राहत

बजट में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लंबी अवधि की स्पष्टता दी गई है। सितंबर 2035 तक कस्टम्स में रजिस्टर्ड सभी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए न्यूक्लियर जनरेशन इक्विपमेंट, एब्जॉर्बर रॉड्स और प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स पर कस्टम ड्यूटी शून्य कर दी गई है। एविएशन सेक्टर में रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आयात किए जाने वाले एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इंजन और **MRO** से जुड़े कच्चे माल पर भी ड्यूटी हटा दी गई है।

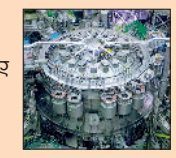

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा बुद्ध सर्किट

सीतारमण ने इस बार बजट में पर्यटन पर काफी फोकस रखा गया है और मोदी सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर के छह राज्यों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कॉरिडोर का ऐलान किया है। कॉरिडोर का नाम रखा गया है- बौद्ध सर्किट जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर योजना के तहत मंदिरों और मठों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे। सीतारमण ने कहा, 'सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए योजना शुरू करेगी ताकि मंदिरों और मठों का संरक्षण किया जा सके। सरकार पूर्वोत्तर के पांच राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों का विकास करेगी।

टूरिज्म के क्षेत्र में सरकार की बड़ी पहल

15 पुरातत्व स्थल, 20 टूरिस्ट साइट्स और इको-टूरिज्म को बढ़ावा

नार्थ ईस्ट के मंदिरों-मठों को बचाने पर खास जोर

इंटरप्रिटेशन सेंटर्स में इतिहास की जानकारी

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई इस योजना के तहत पर्यटन स्थलों के पास इंटरप्रिटेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी जहां उन जगहों के इतिहास और महत्व संबंधी जानकारियां दी जाएंगी।

पर्यटन में यह भी खास

वित्त मंत्री ने कहा, '20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों को ट्रेन करने के लिए एक पायलट योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 12 हफ्ते का स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा।' मोदी सरकार के टूरिज्म प्लान में भारत के पुरातात्विक स्थलों को बढ़ावा देना भी शामिल है। निर्मला सीतारमण के मुताबिक, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत तरीके से विकसित किया जाएगा।

अब मिशन मोड में बढ़ाया जाएगा खेलो इंडिया

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारी! स्टेडियम से साइंस लैब पर होगा सुधार

कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर

बजट में खेलों के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए। खेलो इंडिया को अब मिशन मोड में बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य अगले दशक में भारत के खेल ढांचे और खिलाड़ियों के विकास को नई रफ्तार देना है। इस पहल के तहत स्टेडियम और ट्रेनिंग सेंटर से लेकर स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी तक हर स्तर पर सुधार किया जाएगा, ताकि जमीनी स्तर से ही टैलेंट को पोषित किया जा सके। भारत की 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, यह मिशन ग्रासरूट से एलीट लेवल तक खिलाड़ियों और कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि यह मिशन इंटर-लिंकिंग तरीकों से एक इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम को आसान बनाएगा। खेलो इंडिया प्रोग्राम 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य टैलेंट (प्रतिभा) पहचानने के लिए अलग-अलग आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं करवाना था। 'स्पोर्ट्स सेक्टर रोजगार, स्किलिंग और नौकरी से मिलते मौके लोकसभा में अपने बजट भाषण के दौरान निर्मण सीतारमण ने कहा, 'स्पोर्ट्स सेक्टर रोजगार, स्किलिंग और नौकरी के कई मौके देता है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के जरिये खेल प्रतिभा का सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से बढ़ावा देने की जो शुरुआत हुई है, उसे आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलने के लिए एक खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखती हूं।'

मिलेंगी ये सुविधाएं

- ट्रेनिंग सेंटरों द्वारा समर्थित फाउंडेशनल, इंटरमीडिएट और एलीट स्तर वाले इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट पाथवे
- कोच और सपोर्ट स्टाफ का सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से विकास।
- स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन।
- स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने और प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रतियोगिताएं और लीग।
- ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट।

आम बजट पर आम नजरिया

चुनौती जमीनी स्तर पर समय पर क्रियान्वयन

-प्रो.आरएस मीना
वाणिज्य संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

केंद्रीय बजट 2026 ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी दीर्घकालिक क्षमता को लेकर आश्वस्त है, फिर भी अल्पकालिक आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं से बाधित है। परिवहन, रसद, ऊर्जा या शहरी विकास सहित अधिकतर क्षेत्र में अवसंरचना को एक बार फिर प्रमुखता दी गई है। यह तर्कसंगत है। सार्वजनिक निवेश न केवल अल्पकालिक रूप से रोजगार सृजित करता है, बल्कि दीर्घकालिक रूप से उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार करता है। हालांकि, असली परीक्षा क्रियान्वयन में होगी। भारत के पास महत्वाकांक्षी योजनाओं की कोई कमी नहीं है। चुनौती हमेशा से जमीनी स्तर पर समय पर क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण परिणाम प्राप्त करने की रही है। बजट इस बात की जागरूकता का संकेत देता है कि केवल विकास ही पर्याप्त नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में खर्च को बनाए रखने का स्पष्ट प्रयास किया गया है, विशेष रूप से ग्रामीण आजीविका, आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। मध्यम वर्ग, जिसे

अक्सर उपभोग और कराधान की रीढ़ कहा जाता है, शायद खुद को पूरी तरह से पुरस्कृत महसूस नहीं करे, लेकिन नवाचार और हरित परिवर्तन की दिशा में प्रयास बजट में दिख रहा है। घरेलू उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा और प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन भारत की वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की आकांक्षा के अनुरूप हैं। हालांकि, इन पहलों के साथ-साथ कौशल विकास, व्यापार करने में सुगमता और नियामक स्पष्टता में गहन सुधार भी आवश्यक हैं। इनके बिना, केवल प्रोत्साहनों से कंपनियों के एक छोटे से वर्ग को ही लाभ मिलने का जोखिम है। केंद्रीय बजट 2026 भारत की आर्थिक दिशा में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता है, लेकिन शायद यही इसका उद्देश्य है। यह एक विघटनकारी मार्ग के बजाय एक स्थिर, सुनियोजित मार्ग को सुदृढ़ करता है। कुछ लोगों को यह निराशाजनक लग सकता है। इस बजट की सफलता इसकी घोषणाओं पर कम और इसके कार्यान्वयन पर अधिक निर्भर करेगी।

कार्टूनिस्ट हरिओम की नजर में बजट

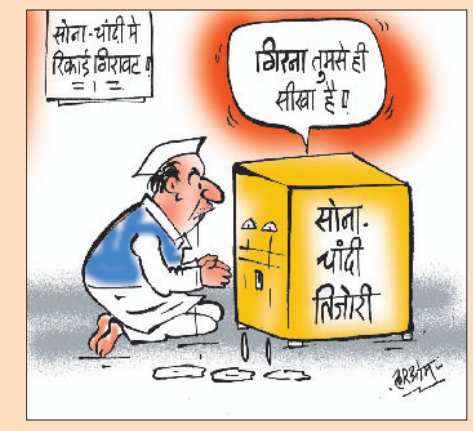

राजनाथ सिंह
केंद्रीय रक्षा मंत्री

जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह जनभावनाओं और जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यह बजट प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को सशक्त आधार देता है।

धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री

'विकसित भारत' का ठोस ब्लूप्रिंट

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा है कि 'विकसित भारत बजट' सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है। उनके मुताबिक यह बजट शिक्षा और रोजगार सृजन को नई रफ्तार देता है। साथ ही केंद्रीय बजट देश के विकास के अगले चरण के लिए एक साफ और मजबूत रोडमैप पेश करता है। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' बनाने की घोषणा का स्वागत किया।

जीतन राम मांझी
केंद्रीय मंत्री

बजट बहुत अच्छा

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा है कि एमएसएमई के माध्यम से भारत की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इस बजट में काफी प्रयास किया गया है, जो सराहनीय है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "मैं समझता हूं कि एमएसएमई के लिए ही ये बजट है, इसलिए क्योंकि ये एमएसएमई भारतीय आर्थिक व्यवस्था का ऋण है।

जेपी नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

देश की युवा शक्ति का बजट

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आम बजट को एक लोक-कल्याणकारी और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को नई दिशा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी एवं सर्वस्पर्शी है, जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। यह देश की युवा शक्ति का बजट है। इस ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत के बजट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता।

रामदास अठावले
आरपीआई
सांसद

बजट क्रांतिकारी, समाज के हर वर्ग को छूता है

आरपीआई सांसद रामदास अठावले ने केंद्रीय बजट को क्रांतिकारी बताते हुए कहा कि यह समाज के सभी वर्गों को संबोधित करता है और सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। अठावले ने बताया कि निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट क्रांतिकारी है क्योंकि यह समाज के हर वर्ग को छूता है। यह सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों प्रदान करेगा।

अगले 25 वर्षों के लिए 'रोडमैप' पेश करेगा बजट : गृहमंत्री शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बजट भारत को वैश्विक मंच पर पारंपरिक से लेकर नये दौर के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की रफ्तार को तेज करेगा। शाह ने कहा कि 'विनिर्माण से लेकर बुनियादी ढांचे तक, स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, खेल से लेकर तीर्थ स्थलों तक, विकसित भारत बजट एक ऐसा बजट है, जो हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं एवं किसानों के सपनों को सशक्त बनाता है, ताकि वे उन सपनों को साकार कर सकें।'

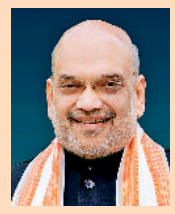

2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य

शाह ने कहा कि बजट राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के लक्ष्य को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि बजट 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की परिकल्पना और अगले 25 वर्षों के लिए 'रोडमैप' पेश करता है। उन्होंने कहा, 'वित्त वर्ष 2026-27 के इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। यह बजट न केवल हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए एक स्पष्ट खाका प्रस्तुत करता है, बल्कि इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक ठोस दृष्टिकोण भी प्रदान करता है, जो हर कदम पर इसका समर्थन करेगा।

किसानों और हथकरघा उद्योग को नया समर्थन

विकसित भारत बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का दृष्टिकोण है, जो विश्व के हर क्षेत्र में अग्रणी हो। गृह मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में योजना शुरू करने का एक ऐतिहासिक निर्णय बजट प्रस्ताव में लिया गया है। उन्होंने कहा, 'इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और बुनकरों, किसानों और हथकरघा उद्योग को नया समर्थन मिलेगा।' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तटीय क्षेत्रों में नारियल प्रोत्साहन योजना के माध्यम से तीन करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने, काजू और नारियल के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने तथा चंदन के संरक्षण का निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की समृद्धि और कृषि को एक लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

बदलेगी युवाओं-महिलाओं की तकदीर : सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को 'विकसित भारत' की परिकल्पना का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह महिलाओं, युवाओं और आम जनता पर केंद्रित है। उन्होंने अवसंरचना विकास के लिए 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन की सराहना की, जिसमें सात नए रेल गलियारे शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्रीय बजट आम जनता पर केंद्रित है और महिला-केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य 2047 तक "विकसित भारत" के मिशन को हासिल करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने 'विकसित भारत' का रोडमैप तैयार करते हुए आज केंद्रीय बजट पेश किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बजट दिशा-निर्देशों के मार्गदर्शन और देखरेख के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी इस बजट को पेश करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

विकसित भारत' के मिशन का प्रतीक

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बजट में सात रेल गलियारों के निर्माण सहित अवसंरचना विकास के लिए 12 लाख रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के 145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को दर्शाता है।

केरल के लिए कुछ नहीं

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट भाषण में केरल के लिए कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, जो निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि अभी हमने केवल भाषण सुना है, पूरा बजट दस्तावेज नहीं पढ़ा है, इसलिए हो सकता है कि आगे विवरण में कुछ बातें सामने आएं। लेकिन फिलहाल भाषण में जरूरी जानकारियों की कमी साफ नजर आती है।

शशि थरूर
कांग्रेस सांसद

टैक्स ब्यूएंसी बेहद कम

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बजट के आर्थिक पहलुओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक समस्याएं अभी भी जस की तस हैं। पिछले 10 वर्षों से नाममात्र जीडीपी में गिरावट देखने को मिली है और टैक्स ब्यूएंसी बेहद कम है, जिससे सरकारी राजस्व पर असर पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक पूंजीगत खर्च बढ़ाया गया है, जिससे साफ है कि निजी निवेश अभी भी गति नहीं पकड़ पा रहा है।

मनीष तिवारी
कांग्रेस सांसद

जनता के साथ छलावा

गहलोत ने केंद्रीय बजट को प्रदेश की जनता के साथ छलावा करार दिया है। बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का बजट भाषण में नाम तक न होना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार का राज्य के प्रति रवैया 'सौतेला' है। उन्होंने कहा, प्रदेश को उम्मीद थी कि डबल इंजन सरकार होने का लाभ मिलेगा, लेकिन न तो किसी नई रेलवे परियोजना की घोषणा हुई और न ही जयपुर मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को कोई सहारा मिला।"

अशोक गहलोत
पूर्व सीएम
राजस्थान

विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रतिबद्ध बजट : शिवराज

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को विकसित भारत के निर्माण की दिशा में प्रतिबद्धता बताया। केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि यह बजट गांवों और किसानों की स्थिति और भविष्य दोनों को बदल देगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय कृषि को मजबूत बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने बताया कि यह बजट गांवों, गरीबों, कृषि और किसानों का भविष्य बदल देगा। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि को विकसित करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं ताकि गांव विकास के इंजन बन सकें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश ने लगभग सात प्रतिशत की मजबूत विकास दर हासिल की है और गरीबी कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मनरेगा का कुल बजट पहले 86,000 करोड़ रुपए था, लेकिन अब 'विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के लिए अकेले केंद्र सरकार का हिस्सा 95,600 करोड़ रुपए से अधिक है, जो राज्यों के योगदान को जोड़ने पर और भी अधिक होकर 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा।

खरगे ने कहा दिशाहीन बजट, किसान बेहाल

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्रीय बजट 2026 को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के पास कोई नए विचार नहीं बचे हैं और बजट में विनिर्माण, किसान, रोजगार और बढ़ती असमानता जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए कोई नीतिगत दूरदर्शिता नहीं है। खरगे ने केंद्रीय बजट को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि इसमें देश की गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत दूरदर्शिता और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए पूछा कि मेक इन इंडिया कहां है और दावा किया कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 13% पर अटकी हुई है। खरगे ने किसानों के लिए समर्थन की कमी पर भी निराशा व्यक्त की और कहा कि वे अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका उल्लेख नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता प्रदान की गई है।

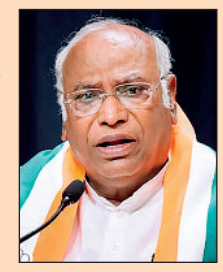

मोदी सरकार के पास कोई नए विचार नहीं

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मोदी सरकार के पास अब कोई नए विचार नहीं बचे हैं। बजट 2026 भारत की अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों का एक भी समाधान नहीं देता। 'मिशन मोड' अब 'चुनौती मार्ग' बन गया है। 'सुधार एक्सप्रेस' शायद ही किसी 'सुधार' जंक्शन पर रुकती है। नतीजा: कोई नीतिगत दूरदृष्टि नहीं, कोई राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं। हमारे अन्नदाता किसान अभी भी सार्थक कल्याणकारी सहायता या आय सुरक्षा योजना का इंतजार कर रहे हैं। असमानता ब्रिटिश राज के समय के स्तर को भी पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं है और न ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों को कोई सहायता प्रदान की गई है।

संघवाद को भारी नुकसान

खरगे ने कहा कि वित्त आयोग की सिफारिशों का और अधिक अध्ययन करना होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकारों को कोई राहत प्रदान करती हैं। संघवाद को भारी नुकसान हुआ है।

पारदर्शिता की कमी

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए इसे बिल्कुल नीरस बताया है। रमेश ने बजट से जुड़ी कई कमियों को उजागर किया, जिनमें पारदर्शिता की कमी भी शामिल है और कहा कि बजट प्रचार के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कई प्रमुख कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन स्पष्ट नहीं किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि बजट पूरी तरह नीरस निकला।

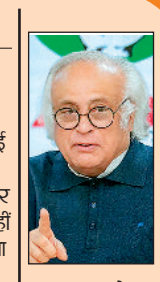

जयराम रमेश
कांग्रेस नेता

विकसित भारत का बजट

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने पर्यटन, पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा, यह विकसित भारत का बजट है। हम विकसित भारत के लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि भारत में ट्रेकिंग और प्रकृति-आधारित पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। ये योजनाएं स्थानीय रोजगार बढ़ाएंगी, पर्यावरण की रक्षा करेंगी और पर्यटकों को बेहतर अनुभव देंगी। ये घोषणाएं हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए खास फायदेमंद साबित होंगी।

-कंगना रनौत
सांसद

दिशाहीन, इसमें कुछ नहीं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि इसमें शिक्षा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया गया है और इसने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। उन्होंने केंद्र पर जानबूझकर पश्चिम बंगाल को आवंटन में नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा को आगामी विधानसभा चुनावों में हार की आशंका के चलते राज्य को दरकिनार किया गया है।

- ममता बनर्जी
मुख्यमंत्री
पश्चिम बंगाल

5 फीसदी आबादी वाला बजट

समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट गरीबों और गांवों में रहने वालों की समझ से परे है। इस बजट में न तो नौकरी दी गई है और न ही रोजगार के अवसर। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकती है। नौकरी रोजगार दिए नहीं। सपने दिखाने वाला बजट है।

अखिलेश यादव
सांसद

विकसित भारत 2047 के लिए 'संकल्प से सिद्धि': नितिन नबीन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत 2047 के लिए 'संकल्प से सिद्धि' बताया। नितिन नबीन ने विनिर्माण क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं कर्तव्य भवन में तैयार किए गए बजट का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 'सबका साथ, सबका विकास' का सिद्धांत इस बजट में झलकता है। साथ ही, यह विकसित भारत 2047 के लिए 'संकल्प से सिद्धि' वाला बजट है।

बजट एक्सपर्ट्स

जवाहर सुरिसेट्टी
प्रख्यात मनोवैज्ञानिक

परिणाम आधारित रोजगार पर ध्यान

केंद्रीय बजट 2026, पारंपरिक डिग्री-आधारित शिक्षा के बजाय परिणाम-आधारित रोजगार क्षमता पर ध्यान केंद्रित है। यह विशेष रूप से शैक्षणिक स्नातक और नौकरी के बाजार की जरूरतों के बीच के अंतर को पाटने का लक्ष्य रखता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और क्रिएटिव इकोनॉमी जैसे उभरते क्षेत्रों पर भारी जोर दिया गया है। प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह एक रणनीतिक कदम है ताकि शिक्षा जगत और उद्योग जगत एक ही माहौल में साथ काम कर सकें, जिससे उच्च शिक्षा का अलगाव और उसकी व्यावहारिक दूरी कम हो सके। साथ ही, 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। यह कदम पारंपरिक कॉर्पोरेट नौकरियों के बजाय 'क्रिएटर इकोनॉमी' की ओर 'जेन-जी' की बदलती करियर प्राथमिकताओं को स्वीकार करता है।

1.62
लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए

भारत-विस्तार एआई टूल, किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य

भारत-विस्तार एआई टूल की मदद से किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। अपने नौवें बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और एआई के इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एआई का बूस्ट मिलेगा, जो किसानों को एडवांस खेती के तरीकों के बारे में बताएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 'भारत विस्तार' की घोषणा की है। यह एक एआई बेस्ड पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी मदद से एग्रीकल्चर सेक्टर, खास तौर पर किसानों को फायदा होगा।

बजट में 500 रिजरवॉयर में मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा

बजट में मछली पालन को बढ़ावा देने का ऐलान किया। 500 रिजर्वायर में मछली पालन को बढ़ावा दिया। अमृत सरोवरों में मछली पालन को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत करने का लक्ष्य है। मछली पालन में स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा मिलेगा। इसमें महिला-नेतृत्व वाले समूहों को भी जोड़ा जाएगा। फिश फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गनाइजेशन बजट में गांव में रोजगार बढ़ाने पर फोकस होगा। एनिमल हसबेंड्री में आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा। क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी के जरिए आसान फंडिंग होगी। पशुपालन के विस्तार और मॉडर्नाइजेशन पर जोर है।

05
लाख रुपए हुई केसीसी के तहत सब्सिडी वाले अल्पकालिक ऋण

बजट में खास

पशुपालकों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना शुरू होगी

1.70 लाख करोड़ रु. से अधिक उर्वरक सब्सिडी, किसानों की लागत में राहत

पशुधन, मुर्गीपालन और डेयरी के लिए इंटीग्रेडेड वैल्यू चेन बनाने की योजना

सस्ते खाद के लिए 1,70,944 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान

एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या हाई सीज में पकड़ी गई मछली पर शुल्क मुक्त किया

मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास शुरू होगा

कृषि शिक्षा और अनुसंधान विशेषकर आईसीएआर सहित, के लिए 9,967 करोड़ रुपए का प्रावधान

नारियल और चंदन जैसी हाई-वैल्यू फसलों के समर्थन के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। पशुपालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। दुग्ध, पोल्ट्री और पशु व्यवसायों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और वैल्यू चेन से किसान संगठनों को बढ़ावा मिलेगा। नारियल और चंदन जैसी हाई-वैल्यू फसलों के समर्थन के लिए कोकोनट प्रोत्साहन योजना की मदद से 1 करोड़ किसानों और 3 करोड़ लोगों की मदद की जाएगी।

कोकोनट से जुड़े तीन करोड़ लोगों को मदद

डेयरी और मुर्गी पालन पर सरकार का बड़ा फोकस

डेयरी और मुर्गी पालन को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों से लाखों किसान और छोटे परिवार जुड़े हुए हैं। सरकार चाहती है कि किसान दूध, अंडे और इससे जुड़े उत्पादों के जरिए स्थायी आमदनी कमा सकें।।

अब काजू और कोको को मिलेगी नई पहचान

कृषि बजट 2026 में काजू और कोको को भी खास जगह दी गई है। इसके साथ ही निर्यात को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। काजू और कोको से जुड़े उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए किसानों और उद्यमियों को सहायता दी जाएगी।

रेयर अर्थ मटेरियल के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी

एआई एग्री टूल, उत्पादकता बढ़ाने में होगा सहायक

चंदन की खेती को फिर मिलेगा पुराना गौरव

वित्त मंत्री ने कहा कि चंदन सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। सरकार राज्यों के साथ मिलकर चंदन की खेती, संरक्षण और वैल्यू चैन विकास पर काम करेगी, ताकि इसकी खोई हुई गरिमा को फिर से बहाल किया जा सके। इस पर निर्भर लोगों की आय बढ़ने की उम्मीद है।

इन फसलों पर फोकस

महंगी फसलों का उत्पादन: सरकार ने इस बजट में हाई वैल्यू फसलों पर खास जोर दिया है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने और ज्यादा कमाई के लिए सरकार हाई वैल्यू उत्पादन जैसे काजू, अखरोट,नारियल, चंदन इत्यादि को सपोर्ट करेगी। इसके साथ ही सरकार ने काजू को प्रीमियम ब्रांड के रूप में रखा है। इससे एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी होगी।

पहाड़ी इलाकों में खेती को बढ़ावा : पहाड़ी इलाकों में होने वाली खेती जैसे अखरोट, बादाम, खुमानी इत्यादि को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी स्कीम लागू की जाएगी जिससे भूगोल स्थिति की वजह से होने वाली परेशानी से राहत मिल सके।

चंदन की खेती पर भी दिया गया जोर: केंद्र, राज्य के साथ चंदन की खेती और कटाई के बाद होने वाले प्रोसेस पर फोकस है, ताकि चंदन को को ज्यादा बढ़ावा मिले। चंदन जैसे बढ़ती मांग और महंगी फसल फिर से पहचान बन सके।

पिछले बजट में ये हुए थे नवाचार

वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र को 137756.55 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को पिछले बजट में 63500 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे। इस योजना का मकसद जमीन वाले किसानों की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत, देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड से हर साल 6000 रुपए की फाइनेंशियल मदद तीन बराबर चार महीने की किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को पिछले बजट में 120 करोड़ रु. का आवंटन हुआ था। इस योजना का मकसद सबसे कमजोर किसान परिवारों को सोशल सिक्योरिटी देना है। यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, जो कुछ शर्तों के तहत, पेंशन फंड में हर महीने पैसे जमा करके इस स्कीम के सदस्य बन सकते हैं।

संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना

संशोधित ब्याज सबवेंशन योजनाको पिछले बजट में 22600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। एमआईएसएस , फसल उगाने वाले किसानों और पशुपालन, डेयरी और मछली पालन जैसी दूसरी संबंधित गतिविधियों के लिए रियायती शॉर्ट टर्म कृषि लोन देती है। यह उन किसानों के लिए उपलब्ध है जो 3 लाख तक का शॉर्ट टर्म फसल लोन लेते हैं, जिस पर एक साल के लिए 7% सालाना ब्याज दर लगती है। लोन का समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाती है।

किसानों की प्रगति और विकास का बजट

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की मज़बूत नींव रखने वाला ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बजट बताया है। यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने का महाकाव्य है। यह समाज की समृद्धि और संकल्पों की सिद्धि का बजट है। यह डेवलप्ड इंडिया का डायनामिक बजट है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और विज़न से प्रेरित यह बजट वर्ष 2047 के आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध भारत की मजबूत नींव रख रहा है। कृषि विभाग का बजट बढ़ाकर इस वर्ष 1,32,561 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

अनुसंधान और सस्ती खाद पर विशेष ज़ोर

कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि उन्होंने बताया कि कृषि शिक्षा और अनुसंधान, विशेषकर आईसीएआर सहित, के लिए 9,967 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे शोध और नवाचार को बल मिलेगा। किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी पर उन्होंने कहा कि सस्ता खाद और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 1,70,944 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है, ताकि उत्पादन की लागत कम हो और किसान को राहत मिले।

लखपति दीदी और 'शी मार्ट': ग्रामीण बहनों को उद्यमी बनाने में होगा कारगर

शिवराज सिंह ने कहा कि लखपति दीदी योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए बजट में सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर शी मार्ट की व्यवस्था की गई है। हर ज़िले में बहनों के उत्पादों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कम्युनिटी-ओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे, जहां स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण बहनों द्वारा तैयार उत्पादों को नया बाज़ार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पशुपालन, कृषि से जुड़ी गतिविधियों और अन्य कार्यों में लगी बहनें अब केवल आजीविका तक सीमित न रहकर उद्यमी के रूप में आगे बढ़ सकेंगी, यही इस पहल का उद्देश्य है।

शिवराज सिंह ने कहा कि लखपति दीदी योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए बजट में सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर शी मार्ट की व्यवस्था की गई है। हर ज़िले में बहनों के उत्पादों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कम्युनिटीओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे, जहां स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण बहनों द्वारा तैयार उत्पादों को नया बाज़ार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पशुपालन, कृषि से जुड़ी गतिविधियों और अन्य कार्यों में लगी बहनें अब केवल आजीविका तक सीमित न रहकर उद्यमी के रूप में आगे बढ़ सकेंगी।

पंचायतों को दोगुनी सीधी सहायता

शिवराज ने कहा कि 16वें वित्त आयोग के ताजा निर्णय के अनुसार पंचायतों को सीधे 55,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जाएगी। पहले पांच वर्षों में पंचायतों को कुल लगभग 2,36,000 करोड़ रुपए सीधे मिले थे, जो अब बढ़कर 4,35,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। 'विकसित भारत जी राम जी' की 1,51,000 करोड़ रु. की राशि और वित्त आयोग के तहत मिलने वाले 55,900 करोड़ रु. मिलकर विकसित ग्राम, स्वावलंबी ग्राम, रोजगारयुक्त और गरीबीमुक्त गांव के निर्माण में अभूतपूर्व भूमिका निभाएंगे।

फाइबर-मेडिसिनल प्लांट्स से सीधा लाभ

नेशनल फाइबर स्कीम के अंतर्गत सिल्क, वूल और जूट जैसे फाइबर पर फोकस किया गया है, जिससे इनसे जुड़े किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। आयुष मंत्रालय में मेडिसिनल प्लांट्स के सर्टिफिकेशन और एक्सपोर्ट से संबंधित प्रावधानों का फायदा औषधीय पौधे उगाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। परंपरागत फसलों के साथ नारियल, कोको, काजू जैसी फसलों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

आम बजट पर विशेषज्ञों का नजरिया

किसान हितैषी मंशा पर खरा नहीं उतरा बजट

मोहिनी मोहन मिश्र
अखिल भारतीय महामंत्री
भारतीय किसान संघ

केंद्र सरकार का आम बजट में छोटे किसानों की समस्याएं, कृषि यंत्रों पर जीएसटी अधिक होना, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी कार्ड) की 5 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ाने की घोषणा करने के बावजूद उसका क्रियान्वयन न होना, प्राकृतिक खेती का लक्ष्य घोषणा करने के बाद भी प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को डीबीटी के माध्यम से अपना जैविक खाद बनाने को प्रोत्साहन न देना चिंता का विषय है। प्राकृतिक खेती के समर्थन में देशभर में सारी फसलों में रसायन की मात्रा के स्तर की जांच बड़ा मुद्दा है। लेकिन इस बजट में कोई योजना नहीं है। बजट में 500 अमृत सरोवर का एकीकृत विकास और पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता की सहायता करना जैसी योजना एक अच्छा कदम है। इससे अंतर्देशीय मत्स्य पालन मजबूत होगा। ग्रामीण महिला समूहों को सशक्त बनाने शी मार्ट की स्थापना भी अच्छी पहल है। इससे स्थानीय स्वयं सहायता समूह भी मजबूत होंगे। किसान परिवार के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को किसान हितैषी मांगों को शामिल कर बजट में संशोधन करना चाहिए। ताकि देश भर के जरूरतमंद किसानों का जीवन आसान हो सके।

किसान विरोधी बजट है, किसान निराश

धर्मेंद्र सिंह चौहान
अध्यक्ष, मप्र किसान कांग्रेस

कांग्रेस ने बजट को लेकर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मप्र ही नहीं देशभर के किसानों को हाशिए पर धकेल दिया। बजट में खेती को लेकर कोई राहत नहीं दी, उपकरण को लेकर भी कोई राहत नहीं दी। जीएसटी में कोई कमी नहीं की गई। किसानों टैक्टर सहित अन्य उपकरण खरीदने को लेकर कोई राहत नहीं है। यह निराशाजनक और किसान विरोधी बजट है। किसानों को बजट से भारी निराशा हुई है। फिर एक बार साबित हो गया कि भाजपा सरकार केवल पूंजीपतियों की है, किसानों से की समस्याओं से कुछ नहीं लेना देना है। यूरिया खाद की बोरी पहले जहां 43 किलो की आती थी। अब उसे 40 किलो कर दिया। धर्मेंद्र सिंह चौहान ने मांग की कि किसानों की उपज एमएसपी पर ही खरीदी करने का ऐलान होना चाहिए था।

बजट में खास

अर्थव्यवस्था और उद्योग

01

ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 'रेयर अर्थ कॉरिडोर' बनाए जाएंगे।

02

कंटेनर निर्माण के लिए 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू होगी।

03

200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को तकनीक अपग्रेड के जरिए पुनर्जीवित किया जाएगा।

04

भविष्य के एमएसएमई चैंपियंस के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड' बनेगा।

05

सरकारी कंपनियों द्वारा एमएसएमई से खरीद के लिए ट्रेडस प्लेटफॉर्म अनिवार्य होगा।

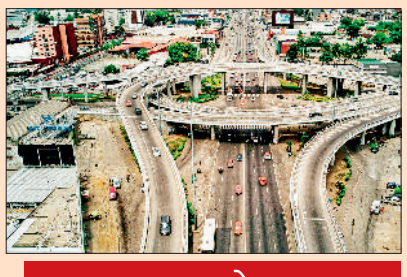

इन्फ्रास्ट्रक्चर के 7 रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ावा

आर्थिक विकास को गति देने के लिए बजट में राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली परियोजनाओं सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर को सशक्त प्रोत्साहन देने, 7 रणनीतिक क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और तेजी से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सृजित करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक निवेश पर मजबूत जोर देते हुए राजकोषीय विवेक और मौद्रिक स्थिरता बनाए रखी है, और आगे कहा कि भारत को वैश्विक बाजारों के साथ गहराई से जुड़ना चाहिए, अधिक निर्यात करना चाहिए और विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना चाहिए।

छोटे शहर अब 'बड़े' होंगे, खुला खजाना, थोक में मिलेगा रोजगार भी

केंद्रीय बजट में इस बार सरकार ने अपने खर्च की पूरी तस्वीर सामने रख दी है। इस बजट में साफ दिख रहा है कि फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और आम आदमी से जुड़े सेक्टरों पर है। बजट के आंकड़ों के मुताबिक, सरकार का सबसे ज्यादा खर्च परिवहन और रक्षा जैसे बड़े क्षेत्रों में जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में और रफ्तार पकड़ सकते हैं। सरकार का मानना है कि मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षित देश ही तेज आर्थिक विकास ही बुनियाद बनते हैं।

सरकार का फोकस शहरी आर्थिक क्षेत्रों को विकसित करना

बजट में इस क्षेत्र के लिए 12.2 करोड़ रुपए रखे गए है

इस बार बजट में सरकार ने जन निवेश पर जोर देते हुए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ किया है। सरकार का मकसद है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। बजट में विशेष ध्यान टियर-2 और टियर-3 शहरों पर रखा गया है, जो धीरे-धीरे विकास के नए केंद्र बनते जा रहे हैं। इस बार एक बड़ा कदम इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना का प्रस्ताव है। इसका मकसद बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को आंशिक गारंटी देना है ताकि बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निर्माण के दौरान जोखिम कम हो और निजी निवेश बढ़े। साथ ही, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (सीपीएसई) की रियल एस्टेट संपत्तियों को रीटस् के जरिए तेजी से मोनेटाइज करने की योजना है। इससे खाली पड़ी संपत्तियों का सही उपयोग होगा, भूमि की दक्षता बढ़ेगी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पूंजी उपलब्ध होगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बढ़ाया गया

त्रेहान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सारांश त्रेहान का कहना है, 'केंद्रीय बजट 2026 भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को काफी बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए पूंजीगत खर्च 12.20 लाख करोड़ रखा गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा है और यह शहरी और उभरते बाजारों में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाएगा। रीट्स आधारित एसेट रीसाइक्लिंग को तेजी से लागू करने और टियर-2 एवं टियर-3 शहरों के लिए समर्थन देने पर जोर, निवेशकों का भरोसा और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत मदद को दर्शाता है। बेहतर अफोर्डेबिलिटी और फाइनेंसिंग विकल्पों के साथ यह बजट मांग को बढ़ा सकता है और रियल एस्टेट सेक्टर को रोजगार, शहरीकरण और समावेशी विकास में स्थायी योगदान देने में मदद करेगा।'

विश्वास पैदा होगा

वीवीआईपी ग्रुप के एमडी विभोर त्यागी का कहना है, बजट से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विश्वास पैदा होगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क डेवलपमेंट फंड और सीपीएसई संपत्ति मोनेटाइजेशन से विकास और पारदर्शिता बढ़ेगी।'

शहरी आर्थिक क्षेत्रों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव

पांच वर्षों में 5000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव

शहरवासियों को बुनियादी ढांचे से बेहतर सुविधाएं मिलेगी

केंद्रीय वित्त मंत्री ने शहरी विकास को मजबूत करने के लिए एक बड़े कदम की घोषणा की। इसके तहत शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सीईआर) के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और प्रत्येक क्षेत्र के लिए पांच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। इसका मकसद संबंधित योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना है। सीतारमण ने लोकसभा में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए शहरों को भारत के विकास, नवोन्मेष और अवसरों का इंजन बताया और कहा कि यह नई पहल दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के साथ-साथ मंदिर नगरों पर केंद्रित होगी, जिन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर शहर आर्थिक क्षेत्र का मानचित्रण करके शहरों की आर्थिक शक्ति को और अधिक बढ़ाना है। सीतारमण ने कहा, 'सुधार-सह-परिणाम आधारित वित्तपोषण व्यवस्था के साथ चुनौतीपूर्ण तरीके से उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रत्येक सीईआर के लिए पांच वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।' उन्होंने कहा कि पिछले दशक में, उनकी सरकार ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के व्यापक सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट) जैसे नए वित्तपोषण साधन और एनआईआईएफ (राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष) और एनएबीएफआईडी (राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा और विकास वित्त पोषण बैंक) जैसी संस्थाएं शामिल हैं।

पर्यावरण अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'पर्यावरण के अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मैं नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हूं, जो पूर्व में डांकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ेगा. अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्ग चालू किए जाएंगे, शुरूआत राष्ट्रीय जलमार्ग 5 से ओडिशा में होगी, जो तालचर और अंगुल जैसे खनिज-समृद्ध क्षेत्रों और कलिंगानगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और डामरा के बंदरगाहों से जोड़ेगा. साथ ही, वाराणसी और पटना में इनलैंड वाटरवे के लिए जहाज मरम्मत का एक इकोसिस्टम भी स्थापित किया जाएगा.।

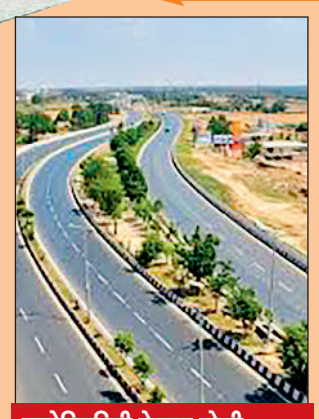

कनेक्टिविटी बेहतर होगी

गंगा रीयल्टी के जेएमडी विकास गर्ग कहते हैं, 'सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि से प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता और कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे निजी निवेश बढ़ेगा। रीट्स और इनविट के जरिए पूंजी जुटाने से संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।'

रिटेल इकोनॉमी के लिए बड़े अवसर लाएगा

भुटानी के सीईओ आशीष भुटानी का कहना है, 'यह बजट रिटेल इकोनॉमी के लिए बड़े अवसर लाएगा। टैक्स में आसानी, एमएसएमई का समर्थन और लॉजिस्टिक्स व कनेक्टिविटी में निवेश से खरीदारों की क्षमता बढ़ेगी। इसका असर टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी महसूस होगा।'

परिवहन पर सबसे ज्यादा खर्च

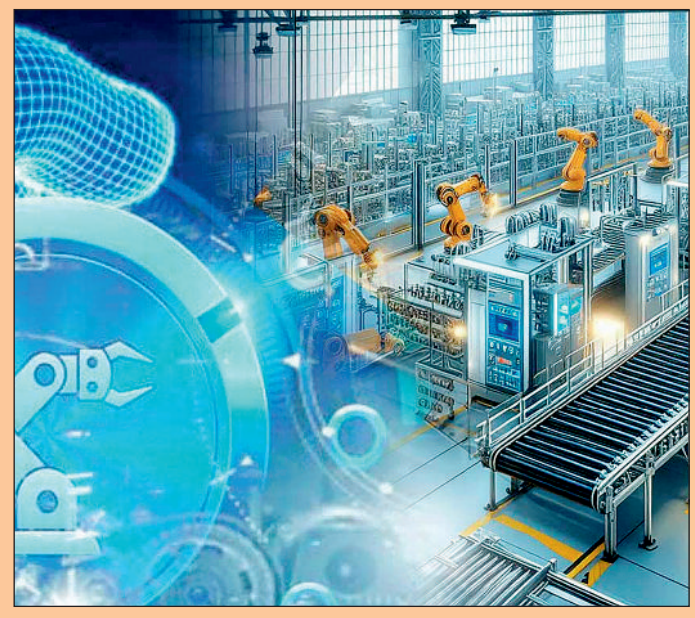

खर्च के आंकड़ों पर नजर डालें तो परिवहन सेक्टर सबसे ऊपर है, जहां करीब 5.98 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके ठीक बाद रक्षा बजट है, जिस पर 5.94 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे साफ है कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा और सैन्य क्षमता को मजबूत करने पर कोई समझौता नहीं करना चाहती। वहीं, ग्रामीण विकास के लिए 2.73 लाख करोड़ रुपये और गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह खर्च ग्रामीण इलाकों में सड़क, आवास, रोजगार और सुरक्षा से जुड़े कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

आम बजट पर आम नजरिया

विकास के लिए मजबूत आधार का निर्माण

रविन्द्र के. ब्रम्हे
प्रोफेसर अर्थशास्त्र
पं. रविवि, रायपुर

चुनौतियों और अनिश्चितताओं के समय में वित्त मंत्री के लिए बजट बनाना है इतना आसान नहीं था। वित्त मंत्री ने वृद्धि को सतत रूप से बनाए रखने के लिए संरचनात्मक सुधारो के माध्यम से आधारभूत संरचना, विनिर्माण और रोजगार की क्षमता को विकसित करने वाले आधार को मजबूत किया है। लगभग 53.47 लाख करोड़ के बजट में राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए एक ओर राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 प्रतिशत पर रखा है वहीं ऋण को जीडीपी के 55.6 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य आकांक्षा को उपलब्धि में और क्षमता को निष्पादन में परिवर्तित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ हर किसी तक पहुंचे।

बजट में सबसे अधिक प्रावधान आधारभूत संरचना के लिए 12.02 लाख करोड़ का रखा गया है। साथ ही रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्र के विनिर्माण उद्योगों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। विनिर्माण उद्योग के लिए अनेक कर सुधार भी बजट में है। मध्य और लघु उद्योगों को इक्विटी सपोर्ट एक महत्वपूर्ण कदम है। देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जीडीपी निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान है। । इसी को देखते हुए टूरिज्म, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय क्षेत्र के लिए अनेक अभिनव प्रावधान बजट में किए गए हैं।

हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

haribhoomi.com

बिलासपुर, सोमवार, 2 फरवरी, 2026

छत्तीसगढ़ में पहली बार दुर्ग में पत्नी प्रताड़ित पुरुषों की काउंसलिंग कर रही पुलिस

डॉ. संदीप उपाध्याय ▸▸ भिलाई

आ रहे अनोखे मामले पति कर रहे मांग मांग पत्नी साथ रहे, लेकिन आदर्श पत्नी की तरह

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहली बार पत्नी से प्रताड़ित पतियों की सुनावाई के लिए एक अलग से पुरुष परामर्श केंद्र शुरू किया गया है। यहां सप्ताह में एक दिन पतियों की पीड़ा सुनने के लिए रिटायर्ड पुलिस और बीएसपी के अधिकारी बैठते हैं। इसके बाद पति और पत्नी दोनों के बयान लेकर उन्हें फिर से नई जिंदगी शुरू करने की समझाइश दी जाती है। इससे अब तक कई घर टूटने से बच चुके हैं।

अलग खबर

अनुभवी टीम कर रही काउंसिलिंग

काउंसिलिंग के लिए पुलिस विभाग से रिटायर्ड एएसपी रैंक के अधिकारी अशोक जोशी और भिलाई स्टील प्लांट के रिटायर अधिकारी बसंत कुमार को रखा गया है। महिलाओं की समस्या को सुनने और बयान दर्ज करने के लिए कांस्टेबल सुषमा चौरे को रखा गया है।

घर टूटने से बच रहे हैं

ये एक तरह की अलग पहल है। हर एक मामले को काफी धैर्य से सुना जा रहा है और उन्हें अच्छी सलाह दी जा रही है। इससे कई घर टूटने से बच रहे हैं।

-विजय अग्रवाल, एसएसपी दुर्ग

आपको बता दें दुर्ग जिले में दिसंबर महीने में दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर महिला थाना सेक्टर 6 में पुरुष परामर्श केंद्र शुरू किया गया था। यह अपनी तरह पहला ऐसा केंद्र है, जहां पत्नी की नहीं पतियों की फिरयाद को विशेष रूप से सुना जाता है। इस ▸▸शेष पेज 4 पर

केस 1

काउंसलिंग में एक पति अपनी पत्नी के गैर मर्द के साथ गलत संबंध से पीड़ित होकर आया। यहां उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा। पत्नी ने भी गलती स्वीकार किया। काउंसिलिंग में समझाइश के बाद पति अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ फिर से नया जीवन जीने को तैयार हो गया।

केस 2

दूसरा केस ऐसा आया कि ट्रांसपोर्टर पति के ट्रक बिक जाने से वो घर पर बैठ गया। उसने 15000 रुपए महीने की नौकरी की, लेकिन पत्नी 60 हजार रुपए महीने कमा रही है और पति चाहता है कि वो उसकी हर बात माने, इसे लेकर दोनों में विवाद होता है। पति का आरोप है कि पत्नी उसे अश्लील गालियां देती हैं। वहीं पत्नी ने आरोपों को गलत बताया है।

केस 3

एक केस में 51 साल का अधेड़ खुद मोचीगिरी का काम करता है। आर्थिक स्थिति खराब होने से जब पत्नी कमाने के लिए बाहर निकली तो पत्नी पर शक करने लगा। पत्नी उसे छोड़कर तीन साल से अलग अपनी बेटी के साथ रह रही है तो अब वो पत्नी को साथ लाने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहा है।

आनंद का सच्चा भाव

18 कैरेट रेट (75.00%) = ₹114621/-

22 कैरेट रेट (91.60%) = ₹139990/-

24 कैरेट रेट (99.99%) = ₹152813/-

सोने का भाव* प्रति 10 ग्राम | GST Extra

*Conditions apply

ANAND Jewels

Pandri, Raipur

खबर संक्षेप

आमजन के लिए आज से खुलेगा अमृत उद्यान

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान के 'शीतकालीन

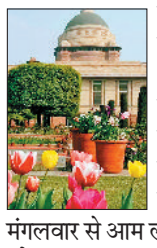

वार्षिक संस्करण 2026' का रविवार को उद्घाटन किया। इसके साथ ही यह उद्यान मंगलवार से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लोग सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम छह बजे के बीच (अंतिम प्रवेश शाम पांच बजे) उद्यान में जा सकेंगे।

चांदी 25 हजार फिर टूटी, सोना दो दिन में 31 हजार हुआ सस्ता

नई दिल्ली। सोना-चांदी की कीमतों में भूचाल मचा है। रविवार को बजट के चलते शुरू हुए कारोबार के दौरान एक बार फिर खुलते ही गोल्ड-सिल्वर के रेट बुरी तरह टूट गए हैं। 1 फरवरी को वायदा बाजार में चांदी करीब 25 हजार रुपए (9%) गिर गई। 1 किलो चांदी का भाव 2.65 लाख रुपए पर आ गया। सोने में भी करीब 12 हजार रुपए की गिरावट है। 10 ग्राम सोना 1.38 लाख रुपए पर आ गया है। चांदी दो दिन में 1.36 लाख सस्ती हो गई, वहीं सोना 31 हजार रुपए सस्ता होकर 1.38 लाख रुपए पर आया।

पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर से होगी पूछताछ

हैदराबाद। तेलंगाना विशेष जांच दल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) से

बीआरएस शासन के दौरान कथित 'फोन टैपिंग' से जुड़े मामले में रविवार दोपहर यहां उनके आवास पर पूछताछ करेगी। राव ने शनिवार को एसआईटी से कहा था कि वह एक फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होंगे। उन्होंने नोटिस जारी करने में जांच अधिकारी पर 'कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन' किए जाने का भी आरोप लगाया।

सनसनी फैलाने वाले बदमाशों का गिरोह पकड़ा गया दो रातों में 14 को किया था जख्मी

दो दिनों में दर्जनभर वारदात, पुलिस ने घेरा, मुठभेड़ में एक बदमाश घायल

हरिभूमि न्यूज ▸▸ जांजगीर-चाम्पा

जिला पुलिस ने लुटेरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह ने दो दिनों के भीतर दर्जनभर लोगों को अपना शिकार बनाया था। पुलिस ने 7 आरोपियों को राहौद से गिरफ्तार किया। गिरोह के सरगना को बोडसरा गांव में पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शनिवार की रात घेराबंदी की। रविवार तड़के सरगना ने भागने की फिराक में देसी कट्टा से पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग मे आरोपी के पैर मे गोली लगी और घायल आरोपी ने पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर दिया। गिरोह ने पामगढ़ और शिवरीनारायण क्षेत्र ने दो रात मे ही कई वारदातों को अंजाम देकर क्षेत्र मे सनसनी फैला दी थी। इन घटनाओं में 14 लोग घायल हुए हैं।

रात में घेराबंदी, मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया

जिले में लुटेरों का एक नया गिरोह तैयार हो रहा था। शिवरीनारायण और पामगढ़ थाना क्षेत्र में इस गिरोह ने दो दिन में लूटपाट और मारपीट की कई वारदात की। शराब के नशे के लिए यह गिरोह रात के अंधेरे में घटना को अंजाम दे रहा था। दो दिनों में 5 घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें 14 लोग घायल हुए है। इनमें से दो की हालत गंभीर है जिनका बिलासपुर के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। सभी आरोपी बाइक में घूमते थे और रात में सड़क पर सुन पाकर अंधेरे में आने जाने वाले लोगों से मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने शिवरीनारायण और पामगढ पुलिस के साथ ही साइबर सेल की टीम बनाई। आरोपियों की ▸▸शेष पेज 4 पर

दो की हालत नाजुक

आरोपियों ने कुल 14 लोगों पर हमला कर लूट की वारदात की है। इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुकेश राय सागर निवासी कचंदा और अमन बंजारे निवासी कचंदा गंभीर हालत में आईसीयू में बिलासपुर के निजी अस्पताल में ▸▸शेष पेज 4 पर

गैंग में दो नाबालिग

पुलिस की गिरफ्त में आए गिरोह में 2 विधी के विरूद्ध संघर्षरत बालक भी शामिल हैं। वहीं शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के राहौद निवासी रामनाथ गोड़ पिता छोटे बाबू उम्र 21 साल, निखिल टंडन पिता राकेश टंडन उम्र 18 साल, मनीराम गोंड पिता छोटेबाबू गोंड उम्र 19 साल, नरेश यादव पिता फिरतू यादव उम्र 19 साल , रोशन टंडन पिता राकेश टंडन उम्र 19 साल और पामगढ थाना क्षेत्र के डुडगा निवासी आयुष रात्रे पिता अयोध्या रात्रे उम्र 18 साल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

पनपने से पहले पकड़ा

प्राणघातक हमला कर लूटपाट करने वाले आरोपियों का गिरोह हाल ही में तैयार हुआ था। गिरोह में सभी युवा हैं, जो नशे की जरूरत पूरी करने के लिए वारदात कर रहे थे। आरोपी एकत्रित होकर मोटर साइकिल से सुनसान एवं अंधेरे रास्तों पर घूमते थे और सड़क पर चल रहे राहगीरों को रोकर सीधे सिर पर प्राणघातक वार करते थे। हमले के बाद वे पीड़ितों से मोबाइल फोन, नकदी एवं अन्य कीमती सामान लूट लेते थे। इतना ही नहीं, वारदात के बाद भी रास्ते में जो भी व्यक्ति मिलता, उस पर सभी आरोपी एक साथ हमला कर देते थे।

टी20 वर्ल्ड कप

भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान

नई दिल्ली। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ आगामी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगी। दोनों देशों के बीच तय कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हाईवोल्टेज मैच खेला जाना था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है। पाकिस्तान सरकार के बयान में इस फैसले का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के खिलाफ विश्व कप मैच का बहिष्कार करेगा।

सलमान अली आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और यूएसए के साथ ग्रुप-ए में शामिल है। पाकिस्तानी टीम 7 फरवरी को कोलंबो में नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पाकिस्तानी सरकार के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हिस्सा लेने की मंजूरी देती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी।

आरोपियों ने ग्रामीणों पर किया हमला आक्रोशित गांव वालों ने फूंकें कई घर

- गरियाबंद जिले के दुधकैयां गांव में विवाद के कारण तनाव
- उग्र भीड़ को काबू पाने पुलिस को करना पड़ा हल्के बल का प्रयोग

हरिभूमि न्यूज ▸▸ गरियाबंद/ राजिम

एक ओर गरियाबंद जिसे में जहां कल्प कुंभ का शुभारंभ हुआ, वहीं दूसरी ओर राजिम से महज कुछ किलोमीटर दूर दुधकैयां गांव में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। संदिग्धों ने घरों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि करीब साल भर पहले शिवजी के मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में प्रतिमा खंडित करने वाले आरोपी जमानत मिलने के बाद गांव वालों को डराने-धमकाने लगे थे। उन्होंने तीन गांव के लोगों के साथ मारपीट और जानलेवा हमला कर दिया। वहीं, वे प्रकरण में गवाही देने वालों को भी

परेशान कर रहे थे। गांव वालों के साथ हुई मारपीट के बाद पूरा गांव उत्तेजित हो गया। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कई घरों पर आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मौके पर शांति स्थापित करने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। जिसमें कुछ जवान चोटिल हुए हैं।

मौके पर पहुंचे पुलिस के आला-अफसर

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के आला-अधिकारी गांव दल-बल समेत गांव पहुंच गए। बेकाबू होते लोगों को नियंत्रित करने के लिए हल्के बल का भी प्रयोग करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राजिम समेत, फिंगेश्वर और आसपास के कई थानों से फोर्स बुलाई गई।

आरोपी को किया गया गिरफ्तार

अभी स्थिति शांत है, आरिफ नाम का पुराना आरोपी है। उसने ग्रामीणों से मारपीट की है। वहीं, पास के दो गांव में भी उसने मारपीट की है। इस पर राजिम थाने में तीन एफआईआर हुए हैं। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। इसके बाद उन्होंने घरों का घेराव किए और इसमे आग लगा दिए। तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अभी स्थिति सामान्य है। घटना में कुछ पुलिस वालों को चोटें आई हैं।

- वेदव्रत सिरमौ
एसपी, गरियाबंद

एक फरवरी से हो गए बड़े बदलाव

सिगरेट-कमर्शियल सिलेंडर महंगा, फास्टेग पर सौगात

हरिभूमि न्यूज ▸▸ नई दिल्ली

एक फरवरी से तंबाकू उत्पादों की कीमतों से लेकर गैस सिलेंडर, फास्टैग और ब्याज दरों तक, कई मोर्चों पर नई व्यवस्था लागू हुई है। रविवार से कई सारे बदलाव लागू हो गए। सिगरेट, पान मसाला में उपकर लागू हो गया। इसके अलावा 1 फरवरी से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 50 तक महंगा हो गया है। अब से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब केवाईवी (नो योर व्हीकल) प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी।

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू होने के बाद रविवार से सिगरेट के दाम में प्रति 10 सिगरेट के पैकट पर न्यूनतम 22 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। वितरकों के अनुसार, 76 मिमी लंबाई वाली प्रीमियम सिगरेट अब ब्रांड के हिसाब से 10 सिगरेट के पैकट पर 50 से 55 रुपए तक महंगी हो गई हैं। हालांकि, कंपनियों ने ▸▸शेष पेज 4 पर

फास्टैग यूजर्स को केवाईवी की जरूरत नहीं

नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब केवाइवी (नो योर व्हीकल) प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई कार के लिए केवाईवी प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। साथ ही, जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगा है, उनके मालिकों को भी अब रूटीन केवाईवी कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्युमेंट होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

कमर्शियल सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े

तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की वृद्धि कर दी है। इस बढ़ोतरी से छोटे दुकानदारों, हलवाइयों, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों पर सीधा असर पड़ेगा। यह लगातार तीसरा महीना है। पेट्रोलियम मार्केटिंग करने वाली सरकारी कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडरों के दाम की समीक्षा करती हैं। इसी क्रम में 1 फरवरी से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 1839 रुपए हो गई है। पिछले महीने इसकी कीमत 1789.50 रुपए थी, जबकि दिसंबर में यह 1678 रुपए पर निर्धारित थी।

पुराने 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर नहीं, अब पांच नए कॉलेजों की चिंता

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

चिकित्सा शिक्षकों के 1123 पद खाली पड़े, नए कॉलेजों में लगभग 100 की होगी जरूरत

राज्य में संचालित 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज 45 प्रतिशत चिकित्सा शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में पांच नए चिकित्सा महाविद्यालय की फैकल्टी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। पुराने कॉलेजों में पढ़ाई 935 डाक्टरों के भरोसे हो रही और 1123 पद खाली हैं। ऐसे में 5 नए कॉलेजों के लिए लगभग 100 शिक्षकों की जरूरत होगी।

राज्य में सवा सौ असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए बुलाए गए आवेदन के आधार पर इंटरव्यू होने का इंतजार है। 10 कॉलेजों में पदस्थ पुराने चिकित्सा शिक्षक भी पिछले पांच साल से प्रमोशन आर्डर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में कबीरधाम, मनेंद्रगढ़, जांजगीर-चांपा, गीदम और जशपुर में नए चिकित्सा महाविद्यालय खोलना शासन के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। 10 शासकीय कॉलेजों में वैसे तो कुल 2058 चिकित्सा शिक्षकों का सेटअप है, इनमें नियमित, संविदा मिलाकर 935 काम कर रहे हैं और 1123 पद रिक्त हैं। चिकित्सा शिक्षकों की 45 फीसदी की कमी के कारण अक्सर किसी न किसी शासकीय कॉलेज में जीरो ईयर की तलवार लटकती रहती है। ऐसे में इस साल खुलने वाले पांच नए कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की व्यवस्था कहां से होगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जानकारों को कहना है कि आने वाले दिनों में फैकल्टी की होने वाली बड़ी समस्या से बचने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को अभी से प्रयास करना चाहिए। इसके लिए डीपीसी की बैठक कर पुराने चिकित्सा शिक्षकों को प्रमोशन देने और नए असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती शीघ्र किया जाना चाहिए।

सवा सौ असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती का इंतजार, पुराने भी ताक रहे प्रमोशन का रास्ता

नियमितिकरण भी बड़ी चुनौती

वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों में करीब चार सौ डॉक्टर संविदा आधार पर अपनी सेवा दे रहे हैं। इनमें से कई तो रिटायरमेंट के करीब हैं, मगर आदर्श भर्ती नियम लागू होने के बाद भी इन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। रेगुलर नहीं होने की वजह से संविदा डॉक्टर समय-समय पर नौकरी छोड़कर झटका भी दे रहे हैं। वहीं कॉलेज स्तर पर समय-समय पर निकलने वाली सौ से ज्यादा की भर्ती प्रक्रिया में दो से तीन लोगों की ज्वाइनिंग संविदा सेवा के प्रति नीरसता को दर्शाती है। मेडिकल कॉलेजों में सबसे ज्यादा कमी सीनियर रेसीडेंस डॉक्टरों की है।

दोहरी जिम्मेदारी

शासन द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों में डीन की नियुक्ति प्रभारी के रूप में की है। उनके नेतृत्व में इन कॉलेजों में आवश्यक निर्माण पूरा करने के साथ अन्य डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में नियुक्ति किए गए डीन अन्य मेडिकल कॉलेजों की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उनकी दोहरी जिम्मेदारी मूल काम को प्रभावित कर सकती है। वर्तमान में सौ से ज्यादा चिकित्सा शिक्षक अधीक्षक अथवा डीन बनने के पात्र हैं, मगर प्रमोशन के अभाव में जूनियरों को यह जिम्मेदारी देकर काम चलाया जा रहा है।

आर्थिक रूप से कमजोर दंपती की सुविधा के लिए शुरू किया जाना था सेंटर

हवा में आंबेडकर अस्पताल का आईवीएफ सेंटर, घोषणा, प्रस्ताव के बाद ठप

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

शासकीय स्तर पर सुविधा नहीं, निजी हास्पिटलों में लाखों खर्च करना मजबूरी

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की घोषणाओं के बीच आंबेडकर अस्पताल का आईवीएफ सेंटर सिमटकर रह गया है। राज्य शासन ने अपने पिछले बजट में इसके लिए दस करोड़ का प्रावधान किया, मगर काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। आईवीएफ सेंटर का निर्माण आर्थिक रूप से कमजोर दंपती को संतान सुख की प्राप्ति के लिए किया जाना था। अस्पताल प्रबंधन द्वारा आवश्यक निर्माण सहित जरूरी उपकरणों की सूची बनाकर विभाग को भेज दी गई जो दस माह बाद भी ठंडे बस्ते से बाहर नहीं आया।

शासकीय स्तर पर आईवीएफ अथवा एआरटी सेंटर की सुविधा शुरू नहीं होने की वजह से निजी हास्पिटलों जाकर लाखों रुपए खर्च करना निसंतान दंपती की मजबूरी है। जानकारों का कहना कि शासकीय स्तर पर यह सुविधा शुरू होने से उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। शासकीय स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य शासन द्वारा पिछली बजट में आंबेडकर अस्पताल से स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में आईवीएफ सेंटर प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके लिए उस दौरान दस करोड़ का प्रावधान भी किया गया था और विभिन्न 9 पदों पर भर्ती को मंजूरी भी दी गई थी। घोषणा के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस सुविधा को प्रारंभ करने के लिए जरूरी उपकरण और अन्य निर्माण संबंधी प्रस्ताव बनाकर मेडिकल कालेज प्रबंधन के माध्यम से शासन को भिजवा दिया गया था। इसके बाद विभिन्न मंच के माध्यम से एआरटी सेंटर खोलने की घोषणा हुई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जानकारों का कहना है कि शासकीय स्तर इसकी सुविधा नहीं होने की वजह से हर जरूरतमंद इसका लाभ नहीं ले पाते क्योंकि प्रायवेट सेंक्टर में इसका खर्च लाखों रुपए का है।

प्रस्ताव भेजा जा चुका

जरूरतों के हिसाब से एआरटी सेंटर बनाने आवश्यक उपकरणों सहित अन्य संसाधनों का प्रस्ताव कालेज प्रबंधन के माध्यम से शासन को भेजा जा चुका है। इसकी सुविधा शुरू होने से जरूरतमंद मरीजों को इसका लाभ मिल सकेगा।

- डा. ज्योति जायसवाल, विभागाध्यक्ष, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, आंबेडकर अस्पताल

नए भवन का इंतजार

सूत्रों का कहना है कि वर्तमान में मरीजों का सबसे ज्यादा बोझ सहने वाले स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में एआरटी सेंटर शुरू करने के लिए 700 बेड के नए भवन बनने का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी ओर अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि पुराने भवन में ही इसकी शुरुआत की जा सकती है और आवश्यकता होने पर निर्माण पूरा होने के बाद आवश्यकता होने पर सेटअप नए भवन में शिफ्ट किया जा सकता है।

दस फीसदी को समस्या

चिकित्सकों के मुताबिक करीब दस फीसदी दंपति ऐसे होते हैं जो अलग-अलग कारणों से संतान सुख नहीं ले पाता है। ऐसे में उनके पास आईवीएफ जैसी आधुनिक सुविधाओं के जरिए संतान प्राप्ति का रास्ता होता है। निजी सेक्टर में ऐसे की सेंटर कार्यरत है मगर शासकीय स्तर पर यह सुविधा शुरू होने से अधिकांश जरुरतमंद इसका फायदा प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार आंबेडकर अस्पताल में हर माह 10 से 20 महिलाएं आती हैं जो मां नहीं बनने पर आईवीएफ तकनीक अपनाना चाहती हैं।

एम्स में इसी माह शुरू होने की संभावना

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इसी माह आईवीएफ सुविधा शुरू होने की संभावना है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स सबसे बड़ा सेंटर हैं जिसका संचालन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राज्य में सबसे बड़े अस्पताल का दर्जा आंबेडकर हास्पिटल को दिया जाता है जहां इस सुविधा की शुरुआत घोषणाओं में सिमटा हुआ है। अस्पताल प्रबंधन इसके माध्यम से इलाज शुरू करने शासकीय स्तर पर काम शुरू होने का इंतजार कर रहा है।

मौसमी व्यवधान के साथ बीतेगा फरवरी... बादल बारिश, ओलावृष्टि के साथ पारा भी चढ़ेगा

- मौसम को बिगाड़ने वाले पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने की संभावना ज्यादा
- हवा की दिशा में बदलाव से कम होगी ठंड, माहांत तक 35-36 डिग्री की गर्मी

रायपुर। फरवरी के महीने में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ मौसमी व्यवधान पैदा करने वाले होते हैं। इसके प्रभाव से बादल, बारिश के साथ आम सहित अन्य फसलों को खराब करने वाले ओलावृष्टि की संभावना रहती है। महीने के शुरुआत में राज्य में वर्षा होने की संभावना है और आने वाले दिनों में अन्य तरह की हलचल से भी इंकार नहीं किया जा रहा है। इस मौसम होने वाले हवा की दिशा में बदलाव से अधिकतम तापमान के चढ़कर मध्य इलाकों में 35-36 होने की संभावना भी है।

जनवरी की विदाई के साथ प्रातःकाल में सिमट चुकी ठंड का प्रभाव फरवरी में धीमे-धीमे कमी आने की संभावना है। दिन की लंबाई बढ़ने के साथ इस महीने राज्य में आने वाली हवा की दिशा में बदलाव होगा जो मौसम की शुष्कता को कम करेगा जिससे रात के साथ दिन का तापमान भी चढ़ेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक फरवरी महीने में पश्चिमी विक्षोभ राज्य को काफी बार प्रभावित करता है और इससे बादल छाने, बारिश होने के साथ कई बार

ओलावृष्टि के आसार भी बनते है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मौसमी उतार-चढ़ाव की संभावना अधिक है और इसकी शुरुआत सोमवार से राज्य के कुछ एक इलाकों में बारिश के रूप में होने के आसार है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और ठंड में उपयोग होने वाले गर्म कपड़ों से दूरी बनाने की आवश्यकता होगी। फरवरी में ठंड की विदाई का प्रभाव दक्षिण और मध्य हिस्से पर ज्यादा नजर आएगा। रायपुर सहित मध्य हिस्से में दिन का तापमान माह के अंतिम दिनों तक 35-36 डिग्री तक पहुंचने के आसार है।

17 साल पहले 38 डिग्री का रिकार्ड

रायपुर में 17 साल पहले यानी वर्ष 2009 में 28 फरवरी को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था जो अब तक का रिकार्ड है। इसी तरह फरवरी में पेंड्रा में 27 फरवरी 2006 को पारा 37 डिग्री, जगदलपुर में 20 फरवरी 2006 को 38.7, अंबिकापुर में 25 फरवरी 2006 को 34.8, बिलासपुर में 28 फरवरी 2009 में 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था। इस बार भी तापमान इसके करीब जाने की संभावना है।

अभी दिन-रात का पारा 2 डिग्री ज्यादा

अभी रायपुर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक रिकार्ड किया जा रहा है। वर्तमान में सुबह-सुबह ठंड का प्रभाव है और दिन चढ़ने के बाद गर्मी बढ़ती महसूस हो रही है। सरगुजा समेत उत्तरी हिस्से में ठंड की विदाई में कुछ वक्त लगने के आसार है मगर मध्य हिस्से ठंड का प्रभाव आने वाले दिनों में समाप्त होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में रायपुर का तापमान सबसे ज्यादा 31. 1 तथा सबसे कम अंबिकापुर का 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

एसी-कूलर का आया सीजन, गांवों में भी डिमांड, गर्मी में इस बार 900 करोड़ के कारोबार का अनुमान

रायपुर। गर्मी का आगाज इस बार अभी नहीं हो सका है, लेकिन कारोबारियों ने एसी और कूलरों का स्टॉक मंगाकर रख लिया है। एसी और कूलरों के बिकने का सिलसिला इस माह से प्रारंभ हो जाएगा। इस बार

- जीएसटी कम होने से दाम भी दस फीसदी तक घटे

सीजन में डेढ़ लाख से ज्यादा एसी बिकने का अनुमान है। बीते साल सवा लाख एसी बिके थे। पहली बार गर्मी के सीजन में इतने ज्यादा एसी बिके थे। इसके पीछे का कारण यह है कि अब गांवों से भी एसी की डिमांड आ रही है। इस सीजन में एसी और कूलरों का मिलाकर 900 करोड़ का कारोबार अनुमानित है। एसी के दाम इस बार जीएसटी कम होने के कारण दस फीसदी तक कम हो गए हैं। एयर कंडीशनर यानी एसी भी अब खास से आम गया है। एक समय था, जब इसकी डिमांड बड़े शहरों और अमीरों के घरों के लिए होती थी, लेकिन अब एसी की डिमांड बड़े शहरों से हटकर गांवों और छोटे शहरों में भी बढ़ गई है। अब मध्यम वर्ग के घरों में भी एसी एक से ज्यादा लग रहे हैं। यही वजह है कि बीते तीन साल से हर साल 20 से 25 फीसदी कारोबार में इजाफा रहा है।

तीन साल में एसी का कारोबार डबल

एसी का कारोबार बड़ा होता है। ब्रांडेड एसी 30 हजार से एक लाख तक के आते हैं। पहले एसी कम बिकते थे, लेकिन बीते तीन सालों से एसी की डिमांड बढ़ गई है। हर साल 15 से 20 हजार एसी ज्यादा बिक रहे हैं। तीन साल पहले प्रदेश में 50 हजार के आस-पास ही एसी बिकते थे, लेकिन जहां 2023 में 65 हजार के आस-पास एसी बिके, वहीं 2024 में 80 हजार बिके हैं। बीते साल सवा लाख एसी बिके हैं। ऐसे में बीते साल 45 हजार एसी ज्यादा बिके। यानी कारोबार में 50 फीसदी का इजाफा हो गया।

600 करोड़ का होगा एसी का कारोबार

कम और ज्यादा कीमत को देखते हुए एक एसी की औसत कीमत अगर 40 हजार मान लें तो इस सीजन में करीब छह सौ करोड़ का कारोबार हो जाएगा। इस बार तो कीमत में दस फीसदी तक की कमी आई है। बीते साल सितंबर में जीएसटी को एसी पर 28 फीसदी के स्थान पर 18 फीसदी कर दिया गया है। ऐसा होने से 40 हजार का एसी चार हजार रुपए कम हो गया है। तीस हजार वाला एसी तीन हजार रुपए कम हो गया है। दाम कम होने से भी कारोबार ज्यादा होगा।

कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ब्लॉक एवं मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक पुराने कांग्रेस भवन गांधी मैदान में आयोजित की गई। बैठक

- मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत गांव-गांव पहुंचेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता

को प्रदेश कांग्रेस महामंत्री एवं मनरेगा बचाओ समिति के सदस्य अमरजीत चावला ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा, आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यकर्ताओं की एकजुटता और सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे कहा, वर्तमान में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का सहयोग सराहनीय है, जिससे आने वाले समय में सकारात्मक और निर्णायक परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। कार्यकर्ताओं ने संगठनात्मक गतिविधियों को और तेज करने का संकल्प लिया गया। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत गांव-गांव पहुंचकर श्रमिकों से संपर्क करना है। जहां मनरेगा का काम चल रहा है, वहां जाएं और जहां नहीं चल रहा, वहां भी जाकर मुद्दे उठाएं।

जमीनी स्तर पर जाएंगे : बैज

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं से कहा, हम जमीनी स्तर पर जाएंगे और कांग्रेस के रीति-नीति एवं विचारों को जन-जन तक पहुंचाएंगे। रायपुर जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमें पूरे प्रयास से आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस का यह कदम संगठन में निष्क्रियता तोड़ने और पुराने ढांचे में नई सक्रियता लाने की कोशिश है।

कांग्रेस नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी

कांग्रेस संगठन आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दे रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, जनता के सीधे संपर्क में रहने वाले नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी की जा रही है। इसे कांग्रेस की जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। संगठनात्मक बैठक में ऐसे नेताओं को विशेष दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, जो पहले ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं।

हथकरघा तैयार कर रहा 60 लाख यूनिफार्म

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग के सभी सरकारी स्कूलों में भी नए शिक्षा सत्र से कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चे अब नई यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे। सफेद शर्ट और

- कक्षा 8वीं तक रायपुर-बस्तर, दुर्ग संभाग के स्कूलों में भी बच्चे अब नई यूनिफॉर्म में दिखेंगे

नीला पेंट की जगह अब कत्थे रंग की पेंट और ब्लू रंग की चेक शर्ट यूनिफॉर्म बनाई गई है। यह यूनिफॉर्म काफी आकर्षक है। इस तरह की यूनिफॉर्म अब तक निजी स्कूलों के बच्चे पहनते हैं, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं भी इस आकर्षक यूनिफॉर्म को पहन पाएंगे। इस यूनिफॉर्म को तैयार करने का ठेका छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विपणन सहकारी संघ को दिया गया है। इस नई यूनिफॉर्म का वितरण प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले वितरण करना है, जिसके लिए युद्धस्तर पर हथकरघा संघ भी यूनिफॉर्म तैयार कराने में जुटा हुआ है।

329 समितियां तैयार कर रही यूनिफॉर्म

अधिकारियों ने बताया कि हथकरघा संघ के अंतर्गत बुनकरों की पंजीकृत 329 समितियां हैं। इन सभी समितियों के माध्यम से ही यूनिफॉर्म तैयार कराया जा रहा है। सभी समितियां दिन-रात इस काम में जुटी हुई है।

बेस्ट क्वालिटी, कीमत भी कम

यूनिफॉर्म को तैयार करने में यूज किया जा रहा कपड़ा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। गर्मी के दिनों में बच्चों को यूनिफॉर्म से गर्मी का कम अहसास होगा। वैसे तो यूनिफॉर्म बच्चों को निःशुल्क वितरण किया जाएगा, लेकिन इसकी कीमत भी बहुत कम प्रति सेट 299 रुपए है, जो कपड़े की क्वालिटी की तुलना में कीमत बहुत कम है। एक बच्चे को दो सेट यूनिफॉर्म निःशुल्क दिया जाएगा।

सरगुजा-बिलासपुर में पहले से लागू

कत्थे रंग की पेंट और ब्लू रंग की चेक शर्ट यूनिफॉर्म को पहले ही सरगुजा और बिलासपुर संभाग के सभी प्रायमरी एवं मीडिल सरकारी स्कूलों में लागू किया जा चुका है। इन दोनों संभाग के बाद अब इस यूनिफॉर्म को रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग अंतर्गत सभी जिलों के स्कूलों में भी लागू किया जा रहा है।

60 लाख यूनिफॉर्म किए जा रहे तैयार

प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले करीब 60 लाख छात्र-छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म हथकरघा तैयार कर रहा है। हथकरघा संघ के अधिकारियों ने बताया कि ऑर्डर के अनुसार अब तक लगभग 50 प्रतिशत यूनिफॉर्म तैयार कर लिए गए हैं, वहीं शेष यूनिफॉर्म भी मार्च तक तैयार हो जाएंगे।

स्कूल शुरू होने से पहले सप्लाई

नए शिक्षा सत्र के लिए प्रदेशभर के कक्षा पहली से आठवीं तक स्कूलों के लिए 60 लाख सेट नई यूनिफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। इसकी सप्लाई स्कूल शुरू होने से पहले कर दी जाएगी। 50 प्रतिशत से अधिक यूनिफॉर्म सेट तैयार कर लिए गए हैं, शेष भी जल्द कर लिए जाएंगे।

- एमएम जोशी, सचिव, राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित

सबसे अधिक वेटिंग पटना की ओर जाने वाली ट्रेनों में, दुर्ग और निजामुद्दीन के बीच एक होली स्पेशल ट्रेन की सुविधा

होली में घर जाने ट्रेनें होने लगीं पैक, पटना से गुजरात तक ट्रवेटिंग, दिल्ली और मुंबई जाने अभी सीट उपलब्ध

हरिभूमि न्यूज ⏭ रायपुर

होली का पर्व नजदीक आते ही ट्रेनों की में बुकिंग तेजी आ चुकी है। रायपुर से महानगरों की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में ऑनलाइन कन्फर्म सीट बुक हो चुकी है, जिसके बाद कई ट्रेनों में अब वेटिंग शुरू हो गई है। वर्तमान में सबसे अधिक वेटिंग पटना की ओर जाने वाली ट्रेनों में दिखाई दे रही है, जिसके बाद रायपुर से गुजरात व हावड़ा जाने वाली ट्रेनों में है। बात दें कि होली में बड़ी संख्या में लोग जयपुर, मथुरा भी जाते हैं। इस वजह से दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस और छत्तीसगढ़ में वेटिंग की संख्या अभी से स्लीपर में 50 तक पहुंच चुकी है, वहीं थर्ड एसी में 30 तक है। आने वाले समय में यह संख्या तेजी से बढ़ेगी। बात दें कि रायपुर से दिल्ली, भोपाल, हैदराबाद और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में अभी प्रयाप्त सीटें उपल्बध हैं। इसकी बुकिंग में तेजी फिलहॉल नहीं है। इन ट्रेनों में वेटिंग बढ़ने के बाद रेलवे होली स्पेशल ट्रेनों चलाने का फैसला ले सकता है।

बिहार, यूपी की तीन ट्रेनों में वेटिंग 80 के पार

होली को लेकर 1 से 2 मार्च के बीच बिहार और यूपी जाने वाले तीन ट्रेनों में वेटिंग स्लीपर में 80 के पास पहुंच गया है। सारनाथ में स्लीपर में वेटिंग 81 है तो वही थर्ड एसी में 41 है। साउथ बिहार में 62 व बरौनी एक्सप्रेस में 20 तक है। सारनाथ में यात्रियों का दबाव इस होली में ज्यादा रहेगा। यह ट्रेन छत्तीसगढ़ से होकर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश से होकर बिहार जाती है।

हावड़ा रूट की ट्रेनों में वेटिंग

रायपुर हावड़ा रूट की ओर जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग शुरू हो चुकी है। शालीमार एक्सप्रेस के स्लीपर में 9 वेटिंग है, तो वही आजाद हिंद एक्सप्रेस में 18 है। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में स्लीपर में 27 है। पुरी अहमदाबाद में 60 के पार पहुंच गई है। बता दें कि दिल्ली, मुंबई और भोपाल जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग शुरू नहीं हुई है। इसमें 200 से अधिक सीटे खाली है।

दुर्ग-निजामुद्दीन के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, मिलेंगी कन्फर्म बर्थ

होली के त्यौहार पर ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। त्यौहार के दौरान कन्फर्म बर्थ और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग और निजामुद्दीन के बीच एक होली स्पेशल ट्रेन (08751/08752) चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दो-दो फेरे लगाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। इस ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जिसमें जनरल, स्लीपर और एसी कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। रेलवे द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 08751 दुर्ग-निजामुद्दीन होली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 1 और 2 मार्च 2026 को दुर्ग से सुबह 10.45 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन रायपुर 11.20 बजे पहुंचकर 5 मिनट बाद छूटेगी और उसलापुर दोपहर 1.20 बजे पहुंचेगी। इसके बाद पेंड्रारोड, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया होते हुए शाम 7.30 बजे कटनी मुड़वारा पहुंचेगी। रात के सफर में यह ट्रेन दमोह, सागर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी, आगरा कैंट और मथुरा होते हुए अगले दिन सुबह 11.10 बजे निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी।

बिलासपुर
सोमवार 2 फरवरी 2026
फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा
वर्ष : 25, अंक : 311
पृष्ठ : 8+8+6 = 22 मूल्य : 5.00***

मौसम
अधि. 31.5
न्यून. 17.4

हरिभूमि

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा व दिल्ली से एक साथ प्रकाशित

समाचार ही नहीं, विचार भी

haribhoomi.com

5 रणजी ट्रॉफीः विदर्भ और आंध्र ने क्वार्टर फाइनल में बनाई ...

विचार पेज
2 विकसित भारत के लिए सुधारों का बजट

भाजपा सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की जनता दरबार शैली में हुई समीक्षा

नारायणपुर में हरिभूमि-आईएनएच का जिला संवाद बना जवाबदेही का मंच

सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की देखने को मिली सक्रिय भागीदारी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| नारायणपुर

हरिभूमि एवं आईएनएच के संयुक्त तत्वावधान में 31 जनवरी को नारायणपुर स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित जिला संवाद कार्यक्रम लोकतांत्रिक विमर्श, जवाबदेही और विकास की जमीनी तस्वीर सामने लाने का सशक्त मंच बनकर उभरा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल की जनता दरबार शैली में समीक्षा की गई, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

कार्यक्रम में बस्तर सांसद महेश कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि बस्तर अब निर्णायक बदलाव के दौर में है और नक्सल मुक्त बस्तर आने वाले समय में देश के लिए एक नजीर बनेगा। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित कर उनके योगदान की सराहना की। जिला संवाद के विभिन्न सत्रों का संचालन स्टेट ब्यूरो हेड शैलेश पांडे, एंकर नदीम और नारायणपुर जिला ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान खान ने किया। संवाद के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क-बिजली-पानी, सुरक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित चर्चा हुई।

योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य

कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष संध्या पवार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की है। वहीं विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश दीवान, पूर्व जिला अध्यक्ष देवनाथ उसेंडी और छात्र नेता विजय सलाम ने एक के बाद एक सवाल उठाकर सत्ता पक्ष से जवाबदेही तय करने का प्रयास किया।

उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया

सामाजिक क्षेत्र से रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी व्याप्तानंद महाराज, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी संजय नंदी सहित अन्य वक्ताओं ने शिक्षा, सेवा और सामाजिक समरसता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास तथा निर्वाचन से जुड़े विभागों में उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यूनिट एजीएम निलेश द्विवेदी, हरिभूमि जिला ब्यूरो चीफ शेख महमूद, विभिन्न समाज प्रमुखों और नगर के सैकड़ों गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही।

केवल बहस नहीं, बल्कि समाधान आधारित संवाद को बढ़ावा देना है

कार्यक्रम के आयोजन में गुरुनानक ऑटो और दर्शनम ने सह-प्रायोजक के रूप में, जबकि मालक ट्रक यूनियन और निक्को जायसवाल, छोटेडोंगर ने प्रमुख प्रायोजक के रूप में सहभागिता निभाई। आयोजकों के अनुसार जिला संवाद का उद्देश्य केवल बहस नहीं, बल्कि समाधान आधारित संवाद को बढ़ावा देना है। नारायणपुर में आयोजित यह कार्यक्रम संवाद, विकास और सहभागिता की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में देखा जा रहा है।

बस्तर की खनिज संपदा आम आदिवासी परिवारों के लिए समृद्धि का माध्यम

जिला संवाद का एक प्रमुख आकर्षण रहा मालक ट्रक यूनियन के जिला अध्यक्ष किशोर आर्य का वक्तव्य। उन्होंने मंच से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में बस्तर की खनिज संपदा आम आदिवासी परिवारों के लिए समृद्धि का माध्यम बन रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिन घरों में कभी साइकिल तक नहीं हुआ करती थी, आज वही परिवार लाखों रुपए कीमत के ट्रकों के मालिक बन चुके हैं।

ट्रंप का दावा, बोले- हमारी डील हो गई है

हिंदुस्तान अब ईरान से नहीं वेनेजुएला से खरीदेगा तेल

एजेंसी ▶▶| वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक अहम बयान देते हुए कहा कि भारत अब ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका दुनिया के कई देशों पर अपने ऊर्जा स्रोत बदलने का दबाव बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात वॉशिंगटन से फ्लोरिडा जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, ट्रंप ने कहा, 'हम इस पर पहले ही एक समझौता कर चुके हैं, कम से कम इस सौदे की रूपरेखा तो तय हो ही चुकी है।' उनके इस बयान से साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच ऊर्जा को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है।

बयान के मायने : यह बयान ऐसे समय पर आया है जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने भारत को संकेत दिया था कि वह जल्द ही वेनेजुएला से दोबारा तेल खरीद सकता है।

लाया गया जोधपुर एम्स

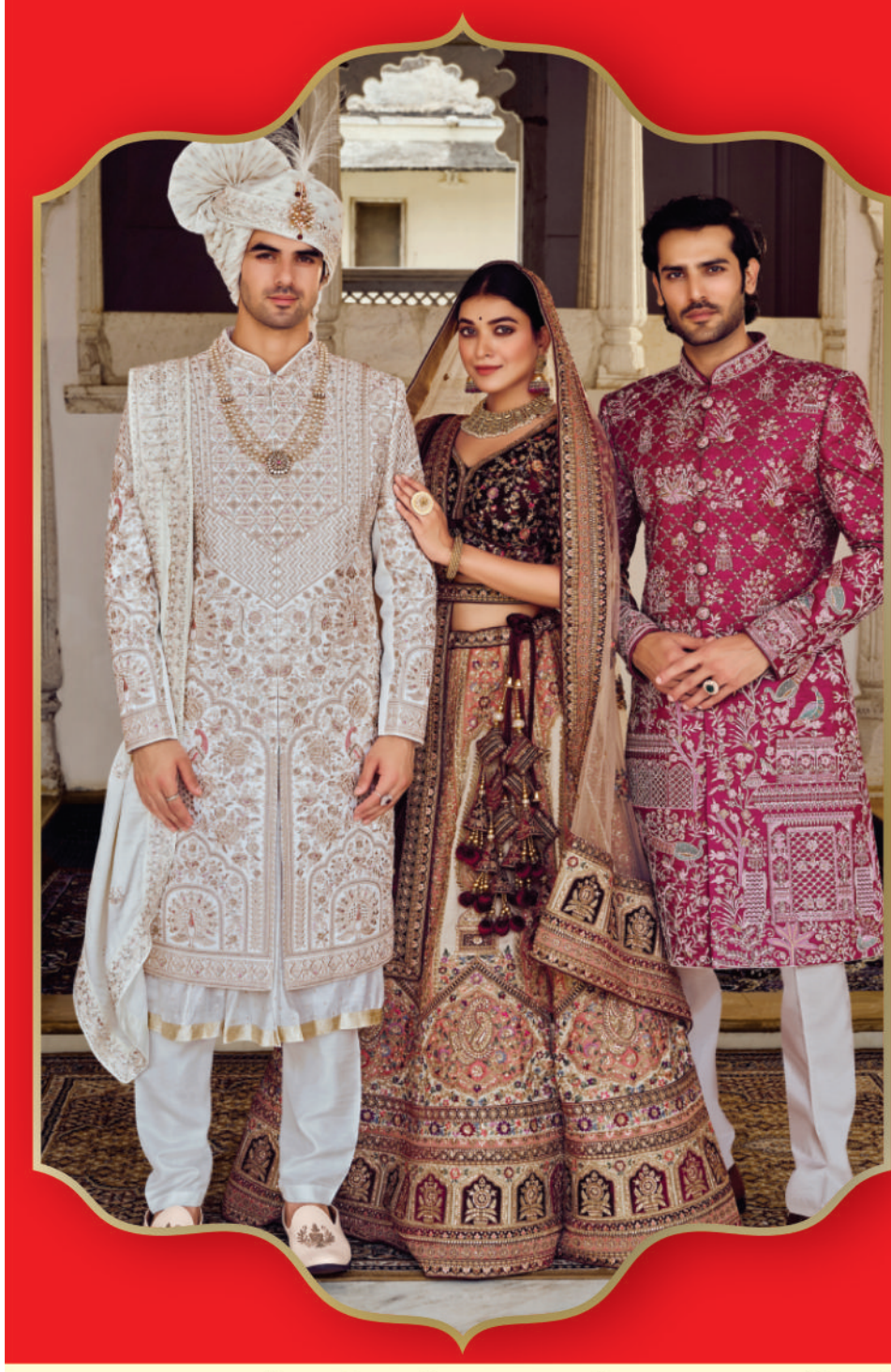

सेंट्रल जेल में बंद एक्टिविस्ट वांगचुक की बिगड़ी तबीयत

एजेंसी ▶▶| जोधपुर

एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट सोनम वांगचुक की जेल में तबीयत खराब हो गई है। वांगचुक को शनिवार (31 जनवरी, 2026) सुबह मेडिकल जांच के लिए जोधपुर केंद्रीय जेल से एम्स जोधपुर ले जाया गया। वह 27 सितंबर 2025 से जेल में बंद हैं।

अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। अस्पताल में उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में करीब डेढ़ घंटा बिताया। जिसके बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। एम्स के सूत्रों ने बताया कि सोनम वांगचुक पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं। इसी वजह से वह एक दिन पहले, शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को भी जांच के लिए अस्पताल आए थे। सुप्रीम कोर्ट इस समय सोनम वांगचुक की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट 2 फरवरी तक पेश करने को कहा है।

चिंतन

आम बजट में भविष्य की तस्वीर दिखाई

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया आम बजट 2026 एक ऐसा आर्थिक दस्तावेज़ है, जो भारत को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने की स्पष्ट मंशा दिखाता है। यह बजट विकासोन्मुखी,दीर्घकालिक सोच, रणनीतिक मजबूती और वैश्विक चुनौतियों के प्रति सजगता का परिचायक है, लेकिन साथ ही यह आम आदमी की तात्कालिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने में कमजोर भी नजर आता है। कहा जा सकता है कि यह बजट "कल" की तैयारी करता है, पर "आज" की परेशानियों को पूरी तरह संबोधित नहीं करता। वित्त मंत्री ने 85 मिनट के लंबे भाषण में अर्थव्यवस्था, भू-राजनीति, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर विस्तार से बात की, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का बदलाव न होना यह संकेत देता है कि सरकार फिलहाल वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक निवेश को प्राथमिकता दे रही है। टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने जैसे सुधार स्वागत योग्य हैं, मगर बढ़ती महंगाई के दौर में आम करदाता को इससे सीमित ही राहत मिलेगी। बजट का सबसे मजबूत पक्ष रक्षा क्षेत्र है। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पेश हुए पहले बजट में सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। रक्षा बजट को 6.81 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपये करना और आधुनिकीकरण व हथियार खरीद पर पूंजीगत खर्च में करीब 15% की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि सरकार सेना को तकनीकी और रणनीतिक रूप से और सक्षम बनाना चाहती है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम है, हालांकि सामाजिक क्षेत्रों में इसी अनुपात में खर्च न बढ़ना सवाल भी खड़े करता है। अर्थव्यवस्था को बाहरी दबावों से बचाने के प्रयास बजट में साफ झलकते हैं। वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, ट्रंप-युग की टैरिफ मानसिकता और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं में तनाव के बीच निर्यात प्रोत्साहन पर जोर दिया है। कपड़ा, चमड़ा, फिशरीज और दालों के निर्यात को बढ़ावा देने के कदम ग्रामीण और अर्ध-शहरी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक साबित हो सकते हैं। इससे रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बनेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में नए अस्पतालों की घोषणा, दवाओं को सस्ता करने की पहल और 17 कैंसर मेडिसिन को ड्यूटी फ्री करना आमजन के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। आयुर्वेदिक एम्स जैसी घोषणाएं भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आधुनिक ढांचे से जोड़ने की कोशिश मानी जा सकती हैं। शिक्षा और युवाओं पर केंद्रित योजनाएं बजट का एक और उल्लेखनीय पहलू हैं। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की योजना डिजिटल इंडिया और क्रिएटर इकोनॉमी की दिशा में कदम है। साथ ही करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की घोषणा सामाजिक समावेशन और महिला शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बजट चुनावी लोकलुभावन घोषणाओं से दूर नजर आता है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों के बावजूद किसी सीधे चुनावी लाभ वाली घोषणा का अभाव बताता है कि सरकार फिलहाल दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। कुल मिलाकर आम बजट 2026 एक विज़न डॉक्यूमेंट है जो भविष्य की तस्वीर दिखाता है। यह बजट लोगों को संतुष्ट कर सकता है जो मजबूत रक्षा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देते हैं।

विश्लेषण
डॉ .जयंतीलाल भंडारी

विकसित भारत के लिए सुधारों का बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तस्वीर में यह उभरकर दिखाई दे रहा है कि यह बजट आम आदमी के लिए राहत और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत सुधारों की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए तीन कर्तव्यों पर आधारित किया है। इनमें उत्पादकता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना, लोगों की आशंकाओं को पूरा करने के लिए क्षमता निर्माण और सबका साथ, सबके विकास के मद्देनजर ढांचागत सुधार के साथ प्रगति करना शामिल है।

इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित किए गए हैं। यद्यपि बजट के तहत इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाना सुनिश्चित करके आयकर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और आयकर भरना आसान किया गया है। बजट के नए प्रावधानों से बुनियादी ढांचा, छोटे शहर, एमएसएमई, शिक्षा, पर्यटन और सर्विस सेक्टर जैसे क्षेत्रों में नई पीढ़ी के लिए रोजगार के व्यापक मौके बढ़ेंगे। खास बात यह भी है कि आगामी वर्ष के बजट के तहत वित्त मंत्री राहत और विकास के बीच सूझबूझ पूर्ण संतुलन बनाते हुए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 फीसदी के स्तर पर सीमित रखने और सात फीसदी से अधिक विकास दर पाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं। गौरतलब है कि नए बजट के तहत वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में धीमेपन के बीच अगली पीढ़ी के सुधार, नीतिगत स्थिरता व दीर्घकालीन विकास की रणनीति के साथ घरेलू मांग की मजबूती पर्यावरण नवाचार, उद्यमिता बुनियादी ढांचा, कृषि विकास, गरीब, युवा, महिला और किसान वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र रक्षा, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) स्वदेशी प्रोत्साहन और हरित ऊर्जा पर बड़े ऐलान किए हैं। इनके साथ-साथ भारत को वैश्विक बायो फॉर्मा केंद्र बनाने, शहरी आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण, नए राष्ट्रीय जल मार्ग, सात हाई स्पीड कोरिडोर, व्यापार सुगमता, कंटेनर निर्माण, बुजुर्गों के लिए मजबूत इकोसिस्टम, टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के विकास के लिए प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, वित्त मंत्री के समक्ष बजट तैयार करते समय चुनौतियां भी रही हैं। इन चुनौतियों में रुपये में लगातार गिरावट, अमेरिका का ऊंचा टैरिफ, मैन्युफैक्चरिंग व कृषि की धीमी रफ्तार शामिल हैं। निसंदेह वित्त मंत्री बजट के तहत गरीब, युवा, महिलाएं, किसानों के कल्याण के नए उपायों के साथ विकास योजनाओं पर भी अपने आवंटन को बढ़ाते हुए दिखाई दी हैं। बजट में रोजगार, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा वेयरहाउसिंग संबंधी प्रोत्साहन, रियल एस्टेट सेक्टर और आवास सेक्टर को प्रोत्साहन, डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने तथा स्वच्छ ऊर्जा के लिए अधिक आवंटन करते हुए दिखाई दी हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि इस बजट में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निवेश, रेलवे, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार और

क्षमता संवर्धन के साथ दीर्घावधि वृद्धि, वैश्विक क्षमता निर्माण और एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मिशन मोड के सुधार उभरकर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बजट के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, उद्योग जगत की लाजिस्टिक्स लागत घटाने, रोजगार सृजित करने वाले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने संबंधी रणनीतियां भी दिखाई दी हैं। युवाओं के रोजगार बढ़ाने, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने, प्रधानमंत्री कौशल मुद्रा योजना, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन को बेहतर करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। सीतारमण बजट में खाद्य महंगाई पर काबू पाने के लिए भी आपूर्ति संबंधी नए कदमों के साथ आगे बढ़ी हैं। बजट में वित्त मंत्री ने रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य रखकर नए रोजगार अवसरों को निर्मित करने की रणनीति भी अपनाई है। विकसित भारत के लक्ष्य के मद्देनजर डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन के प्रावधान भी बजट में दिखाई दे रहे हैं। नए बजट में हर क्षेत्र में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को अहमियत हेतु प्रावधान किए गए हैं, ताकि भारत एआई का वैश्विक हब बन सके। सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए भी बजट में अधिक धन का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बजट में भारत को दुनिया के बाजार में और अधिक प्रभावी रूप से जुड़ने और भारत को निर्यात का नया हब बनाने के लिए नई रणनीति प्रस्तुत की है।

भारत को यूरोपीय संघ समेत विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के बाद दुनिया के बाजार में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के प्रोत्साहनमूलक प्रावधानों के साथ आगे बढ़ी हैं। अमेरिका के द्वारा लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ से प्रभावित निर्यात क्षेत्रों को भी राहत देने के मद्देनजर वित्त मंत्री नए निर्यात प्रोत्साहनों की डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दी हैं।निश्चित रूप से वित्त मंत्री ने इस बजट में सीमा शुल्क के लिए जहाँ राहत दी है, वहीं सीमा शुल्क में सुधार भी किए है। यह बजट इसलिए भी खास रहा है, क्योंकि यह बजट पुराने टैक्स युग से नए टैक्स युग की दहलीज पर खड़ा बजट है। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से करीब 60 साल पुराने टैक्स कानून की जगह नया इनकम टैक्स कानून लागू किया है। इससे देश के करोड़ों आयकरदाता लाभांवित होंगे। साथ ही नई श्रम संहिताएं भी आगामी वित्तीय वर्ष में लागू होने से श्रम उत्पादकता बढ़ेगी और औद्योगिक विकास का नया अध्याय दिखाई देगा। निश्चित रूप से वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा एक फरवरी को प्रस्तुत आगामी वित्त वर्ष 2026-27 का प्रस्तुत बजट कोई साधारण वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट देश के आर्थिक परिदृश्य को ऐतिहासिक मोड़ देने वाला बजट है। इस बजट से जहां देश में साहसिक सुधारों का नया युग शुरू हो सकेगा, वहीं आम आदमी के लिए अधिक राहत और देश के लिए तेज विकास का नया परिदृश्य निर्मित होगा।

उम्मीद करें कि एक ओर वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 के बजट के बजट के लक्ष्य के तहत राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3 फीसदी तक रखने में कामयाब होगी। उम्मीद करें कि इस अभूतपूर्व बजट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और यह बजट देश को वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला और 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखने वाला बजट सिद्ध होगा।

(लेखक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

> वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की तस्वीर में यह उभरकर दिखाई दे रहा है कि यह आम आदमी के लिए राहत और विकसित भारत के लिए साहसिक सुधारों को आगे बढ़ाने वाला ऐतिहासिक बजट है। यद्यपि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एक अप्रैल से नया आयकर अधिनियम लागू किया जाना सुनिश्चित करके आयकर संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया है और आयकर भरना आसान किया गया है। इस बजट से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और यह बजट देश को वर्ष 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला और 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखने वाला बजट सिद्ध होगा।

आम बजट
प्रमोद भार्गव

आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट

नए आम बजट से उम्मीद की जा रही थी कि यह आयकर की सारिणी में छूट और पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकलुभावन बजट होगा, लेकिन यह बजट इसके विपरीत आत्मनिर्भरता के लिए उद्योग केंद्रित बजट है। इसके स्थाई और रोजगार देने वाले परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा। इस बजट की उम्मीदों में तमाम आर्थिक उथल-पुथल और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद अगले वित्त वर्ष में भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की बुनियाद रख दी है। इस समय भारत उद्योग,प्रौद्योगिकी और दवाओं के कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है, किंतु यह बजट कालांतर में चीन को चुनौती बनने वाला है। इस बजट में दुर्लभ खनिजों के उत्खनन को बढ़ावा देने के द्वार खोले जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ खनिज के साथ कृषि भी है। अतएव ईयू से जो संधि हुई है, उसके तहत भारत को स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, पेपर, ग्लास, तेल रिफाइनरी और खाद के निर्यात का लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से भारत भूमि को कुदरत ने अटूट प्राकृतिक संपदा दी हुई है। इस संपदा का उत्खनन और उसका उपयोग देश के लोगों के लिए हो, इस नजरिए से दुर्लभ खनिजों के उत्खनन के लिए बजट में ओडिशा, केरल और आंध्रप्रदेश के बीच गलियारा बनाए जाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग भी बनाए जाएंगे। साथ ही वस्त्र, खेलकूद सामग्री,जैविक दवाओं,कंटेनर, इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। रसायन पार्क विकसित होंगे। सेमीकंडक्टर मिशन दो की शुरुआत की जाएगी। चूंकि सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के उपाय निरंतर कर रही है, इस हेतु सेमीकंडक्टर की उपलब्धता जरूरी है। इस दृष्टि से यह उत्पादन और निर्माण के ढांचागत विकास को स्थापित करने का महाबजट है। दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा हेतु संसद के मॉनसून सत्र में माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। इस नए कानून से व्यवसायियों को लीज पर खनन करने के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लीथियम, कोबाल्ट, निकल, हीरा जैसे दुर्लभ खनिजों के उत्खनन की सुविधा भी मिल गई है। भारत इन खनिजों के लिए अब तक चीन पर निर्भर था, लेकिन चीन ने इनके निर्यात पर रोक लगा दी थी। यही वे खनिज हैं, जो क्वांटम कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी और अंतरिक्ष उपकरणों में काम आते हैं। हालांकि ट्रंप द्वारा लगाए गए अनर्गल टैरिफ के बाद चीन ने भारत को उपरोक्त खनिज देने का वादा किया हुआ है। ईयू से समझौते के बाद दुर्लभ खनिजों के आयात-निर्यात का दायरा विस्तृत हो गया है। इसीलिए भारत अब अपनी शर्तों पर विकसित देशों के साथ व्यापार भी करेगा। अब माइंस और मिनरल्स संशोधन विधेयक पारित हो जाने से उद्योगपति निवेश के लिए आगे आएंगे। मध्यप्रदेश की धरती हीरा और सोना तो उगलती ही है, तांबे और चूने का यहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कटनी में चूने के भंडार हैं। शडहोल और उमरिया में कोयला एवं बॉक्साइड, छिंदवाड़ा में कोयला, बैतूल में ग्रेफाइड और सतना में सिमेंट के भंडार भरे पड़े हैं। मध्यप्रदेश में ईंधन खनन के लिए 12 क्षेत्र चिन्हित किए हैं। कोयला आधारित 37 प्रतिशत मीथेन का उत्पादन प्रदेश में हो रहा है। जबलपुर में सोने के नए भंडार मिले हैं। ग्रेफाइट सहित 30 दुर्लभ खनिज तत्वों की खोज की गई है। इनके उत्खनन व प्रसंस्करण के बाद लीथियम और लौह अयस्क के लिए सीधी में एक क्षेत्र चिन्हित कर दिया गया है। इसके अलावा बजट में जैविक औषधीय दवाओं के उत्पादन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है। बायोफार्मा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा। सरकार आयुर्वेद दवाओं के निर्माण को बढ़ावा देगी। इन दवाओं का निर्माण इसलिए जरूरी है, क्योंकि ये रोग को जड़ से दूर करती हैं। सात द्रुत गति के रेल गलियारे बनेंगे। पटना और वाराणसी में जहाजों की मरम्मत के कारखाने खुलेंगे। छोटे नगरों में तीर्थस्थल विकसित होंगे। इस उपाय से छोटे नगरों में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। इससे स्थानीय लोगों को धर्म संबंधी रोजगार मिलेंगे। एक जिला,एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया गया है। साफ है यह बजट अन्य आम बजटों से एकदम अलग है। इसमें मतदाता को लुभाने और आयकरदाताओं को संतुष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह युवाओं की आत्मनिर्भरता और रोजगार के लिए उद्योग केंद्रित बजट है, जिसके स्थाई और फलदायी परिणाम धीमी गति से आएंगे। जो देश की अर्थव्यवस्था को न केवल मजबूती देंगे, बल्कि देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम करेंगे।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

योग के सभी सूत्र सुदृढ़ जीवन की आधारशिला

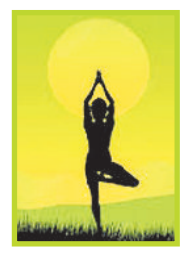

संकलित
दर्शन

योग प्राचीन काल से भारतीय आध्यात्मिक संचेतना का केंद्र रहा है। इसके आदिम सूत्रधार परमयोगी भगवान शिव हैं। योग शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता रहा है। समाधि अर्थ में इसका प्रयोग आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए किया जाता है, जब साधक अपनी साधना की चरमावस्था में परमात्मा से एकाकार होकर उसका साक्षात्कार कर लेता है। अग्निपुराण में भी मन एवं आत्मा तथा आत्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा गया। सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष का भेद होने पर भी पुरुष का आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना योग कहलाता है। कठोपनिषद् के अनुसार, जब इंद्रियां मन के साथ और मन अविचल बुद्धि के साथ स्थिर हो जाता है तो यह अवस्था योग की होती है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने 'योगः कर्मसु कौशलम्' कहकर योग का जो स्वरूप अजरुन के समक्ष प्रस्तुत किया है वह सामान्य जन के सर्वाधिक निकट है। कोई भी मनुष्य एकाग्रचित्त होकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए योग को सिद्ध कर सकता है। योगसूत्र के प्रणोता महर्षि पतंजलि संयमन अर्थ में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उनके अनुसार यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा आदि आठ अंगों से संपन्न प्राणायाम की विविध क्रियाएं योग कहलाती हैं। इससे चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। बुद्धि में स्थिरता आती है। चिंतन उत्कृष्ट होता है। मन में सद्विचारों का उदय होता है। नकारात्मक प्रवृत्तियां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। परिणामतः आत्मिक और शारीरिक शक्तियों में वृद्धि होती है।

मन का भोजन हमारे विचार

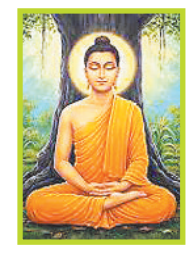

संकलित
प्रेरणा

एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों और अन्य लोगों को उपदेश दे रहे थे। सत्संग में काफी लोग बैठे हुए थे। भीड़ में से एक व्यक्ति उठा और उसने बुद्ध से पूछा कि तथागत मैं जब ध्यान करने बैठता हूं तो मेरा मन ध्यान में नहीं लग पाता है। कृपया बताइए, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध के साथ ही सत्संग में बैठे हुए लोगों ने भी ये प्रश्न सुना, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि कृपया फिर से अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, मैं ध्यान कैसे कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा कि एक बार और अपनी बात कहें। उस व्यक्ति ने एक बार और अपनी बात कह दी। बुद्ध ने कहा कि हमारे विचार मन के लिए भोजन हैं। जब तक मन को विचारों का भोजन मिलता रहेगा, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। जब हम ध्यान करने बैठे, तब मन को विचारों का भोजन नहीं देना चाहिए, यानी सोच-विचार करना बंद कर देना चाहिए। तब ही हम ध्यान कर पाएंगे। जब मन विचारों से खाली हो जाएगा, तब ही हम ध्यान कर पाएंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से ध्यान के बारे में प्रश्न तीन बार पूछा था और बुद्ध ने भी तीन बार इस प्रश्न का उत्तर दिया। बुद्ध ने तीन बार उत्तर दिया तो लोगों ने पूछा कि आपने इस व्यक्ति से तीन बार प्रश्न पूछा और उत्तर भी तीन बार ही दिया, ऐसा क्यों? बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मैं इन सज्जन से तीन बार प्रश्न पूछा, क्योंकि मैं प्रश्न के लिए इनकी गंभीरता को परखना चाहता था। जब मुझे लगा कि ये अपने प्रश्न के लिए गंभीर हैं, तब मैंने उत्तर भी तीन बार दिया, ताकि मेरी बात इन्हें अच्छी तरह समझ आ जाए।

थाईपुसम त्योहार

भगवान मुरुगन की जयंती के अवसर पर एक अपनी जीभ में सांग छेद कर थाईपुसम त्योहार में हिस्सा ले रहा है।

आज की पाती

उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करना जरूरी

विज्ञान ने हमें हर मौसम से बचने के लिए बहुत सी चीजें दी हैं। लेकिन अगर हम इनका सावधानी से प्रयोग न करें तो यह हमारे लिए कभी भी हानिकारक बन सकती हैं और अक्सर खबरें भी पढ़ने और सुनने को मिलती हैं कि इन चीजों के प्रयोग करते कई बार हादसा हो गया। सर्दियों में गैस गीजर, कोयले की अंगीठी और अन्य गर्मी प्रदान करने वाले उपकरण लोगों की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। सर्दियों के मौसम में नहाने के लिए लोग गैस से चलने वाले गीजर का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके प्रयोग में जरा सी भी असावधानी किसी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। गैस गीजर को बाथरूम में लगाने के साथ-साथ एक खिडक्री जरूर रखें। लोगों को चाहिए कि जहां गैस गीजर लगा हो वहां हवा बाहर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए। - *संजय शर्मा, दुर्ग*

2 फरवरी पर विशेष

वेटलैंड

वेटलैंड जो अंग्रेजी का शब्द है के लिए हिंदी में अनेकानेक शब्दों का उपयोग देखने में आता है आर्द्र ,जलोध,नम,दलदली भूमि ये सभी शब्द एक ही मायने और अर्थ प्रकट करते हैं और इनकी उपस्थिति हमारे जैव मंडल के लिए अति आवश्यक है जिसमें जल चर थल घर,नभ चर समाहित हैं इन सभी की जीवन सुरक्षा में वेट लैंड की भूमिका महत्वपूर्ण है जिसका संरक्षण संवर्धन आवश्यक है इन उदाहरणों से समझा जा सकता है झील, ताल तलैया, पोखर, तालाब या वो सभी जल संग्रहण के केंद्र जहां पानी की गहराई 6 मीटर से ज्यादा न हो ये सभी स्थान वेटलैंड (नम भूमि) को इंगित करते हैं जो मिट्टी, पानी,जैव विविधता को पुष्ट कर जीव जगत को सुरक्षित जीवन प्रदान करते रहते हैं।

वेटलैंड प्राकृतिक रुप से जल शोधन का कार्य कर जल को साफ सुथरा कर पेयजल आपूर्ति कर अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं वहीं ये बाढ़ आने पर इसकी रोकथाम कर प्राकृतिक बफर बन ढाल का कार्य कर सभी की सुरक्षा करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में वेट लैंड अग्रणी भूमिका में हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु रक्षक का कार्य प्राकृतिक रुप से करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है आज जिस प्रकार से भी जलवायु परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसे संतुलित रखने में आद्र भूमि अपनी महती भूमिका निभाते दिखते हैं।

इनकी आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988 के अंतर्गत भारत शासन द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 लागू कर इसकी सुरक्षा को सर्वोपरि माना वहीं राज्य शासन द्वारा 17.12.2018 को राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन कर इसकी सुरक्षा हेतु कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का परिपालन सुनिश्चित किया एवं सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठन सुनिश्चित किया गया इस प्रकार के निर्णयों से ये बात तो स्पष्ट होती है कि शासकीय और गैर शासकीय सभी स्तरों पर वेटलैंड को संरक्षित संवर्धित करने की भावना बलवती होती जा रही है जो एक शुभ संकेत है इस प्रकार के नजरिए से हमारे नगरीय और ग्रामीण वेटलैंड को असमय हो रही मृत्यु से बचाया जा सकेगा साथ ही भू-जल स्तर जो तेजी से नीचे जा रहा है उसे भी बचाया जा सकेगा और अस्तित्व-सह अस्तित्व के भाव से समाज परिवार और प्रकृति के भाव सुरक्षित रह सकेंगे।

-*प्रभात मिश्र*

करंट अफेयर

इजराइल की रफाह सीमा क्रॉसिंग खोलने की घोषणा

इजराइल ने फलस्तीनियों के सीमित आवागमन के मद्देनजर गाजा की मिस्र के साथ रफाह सीमा क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद रफाह सीमा क्रॉसिंग पर रविवार को चहल-पहल देखी गयी। रफाह सीमा क्रॉसिंग को दोबारा खोलना इजराइल-हमास संघर्षविराम के आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल ने रविवार को घोषणा की कि रफाह क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोल दिया गया है। गाजा को मानवीय सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली इज़राइली सैन्य एजेंसी सीओजीएटी ने एक बयान में कहा कि क्रॉसिंग को पूर्ण संचालन के लिए सक्रिय रूप से तैयार किया जा रहा है और तैयारियां पूरी होने के बाद गाजा के निवासी यहां से आवागमन शुरू कर सकेंगे। मिस्र के एक अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि फलस्तीनी सुरक्षा अधिकारी मिस्र वाले द्वार से होकर क्रॉसिंग में दाखिल हुए और फलस्तीनी द्वार की ओर बढ़े, जहां वे एक यूरोपीय संघ मिशन के साथ जुड़ेंगे, जो प्रवेश और निकास की निगरानी करेगा। अधिकारी ने यह भी बताया कि एंबुलेंस भी मिस्र वाले द्वार से होकर गुजरीं।

ऑफ बीट

रात में पसीना आने के कई कारण हो सकते हैं

पसीना आना शरीर की शीतलन प्रणाली का एक सामान्य हिस्सा है, जो गर्मी छोड़ने और शरीर के इष्टतम तापमान को बनाए रखने में मदद करता है।

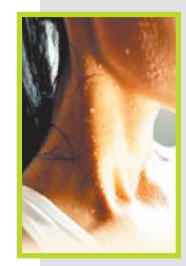

लेकिन नियमित रूप से रात में जागना, अत्यधिक पसीने से भीगना सही नहीं है। मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस, अंत :स्रावी तंत्र का हिस्सा है और शरीर के लिए तापमान नियंत्रण केंद्र है। इसमें तापमान सेंसर होते हैं जो केंद्रीय रूप से (अंगों में) और परिधीय रूप से त्वचा में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं (थर्मोरिसेप्टर्स) से जानकारी प्राप्त करते हैं। थर्मोरिसेप्टर्स शरीर के तापमान में बदलाव का पता लगाते हैं, हाइपोथैलेमस को वापस संकेत भेजते हैं। ये संकेत या तो शरीर को ठंडा करने के लिए पसीने को सक्रिय करेंगे या शरीर को गर्म करने के लिए कंपकंपी को सक्रिय करेंगे। उम्र या लिंग कोई भी हो, किसी को भी रात में पसीना आने का अनुभव हो सकता है। लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाओं को रात में पसीना अधिक आता है, इसका मुख्य कारण रजोनिवृत्ति और संबंधित बदलते हार्मोन स्तर हैं। ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रोजन के स्तर में बदलाव से नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो हाइपोथैलेमस में तापमान विनियमन को प्रभावित करते हैं।

खबर संक्षेप

मीशो का घाटा बढ़कर 491 करोड़ रुपए पर पहुंचा

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स कंपनी मीशो का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध घाटा बढ़कर 490.6 करोड़ रुपये हो गया। त्योहारी मौसम में खर्चे बढ़ जाने से घाटे में यह बढ़ोतरी हुई है। समान तिमाही में कंपनी को 37.43 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी ने बताया अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के वित्तीय नतीजों की जानकारी दी।

ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का मुनाफा 11 प्रतिशत घटा

मुंबई। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही में शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 11.39 प्रतिशत घटकर 70 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने पिछले साल इसी तिमाही में 79 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। हालांकि, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसका राजस्व 6.9 प्रतिशत बढ़कर 1,616 करोड़ रुपये हो गया।

अंबुजा सीमेंट का मुनाफा 86 प्रतिशत घटा

नई दिल्ली। अदाणी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही का शुद्ध लाभ 86.21 प्रतिशत घटकर 366.97 करोड़ रहा है। इसका कारण पिछले साल की इसी तिमाही में कर लाभ के कारण ऊंचा आधार होना था। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड ने पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2,662.97 करोड़ का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया था।

एसआईएस लि. को 138.37 करोड़ रुपए का घाटा

नई दिल्ली। सुरक्षा सेवाएं देने वाली कंपनी एसआईएस लि. को चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 138.37 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। मुख्य रूप से नई श्रम संहिता के कारण असाधारण खर्च के कारण कंपनी को नुकसान हुआ है। एक साल पहले 2024-25 की इसी तिमाही में कंपनी को 102.11 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।

रिलायंस पावर का लाभ 40% घटकर 25 करोड़

नई दिल्ली। रिलायंस पावर का वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 40 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के साथ 25.11 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने अपने वित्तीय परिणामों की जानकारी दी। रिलायंस पावर ने वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 41.95 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था। समीक्षाधीन तिमाही मे दौरान कंपनी की कुल आय घटकर 1,949.78 करोड़ रुपये रह गई जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 2,159.44 करोड़ रुपये थी।

निफ्टी 495 अंक टूटकर बंद हुआ

वायदा सौदों पर एसटीटी बढ़ाने से शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1,547 अंक लुढ़का

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

आम बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) से जुड़े प्रावधानों ने शेयर बाज़ार की धारणा को गहरी चोट पहुंचाई है। बजट के तुरंत बाद आई भारी बिकवाली के चलते शेयर बाज़ार से करीब 9.40 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। विश्लेषकों का मानना है कि एसटीटी से जुड़ी सख्ती और स्पष्ट राहत के अभाव ने निवेशकों, खासकर शॉर्ट-टर्म और हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को निराश किया।

बजट में सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से एसटीटी के दायरे और प्रभाव को लेकर जो संकेत दिए, उससे बाज़ार में लागत बढ़ने की आशंका गहराई। फ्यूचर के लिए एसटीटी को 0.025 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी कर दिया. वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एसटीटी 0.1 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 कर दिया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, एसटीटी में किसी भी तरह की वृद्धि या उसमें राहत न देना सीधे तौर पर ट्रेडिंग वॉल्यूम, खासकर डेरिवेटिव्स और इंट्रा-डे कारोबार को प्रभावित करता है। यही वजह रही कि बजट के बाद पहले ही सत्र में आक्रामक बिकवाली देखने को मिली।

एसटीटी बना गिरावट की बड़ी वजह

निवेशकों के 9.40 लाख करोड़ रुपये डूबे

एसबीआई में रही बड़ी गिरावट

बीएसई के शीर्ष 30 शेयरों में से टीसीएस, इंफोसिस, टाइटन और सनफार्मा के शेयरों को छोड़कर बाकी सभी 24 शेयरों में गिरावट आई है। सबसे ज्यादा एसबीआई के शेयर 6 फीसदी, अदाणी पोर्ट के शेयर 5.5 फीसदी और भेल के शेयर 5.36 फीसदी गिरे हैं। आईटीसी के शेयरों में भी 3 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। सिर्फ आईटी सेक्टर में तेजी है, बाकी सेक्टर रेड जोन में बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा गिरावट पीएसयू बैंक, मेटल और ऑटो सेक्टर में बड़ी गिरावट आई है।

आगे क्या?

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार एसटीटी पर स्पष्टीकरण या भविष्य में पुनर्विचार का संकेत देती है, तो बाजार की धारणा में सुधार आ सकता है। फिलहाल निवेशकों को सतर्क रहने और गुणवत्ता वाले शेयरों पर दीर्घकालिक नजर रखने की सलाह दी जा रही है।

सरकार का पक्ष और दीर्घकालिक तर्क

सरकार का कहना है कि बजट में राजकोषीय संतुलन बनाए रखना जरूरी है और एसटीटी जैसे कर बाजार से स्थिर राजस्व का स्रोत हैं। साथ ही सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स पर खर्च बढ़ाने का संकेत दिया है, जिससे दीर्घकाल में आर्थिक गतिविधियों और कॉरपोरेट मुनाफे को सहारा मिल सकता है।

ब्रोकरेज और एक्सचेंज शेयरों पर दबाव

एसटीटी से जुड़ी चिंताओं का असर ब्रोकरेज, एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों पर भी साफ दिखा। कारोबार घटने की आशंका से इन कंपनियों के शेयरों में औसत से कहीं ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

उतार-चढ़ाव बना रहेगा

बहरहाल, बजट में एसटीटी को लेकर उठे सवालों ने यह साफ कर दिया है कि शेयर बाजार केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि लेन-देन की लागत से भी गहराई से प्रभावित होता है। जब तक इस मोर्चे पर भरोसा बहाल नहीं होता, बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। सोमवार को बाजार के हालत पर इसकी संभावनाओं पर रविवार देर शाम तक विशेषज्ञों ने चुप्पी बनाए रखना ही ठीक समझा।

छोटे निवेशक और ट्रेडर सबसे ज्यादा प्रभावित

एसटीटी का बोझ सीधे हर सौदे पर पड़ता है, चाहे निवेशक को मुनाफा हो या नुकसान। इस कारण छोटे निवेशक, डे-ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा दबाव में आए। बाजार जानकारों का कहना है कि इससे इक्विटी बाजार की आकर्षण क्षमता घटती है और पूंजी का रुख दूसरे एसेट क्लास की ओर मुड़ सकता है।

सेबी ने एनएसई के आईपीओ लाने का रास्ता किया साफ

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

बाजार नियामक सेबी ने देश के सबसे बड़े शेयर बाजार एनएसई के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का रास्ता साफ करते हुए अपना अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है। एक्सचेंज के शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से मिली मंजूरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की एक दशक से लंबित योजना के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एनएसई ने लगभग 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए वर्ष 2016 में पहली बार मसौदा प्रस्ताव दाखिल किया था।

लेकिन संचालन से जुड़ी खामियों और को-लोकेशन विवाद से जुड़ी नियामक चिंताओं के चलते सेबी ने मंजूरी रोक दी थी। इसके बाद से एनएसई ने आईपीओ पर नियामकीय मंजूरी हासिल करने के लिए कई बार सेबी का दरवाजा खटखटाया था। एनएसई के चेयरपर्सन श्रीनिवास इन्जेटी ने कहा कि सेबी की अनापत्ति मिलना एक्सचेंज की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

- अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी
- देश के सबसे बड़े शेयर बाजार को होगा आईपीओ

उन्होंने कहा, 'सेबी की मंजूरी के साथ हम अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य सृजन के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। यह मंजूरी भारतीय अर्थव्यवस्था और पूंजी बाजारों में एनएसई की अहम भूमिका में विश्वास को भी मजबूत करती है।' सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने जनवरी की शुरुआत में कहा था कि अनुचित बाजार पहुंच मामले में निपटान की एनएसई की अर्जी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है।

एनएसई के 1.77 लाख शेयरधारक

प्रस्तावित आईपीओ भारतीय पूंजी बाजार के सबसे बड़े निर्गम में से एक हो सकता है। एनएसई के लगभग 1.77 लाख शेयरधारक हैं और इसका मूल्यांकन पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने पहले कहा था कि एनओसी मिलने के बाद मसौदा प्रस्ताव दाखिल करने की तैयारियां शुरू की जाएंगी।

उद्योग को ऋण 13.3 प्रतिशत की तेज गति से बढ़ाः आरबीआई

- पिछले वर्ष की इसी अवधि में 7 .5 प्रतिशत था

एजेंसी ⏭ मुंबई

उद्योग को बैंक ऋण दिसंबर, 2025 में 13.3 प्रतिशत की तेज गति से बढ़ा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 7.5 प्रतिशत था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।

आरबीआई ने कहा कि सालाना आधार पर 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त पखवाड़े तक गैर-खाद्य बैंक ऋण में 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल के समान पखवाड़े (27 दिसंबर 2024) में यह वृद्धि 11.1 प्रतिशत थी। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, सूक्ष्म और लघु'' उद्योगों को दिए गए ऋण में तेज वृद्धि देखी गई, जबकि ''मझोले'' उद्योगों में भी मजबूती बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, /"बड़े उद्योगों को ऋण भी बढ़ा।/"प्रमुख उद्योगों में ''बुनियादी ढांचा'', ''इंजीनियरिंग'', ''बुनियादी धातु और धातु उत्पाद'', ''रासायनिक और रासायनिक उत्पाद'', ''कपड़ा'' और ''पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन'' के बकाया ऋण में सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

बीओआई का शुद्ध मुनाफा 4.39 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) का दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध मुनाफा 4.39 प्रतिशत बढ़कर 5,443 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि, कम प्रावधान के कारण हुई। एकल आधार पर, बैंक शुद्ध मुनाफा बढ़कर 5,055 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 4,837 करोड़ रुपये था। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी, देबदत्त चंद ने बताया कि बैंक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 11-13 प्रतिशत ऋण वृद्धि मार्गदर्शन के ऊपरी स्तर को हासिल कर लेगा और इसे पार भी कर सकता है, और इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही तक शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को बढ़ाकर 2.90 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान गैर-ब्याज आय छह प्रतिशत बढ़कर 3,600 करोड़ रुपये हो गई।

बजाज ऑटो का लाभ 10% बढ़कर 2,750 करोड़

नई दिल्ली। बजाज ऑटो का वित्त वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2,750 करोड़ रुपये रहा है। बजाज ऑटो ने पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2,196 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। बजाज ऑटो ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी परिचालन आय बढ़कर 16,204 करोड़ रुपये गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 13,169 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने कहा कि तीसरी तिमाही में उसकी कुल बिक्री सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर 13,41,252 इकाई हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 12,24,472 इकाई थी।

रुपया कमजोर होने से बीते सप्ताह अधिकांश तेल के दाम मजबूत

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

विदेशों में खाद्य तेलों के दाम मजबूत होने, रुपये के मूल्य में आई गिरावट के कारण बीते सप्ताह देश के तेल-तिलहन बाजारों में सभी तेल-तिलहनों के दाम मजबूत बने रहे। बीते सप्ताह सरकार ने आयातित खाद्य तेलों के आयात शुल्क मूल्य में भी बदलाव किये हैं।

- विदेशों में खाद्य तेलों के दाम हुए मजबूत
- आयातित खाद्य तेलों के शुल्क में किए गए बदलाव

इस बदलाव के तहत कच्चा पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन तेल का आयात शुल्क मूल्य क्रमशः 14 रुपये और 29 रुपये क्विंटल घटाया गया है जबकि सोयाबीन डीगम का आयात शुल्क मूल्य 20 रुपये क्विंटल बढ़ाया गया है। सूत्रों ने कहा कि एक फरवरी को केन्द्रीय बजट से पहले तेल-तिलहन कारोबार के संबंध में किसी स्पष्ट दिशानिदेशों के अभाव में बाजार का कामकाज सुस्त बना रहा मगर विदेशों में आई तेजी के असर से स्थानीय तेल-तिलहनों के दाम मजबूत हो गये। बजट पेशकशों के बाद सोमवार के बाद बाजार की आगे की दिशा निर्धारित होगी। इस बीच अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया अपने निम्नतम स्तर के करीब मंडरा रहा है। इस वजह से खाद्य तेलों का आयात महंगा हो चला है जो खाद्य तेल कीमतों में तेजी का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा नवंबर-दिसंबर में देश में आयातकों द्वारा लागत से नीचे दाम पर सोयाबीन डीगम तेल की बिक्री की जा रही थी।

बाजार में सोयाबीन की आवक हुई कम

सूत्रों ने कहा कि किसान बाजार में सोयाबीन की आवक कम ला रहे हैं। विदेशों में इसके बाजार मजबूत हुए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया काफी कमजोर हुआ है। बाजार में आपूर्ति इतनी कम है कि सोयाबीन प्लांट पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं। जनवरी के महीने में सोयाबीन का आयात कम हुआ है और आयात के ऑर्डर को देखते हुए फरवरी में भी आयात कम होने के आसार नजर आ रहे हैं।

एक्साइड इंडस्ट्रीज का मुनाफा 23 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। बैटरी निर्माता कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज का 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही का एकीकृत शुद्ध मुनाफा 23 प्रतिशत बढ़कर 194.97 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी ने एक नियामकीय सूचना में यह जानकारी दी। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 158.44 करोड़ रुपये था। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की एकीकृत परिचालन आय 4,200.59 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 4,016.72 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसका कुल खर्च 3,922.81 करोड़ रुपये था, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 3,791.49 करोड़ रुपये था।

इको होटल्स एंड रिजॉर्ट्स अयोध्या में विकसित करेगी नया होटल

- राम जन्मभूमि मंदिर से सात किलोमीटर की दूरी पर होगा

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

इको होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड ने कहा कि उसने अयोध्या में एक नयी होटल संपत्ति विकसित करने के लिए रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के उच्च क्षमता वाले गंतव्यों में कंपनी की विस्तार योजनाओं के अनुरूप है।

- प्रस्तावित परियोजना में 33 कमरे होंगे

इस प्रस्तावित परियोजना में 33 कमरे होंगे। यह मुख्य राजमार्ग से सीधा जुड़ा होगा और राम जन्मभूमि मंदिर से सात किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस होटल को क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है।

एक करोड़ पर्यटक आने की संभावना : त्रिपाठी ने कहा, 'अनुमानों के अनुसार अयोध्या में प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ पर्यटकों के आने की संभावना है, जो इस बाजार की क्षमता को दर्शाता है।' अयोध्या में बनने वाला यह होटल भारत के रणनीतिक स्थानों पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने के इको होटल्स के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

अगले पांच वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपए परिव्यय का प्रस्ताव

भारत वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में होगा विकसित

हरिभूमि न्यूज ⏭ नई दिल्ली

केन्द्रीय बजट 2026-27 में सात रणनीतिक और अग्रिम क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करने पर जोर दिया गया है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम बजट में 'पहला कर्तव्य' के तहत छह क्षेत्रों का हिस्सा होगा।

भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय बजट में अगले पांच वर्षों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'बायोफार्मा शक्ति' का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रस्ताव से बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के

इलेक्ट्रॉनिकी कल-पुर्जा निर्माण का परिव्यय बढाकर 40 हजार करोड़

सेमीकंडक्टर मिशन 2-0 शुरू करने का प्रस्ताव

देश के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमता में विस्तार करने और भारत सेमीकंडक्टर मिशन (1.0) को आधार मानकर केन्द्रीय बजट में उपकरण एवं सामग्री निर्माण, भारतीय आईपी का पूरी तरह से डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन (2.0) शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। सीतारमण ने कहा कि प्रौद्योगिकी और कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए सरकार का ध्यान उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्रों पर रहेगा।

घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ावा

घरेलू रसायन उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने चैलेंज रूट के जरिए क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल पर तीन रसायन पार्कों की स्थापना में राज्यों को मदद करने के लिए एक योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि मजबूत पूंजीगत वस्तु सामर्थ्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता का निर्धारक है। केन्द्रीय बजट में दो स्थानों पर उच्च प्रौद्योगिकी टूल रूम स्थापित किए जाएंगे।

घरेलू उत्पादन के लिए उचित प्रणाली का निर्माण होगा।

सात मौजूदा संस्थानों का अपग्रेडेशन

इसके लिए बजट में अभिकल्पित कार्यनीति में तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के साथ बायोफार्मा केन्द्रित नेटवर्क और सात मौजूदा संस्थानों का अपग्रेडेशन शामिल है। इसमें एक हजार से अधिक प्रत्यायित भारत क्लीनिकल ट्रायल्स केन्द्रों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। केन्द्रीय बजट में वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन को मजबूत करने और एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा कैडर तथा विशेषज्ञों के जरिए समय से अनुमोदन के लिए प्रस्ताव किया गया है।

प्रथम पृष्ठ का शेष

छत्तीसगढ़ में पहली...

परामर्श केंद्र में आने वाली शिकायतों पर गौर किया गया, तो पाया गया कि ज्यादातर पति अपनी पत्नी के दूसरे मर्दों से अवैध संबंध या फिर पत्नी द्वारा पति और ससुराल वालों से गाली गलौज और मारपीट करने को लेकर प्रताड़ित हैं। काउंसलिंग में अधिकतर का यही कहना है कि वो पत्नी को साथ तो रखना चाहते हैं, लेकिन तभी जब पत्नी एक आदर्श पत्नी की तरह उनके साथ रहे।

दो दिनों में...

पतासाजी के लिए सी सी टी वी फुटेज देख कर पीड़ति ग्रामीणों के बयान के आधार पर एक युवको की ग्रुप को चिन्हकित किया गया। इस दौरान सीसी टीवी में 3 बाईक मे 9 युवक हुडदंग करते दिखे। पुलिस ने बाइक के आधार पर आरोपियो की तलाश की और राहौद सबरिया डेरा से 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की। जिसमे 2 नाबालिग भी शामिल थे। गिरोह का सरगना रामनाथ गोड़ फरार हो गया था और ग्राम बोड़सरा में छुप गया था। मुख्य आरोपी रामनाथ के सबरीया डेरा बोड़सरा में छुपे होने की सूचना पर पुलिस टीम ने रविवार 1 फरवरी की सुबह करीब 5 बजे घेराबंदी शुरू की। इस बीच आरोपी को भी सूचना मिलने पर वह भागने की फिराक में पुलिस टीम पर देशी कट्टे से फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में शिवरीनारायण थाना प्रभारी राजेश श्रीवास्तव ने भी दो राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली आरोपी पैर पर लगी। आरोपी रामनाथ देशी ने कट्टा को छोड़ कर पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। घायल होने पर उसे जिला अस्पताल जांजगीर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं अन्य आरोपियों को धारा 296, 351(3), 109 (1), 309 (2), 3(5) बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, स्टील का 4 राड, 2 डंडा, 3 बाइक, 1 स्कूटी, लूटे गए 3 मोबाईल, 9 हजार रुपए नकद रकम जब्त कर कुल 4 लाख 9 हजार रुपए की संपत्ति बरामद की है।

दो की हालत...

भर्ती हैं। वहीं दीपक कुमार कश्यप निवासी बोईदा, प्रशांत कश्यप निवासी बोईदा,अनिकेत राय सागर निवासी कचंदा के सिर में चोट है। कचंदा निवासी आर्यन और सुमित बंजारे भी घायल हुए हैं। इसी तरह कैलाश दास मानिकपुरी ग्राम सोनसरी थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर, बसंत दास ग्राम खोखरी थाना शिवरीनारायण, शुभम यादव निवासी बारगांव थाना पामगढ़, संजीव कुर्रे ग्राम भवतरा थाना शिवरीनारायण, आशीष वानी निवासी बारगांव थाना पामगढ़, सुखनंदन कश्यप निवासी सेंद्री थाना पामगढ़, लक्ष्मण यादव ग्राम कचंदा थाना शिवरीनारायण भी इस गिरोह का शिकार हुए है।

सिगरेट-कमर्शियल सिलेंडर...

अभी नई अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) घोषित नहीं की है, लेकिन वितरक पुराने स्टॉक की बिलिंग खुदरा विक्रेताओं को 40 प्रतिशत जीएसटी के साथ कर रहे हैं। रविवार को थोक बाजार बंद रहने के कारण व्यापारियों को उम्मीद है कि सोमवार से नई कीमतों वाला नया माल बाजार में आएगा। लोकप्रिय मध्यम श्रेणी की सिगरेट 'विल्स नेवी कट', जिसकी कीमत पहले 95 रुपये प्रति पैकेट थी, अब करीब 120 रुपये प्रति पैकेट हो सकती है। इसी तरह, 84 मिलीमीटर लंबाई वाली सिगरेट जैसे 'गोल्ड फ्लेक लाइट्स', 'विल्स क्लासिक' और 'विल्स क्लासिक माइल्ड्स', जिनकी कीमत पहले 170 रुपए प्रति पैकेट थी, अब 220 से 225 रुपए प्रति पैकेट तक हो सकती है। वहीं, पतली सिगरेट 'क्लासिक कनेक्ट', जो 20 सिगरेट के पैकेट में 300 रुपए की मिलती थी, अब लगभग 350 रुपए की हो सकती है। व्यापारियों का कहना है कि महीने के अंत तक कंपनियां नई कीमतों वाले पैकेट बाजार में भेज देंगी।

समिति प्रबंधक ने किया साढ़े सात सौ कट्टा धान का हेरफेर

हरिभूमि न्यूज : रायपुर

उरला थाने में धरसींवा विकासखंड, कुम्हरी कृषि शाखा सहकारी समिति के प्राधिकृत अधिकारी जागेश्वर वर्मा ने समिति प्रबंधक के खिलाफ साढ़े सात सौ कट्टा धान का हेरफेर कर सात लाख रुपए से ज्यादा रकम की गड़बड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। समिति प्रबंधक ने जिस किसान के खाते में धान बिक्री चढ़ाई थी।

■ उरला थाने में समिति प्रबंधक पर अपराध दर्ज

प्राधिकृत अधिकारी ने उन दोनों किसानों तथा कंप्यूटर ऑपरेटर के बयान के आधार पर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जागेश्वर वर्मा ने कृष्णा साहू के खिलाफ गड़बड़ी करने की थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्राधिकृत अधिकारी ने पुलिस को बताया कि किसानों की धान बिक्री की रिपोर्ट उनके आधार का सत्यापित कर ऑनलाइन एंट्री की जाती है। इसके बाद किसानों को उनके द्वारा बेचे गए धान की रकम का भुगतान ऑनलाइन संबंधित बैंकों द्वारा कर दिया जाता है। कृष्णा ने आलोक शर्मा के 104 कट्टा धान की एंट्री करते हुए धान बिक्री की रकम किसान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। समिति प्रबंधक ने उक्त रकम 21 जनवरी को फर्जी तरीके से किसान के नाम धान बिक्री दर्शाकर ट्रांसफर की थी।

शराब दुकानों के 50 कर्मियों को दो माह से सैलरी नहीं

हरिभूमि न्यूज : रायपुर

शराब दुकान में काम करने वाले कर्मी हर स्तर पर शोषण का शिकार हो रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी बीआईएस शराब दुकान कर्मियों से जुर्माना वसूलने से लेकर अनुपस्थित रहने पर सैलरी में से भारी-भरकम राशि काट रही हैं। दिसंबर से लेकर जनवरी तक 50 शराब दुकान कर्मियों की मैनुअल अटेंडेंस का भुगतान नहीं किया गया है। इसके चलते शराब दुकान कर्मियों में आक्रोश है। शराब दुकान कर्मियों ने बताया है कि विरोध करने पर प्लेसमेंट एजेंसी कर्मियों को निकालने तथा ब्लैक लिस्टेड करने की धमकी देते हैं। इसके चलते शराब दुकान के कर्मचारी शोषण का शिकार होने पर भी विरोध नहीं कर पा रहे।

प्लेसमेंट एजेंसी बीआईएस से जुड़े विनय शर्मा के अनुसार, जिन कर्मियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस आईडी नहीं बना है। उनका मैनुअल अटेंडेंस लिया गया है। मैनुअल अटेंडेंस की कॉपी सीएसएमसीएल के पास भेजी गई है। सीएसएमसीएल के अफसरों द्वारा मैनुअल अटेंडेंस वाले कर्मियों की राशि अब तक स्वीकृत नहीं की गई है। इसके लिए वे विभाग के जिम्मेदारों को पत्र लिख चुके हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के जिम्मेदार के अनुसार,जिन कर्मियों की सैलरी रोकी गई है, सीएमसीएल से राशि स्वीकृत होने के बाद उन्हें दी जाएगी।

डेमेज चार्ज 1.36 करोड़

विनय शर्मा के अनुसार, पूर्व में जो 80 लाख रुपए डेमरेज चार्ज आबकारी विभाग ने उन पर लगाया है, उसकी राशि बढ़कर 1.36 करोड़ रुपए हो गई है। डेमरेज चार्ज के नाम पर शराब दुकान कर्मियों की सैलरी से राशि काटे जाने के सवाल पर श्री शर्मा ने बताया कि यह नियम शराब दुकान कर्मियों की सेवा-शर्त में लागू है। पूर्व में भी डेमरेज चार्ज लगाए जाने पर शराब दुकान कर्मियों की सैलरी से राशि काटी जाती थी। पूर्व में हर माह डेमरेज चार्ज लगाया जाता था। इस वजह से कर्मियों की सैलरी से राशि काटे जाने पर उन्हें ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं होता था।

डेमरेज चार्ज का गणित

किसी ब्रांड की शराब निर्माण तिथि के बाद से 180 दिन तक उपयोगी मानी जाती है। इसके बाद उस ब्रांड की शराब को एक्सपायरी मान लिया जाता है। ऐसे किसी ब्रांड की शराब दुकान में पहुंचने के बाद निश्चित तिथि तक शराब को बेचना होता है। संबंधित ब्रांड की शराब एक्सपायरी हो जाती है, ऐसे में आबकारी विभाग प्लेसमेंट एजेंसी पर शराब की कीमत निर्धारण कर जुर्माना लगाता है, जिसकी भरपाई प्लेसमेंट एजेंसी शराब दुकान कर्मियों से करती है।

अहलूवालिया हॉस्पिटल
8103128515, 0771-4050006
• कान, नाक, गला रोग • Hearing Aids • दंत रोग • मुख के कैंसर/प्लास्टिक सर्जरी • चक्कर, खर्राटे
नेमीचंद गली, रामसागर पारा, स्टेशन रोड रायपुर

डॉ. नरेन्द्र अग्रवाल
चर्म एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ
सुविधाएं: लेजर हेयर रिमूवल • केमिकल पीलिंग • हाइड्रोफेशियल • रेडियोफ्रिक्वेंसी • कार्बन फेशियल • एलर्जी टेस्ट
रविवार अवकाश
क्लीनिक : छत्तीसगढ़ कॉलेज के सामने, सिविल लाईन, बैरनबाजार, रायपुर (छ.ग.) समय : सुबह 10:00 से 2:00 बजे तक
सिटी कोतवाली के पास, छोटापारा रोड, रायपुर (छ.ग.) शाम 5:00 से 8:30 बजे तक, फोन : 0771-2546760, 9300323131

सभी प्रकार की एलर्जी • डेंटल सुविधा भी उपलब्ध..
• जैसे नाक • कान • गला • आंख • श्वास की (अस्थमा) • त्वचा
छाती रोग- • अस्थमा • सी.पी.ओ.डी. • फेफड़े सिकुड़ना
• पानी भरना • न्यूमोनिया • स्वाइन फ्लू • मोटापे • खर्राटे • छाती दर्द
50 बिस्तरों का सर्वसुविधायुक्त हॉस्पिटल
Vrinda Multispeciality Hospital — Chest & Allergy Centre
वृन्दा चेस्ट एंड एलर्जी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
अवंति बाई चौक, लोधीपारा, पंडरी रोड, कांपा, रायपुर (छ.ग.) संपर्क: 8962566221, 07714916125, 7223065604

मोतियाबिंद — आयुष्मान कार्ड सुविधा
SBH साईं बाबा नेत्र हॉस्पिटल
छोटी लाईन ब्रिज के पास, फाफाडीह, रायपुर 9644099925

अष्टविनायक हॉस्पिटल
बच्चों एवं महिलाओं का अस्पताल
• प्रसूति • नवजात • शिशु रोग • बांझपन • सोनोग्राफी • आयुष्मान कार्ड • बच्चों एवं बड़ों के आपरेशन • अनुभवी डॉक्टर्स प्रतिदिन
आमा सिवनी, विधानसभा रोड, रायपुर (छ.ग.), 9826182221, 9301744425

डायबिटिज मधुमेह का सर्वोत्तम इलाज - अब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई क्यू जाना
मधुमीत डायबिटिज हॉस्पिटल — डॉ राका शिवहरे MBBS, MD FNIC FIPA — भर्ती सुविधा उपलब्ध
Ecg, Echo, Tmt, Doppler, Carotid, Doppler, Insulin, Pump, Cgms, Homa IR
शिव मंदिर चौक, अवंति विहार, रायपुर, फोन : 0771-4060929, मो. 7389485756

HMS ARSH-RAHAT
आयुर्वेदिक हानिरहित बवासीर का दवा
अर्श-राहत
बवासीर की समस्त समस्याओं से 5 दिनों में छुटकारा दिलाता है व दुबारा होने से भी रोकता है।
आपरेशन के खर्च व तकलीफ से बचना चाहते है तो अर्श-राहत का इस्तेमाल करें
HMS देखकर खरीदें 94060-21769

JHAIGO झाईगो 5+1 Cream
चेहरे को दागों से मुक्त कर सुंदरता बढ़ाये...
तो फिर क्या.. बस इस बार झाईगो क्रीम उपयोग कर देखें।
क्या आपके... चेहरे पर झाईयां है? आंखो पर काले घेरे हैं?
चेहरे पर मुहाँसे के काले निशान है? या जले या चोट के निशान है?

epaper- www.haribhoomi.com
हरिभूमि Classified
Email- hbclassified375@gmail.com
आवश्यकता आपकी सुविधा हमारी
Contact For Advertisement Booking
Ring Road No.-2, Gourav Path, Bilaspur
Mo.- 9826782100

आवश्यकता है

आवश्यकता है- ढाबा में काम करने के लिए वेटर, हेल्पर, तन्दूर मास्टर, कैप्टन की अतिशीघ्र आवश्यकता है वेतन योग्यता अनुसार सम्पर्क करें- रायपुर रोड बिलासपुर 7000942962, 9098976666 (39819)

आवश्यकता है- थोक दवाई एजेन्सी में कार्य करने हेतु एकाउंटेंट, माल निकालने, पैकिंग हेतु लड़के, लड़कियां एवं ड्राइवर की आवश्यकता है इच्छुक सम्पर्क करें- गायत्री मेडिकल एजेन्सी, मेडिकल काम्पलेक्स, तेलीपारा बिलासपुर 9827122105 (39820)

आवश्यकता है- सेल्समैन, सेल्सगर्ल 4पद, फोल्डर 4पद, बिलिंग डिपार्टमेंट (पुरुष) 1पद की आवश्यकता है वेतन योग्यता अनुसार अनुभवी को प्राथमिकता बायोडाटा सहित सम्पर्क करें- शैल वस्त्रालय मेन रोड मसानगंज बिलासपुर 9238107105 (39821)

आवश्यकता है- होटल नटराज में काम करने के लिए अनुभवी हाउस कीपिंग एवं वेटर स्टाफ की आवश्यकता है वेतन योग्यता अनुसार सम्पर्क करें- होटल नटराज अग्रसेन चौक बिलासपुर 9977861508 (39813)

आवश्यकता है- होलसेल कपड़ा दुकान में काम करने हेतु कर्मचारी एवं टैली ऑपरेटर की आवश्यकता है वेतन योग्यता अनुसार। सम्पर्क करें- टूटेजा क्लॉथ सिंडिकेट, श्री राम क्लॉथ मार्केट, अग्रसेन चौक, बिलासपुर 9753000030 (39818)

आवश्यकता है- प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़े लिखे अनुभवी ड्राइवर की आवश्यकता है। वेतन - 15,000/- लाइसेंस के साथ संपर्क करें - 9755849255, 9406211101 (39804)

आवश्यकता है- पैकिंग कार्य एवं अन्य कार्य करने हेतु ,रहकर काम करने वाले हेल्पर लड़को की आवश्यकता है रूम बिजली की सुविधा फ्री है पता बंजारी मंदिर के पास रावाभाटा रायपुर 7828735534 (39785)

आवश्यकता है- प्यूनिफॉर्म टेक्समार्ट बिलासपुर में टेलर (दर्जी 8), डेटा एंट्री ऑपरेटर (2), मशीन ऑपरेटर प्रेस (2), हाउस कीपिंग (1 महिला, 1 पुरुष) की आवश्यकता है सम्पर्क करें- प्यूनिफॉर्म गार्डन के पास, R3 महामाया विहार, वेयर हाउस रोड, बिलासपुर 9111002777, 8711887744 (39817)

आवश्यकता है- बिलासपुर की रियल एस्टेट कम्पनी में आफिस एक्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। योग्यता (1) किसी भी विषय में स्नातक (2) रीयल एस्टेट में अनुभवी को प्राथमिकता (3) अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, वेतन योग्य उम्मीदवार हेतु कोई सीमा नहीं। सम्पर्क- 9630023355 (39811)

आवश्यकता है- बिलासपुर की Pvt. Ltd. कम्पनी को Manager, Service Manager, Marketing Manager, Counselor, Telecaller, वेल्डर, हेल्फर, फिल्ड ऑफिसर, सर्वेयर, ड्राइवर, ऑफिस ब्वाय (प्यून) की आवश्यकता है। वेतन 10000 - 35000 सम्पर्क करें- नारायण प्लाजा, बिलासपुर 9755990933, 6269222003 (39799)

आवश्यकता है- प्रो सोलर एनर्जी कम्पनी में प्रचार प्रसार हेतु लड़के चाहिए बिलासपुर कोटा, लोरमी, मुंगेली, बिल्हा, मस्तूरी, पथरिया, रतनपुर सैलरी 10000+ पेट्रोल 3000 पता- सीएलसी प्लाजा मंगला चौक बिलासपुर 8889580567, 9302158989 (39807)

आवश्यकता है- मिठाई एवं नास्ता बनाने के लिए हलवाई मिस्त्री एवं होटल में काम करने के लिए लड़के को आवश्यकता है सम्पर्क - यदुनन्दन नगर तिफरा बिलासपुर 9300521234 (39809)

आवश्यकता है- पुस्तकों के मार्केटिंग हेतु लड़के, लड़कियां चाहिए उम्र का कोई बंधन नहीं वेतन 8000 से 10000+ कमिशन पता- आदर्श लॉ हाउस डीपी कॉलेज के सामने पुराना हाईकोर्ट रोड बिलासपुर 9827079947 (39800)

आवश्यकता है- अनुभवी डेंटल असिस्टेंट (महिला) एवं वार्ड ब्वॉय की आवश्यकता है वेतन योग्यता अनुसार सम्पर्क करें- मार्क अस्पताल, गीता मैरिज हॉल के पास चांटीडीह रोड, सरकंडा, बिलासपुर 9827174705 (39797)

आवश्यकता है- विनोबा नगर में ऑटोमेटिक SUV कार हेतु अनुभवी ड्राइवर एवं महिला की देखभाल 24घंटे साथ में रहकर बिलासपुर में और बाहर भी जाने हेतु नर्स युवती चाहिए सम्पर्क करें- 7804000314 (39803)

आवश्यकता है- मकान में प्लास्टर मिस्त्री, टाइल्स लगाने हेतु मिस्त्री, बिजली ठेकेदार, छोटा हाथी चलाने हेतु ड्राइवर, दुकान कार्य हेतु मेहनती लड़का। पता- पारस सेल्स, मारुति शोरूम के पास, मोपका, बिलासपुर 9300350334 (39789)

आवश्यकता है- बेरोजगार युवा आज ही नौकरी पाइये पद- सिक्योरिटी गार्ड योग्यता-5वी से 12वीं पास,ग्रेजुएट भी मान्य सुविधा- रहने व खाने की व्यवस्था उपलब्ध वेतन - 9,500 से 18,000 प्रति माह लोकेशन- नया रायपुर,रायपुर, रायगढ़, आज ही कॉल करें और नौकरी पक्की करें 9201958117, 9201958118 (6547)

आवश्यकता है- रोजगार सूचना LIC एजेन्ट बनें शुरू करें स्वतंत्र केरियर असीमित आय, रॉयल्टी इनकम, गृह ऋण विदेश यात्रा आफिस अलाउन्स पार्ट/ फुल टाइम ग्रेजयुटी सुविधा 10वीं पास सम्पर्क अजयकुमार सिंह 9893311075 (39794)

आवश्यकता है- ज्वैलरी शोरूम में कार्य करने हेतु स्टाफ की आवश्यकता है। वेतन योग्यता अनुसार। बायोडाटा के साथ सम्पर्क करें- सराफ मनसुखलाल ज्वेलर्स, सदर बाजार बिलासपुर 9993251234, 9827108605 (39796)

आवश्यकता है-सुरक्षागार्ड, गनमैन, सुपरवाइजर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, फील्ड ऑफिसर कामवाली बाई। वेतन योग्यता अनुसार आवास फ्री। पता- श्रीसांई सिक्युरिटी सर्विस, सांई निवास कॉम्प्लेक्स, जेजे हॉस्पिटल के बाजू में तोरवा बिलासपुर 9301186703, 8253010291 (39669)

आवश्यकता है- सुरक्षा गार्ड वेतन 13000/- सुपरवाइजर वेतन 15000/- फील्ड अधिकारी वेतन 15000/- आवास मुफ्त, योग्यतानुसार वेतन सम्पर्क करें-अलर्ट एसजीएस प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय- 06 जे. शुक्ला कॉम्प्लेक्स पचपेड़ी नाका रायपुर 7747000016, 7746000016, 7746000019. (348)

आवश्यकता है- प्लाईवुड शोरूम में सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन, ऑफिस कार्य हेतु टेलीकॉलर शिक्षित, लड़के, लड़कियां चाहिए। वेतन 10000 से 50000+ बोनस+ कमीशन+ पेट्रोल, बाइक अनिवार्य। रिज्यूम व्हाट्स एप्प करें 9608777772, अनुभवी उम्मीदवार ही सम्पर्क करें- एस.एस. प्लाईवुड महाराणा प्रताप चौक बिलासपुर (561)

आवश्यकता है-आफिस, कम्प्यूटर कार्य हेतु अनुभवी आपरेटर, बागवानी कार्य हेतु मैनेजर, कार ड्राइवर, कुक, घरेलू कार्य, किराए के घर की देखभाल हेतु मैनेजर कोर्ट कचहरी हेतु मुंशी चाहिए मो- 8078280001 (39611)

आवश्यकता है- VPS में किराना समान बेचने समान सैल्स हेतु और बाज़ार से समान लाने ले जाने होमडिलीवरी , साफ़ सफ़ाई , समान तोलने , समान पैकिंग और अन्य सभी काम करने हेतु अनेकों कर्मचारी चाहिये जानकार व्यक्ति कृपया अपने अपने पूरे परिचयपत्र के साथ VPS में आकर के मिलें संपर्क VPS किराना दुकान VPS सुपर बाज़ार VPS पूजा समान भंडार VPS लघु उद्योग पता , वर्षा कॉम्प्लेक्स भाठागाँव रायपुर छत्तीसगढ़ VPS सेठ WHATSAPP नंबर , 8109199199 (0333)

आवश्यकता है- छत्तीसगढ़ से बाहर ऑफिस कार्य हेतु अविवाहित युवकों की अतिशीघ्र आवश्यकता है योग्यता, 10वी, 12वी, स्नातक, वेतन -12000+ कमिशन (रहना फ्री) ट्रेनिंग के बाद कमाए 20-25 हजार नोट नशेड़ी फ़ोन न करें मो. 9982589693 (527)

बेचना है

बेचना है- महाराणा प्रताप चौक के पास अज्ञेय नगर स्थित A सुपर डबल स्टोरी पूर्व मुखी मकान प्लाट साइज 2525 वर्गफुट प्राइम लोकेशन एक करोड़ 60लाख में बेचना है सम्पर्क करें- 9425540759 (39812)

बेचना है- बिलासपुर नगर निगम सकरी में टाऊन एण्ड कन्ट्री एप्रूव्ड विकसित प्लॉट मात्र 1290/- रूपए प्रति वर्गफुट 90% फाईनेंस। शर्तें लागू। साइट विजिट फ्री। सम्पर्क करें- 7987374690, 9770468361 (39791)

हमारा आशियाना
META PROPERTIES
3BHK VILLA & PLOTS AVAILABLE
VIP CITY, Saddu, Vidhan Sabha, Raipur, C.G.
812 000 8290

बेचना है- सरकंडा बिलासपुर सीपत चौक महामाया चौक से 250 मीटर अन्दर प्राइम लोकेशन हॉस्टल हब में बहुत ही शानदार डाइवर्टेड 1600 वर्गफुट जमीन मौके पर जमीन 2500 वर्गफुट है। बेचना है कीमत मात्र 3000/- वर्गफुट कृपया खरीददार ही सम्पर्क 9993865036 (39810)

बेचना है- बिलासपुर दोमुहानी नगर निगम वार्ड 43 आवासपारा के पास 25×45 1125 वर्गफुट चारों तरफ बाउंड्रीवॉल से घिरा सर्वसुविधायुक्त डायवर्टेड प्लाट बेचना है कीमत 760/- वर्गफुट खरीददार ही सम्पर्क करें 9827150471 (39788)

बेचना है- विकसित T&C एप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी आर.के. रेसीडेन्सी तिफरा में स्वतंत्र 3BHK मकान 80 लाख में बेचना है, 1900/1350 प्लाट/ बिल्टअप एरिया। सम्पर्क करें- 9300635493 (39752)

बेचना है- वाद्य एकार्डियन मेड इन इटली 120 बेस ऐन्टीक, एकार्डियन मेड इन जर्मनी 48 बेस पुरानी ट्वाय एकार्डियन पुरानी बेचना है। साथ ही ब्रांड न्यू XPS 10, 30, 60 रोलेण्ड की बोर्ड, साथ ही न्यू एवं ओल्ड गिटार बेचना है सम्पर्क करें- आशीर्वाद वैली, हाईकोर्ट रोड L-3-95 बिलासपुर 7803098408 (39815)

बेचना है- रामा लाइफ कॉलोनी सकरी बिलासपुर में स्थित 40×80= 3200 वर्गफुट का डायवर्टेड प्लॉट तत्काल बेचना है सम्पर्क करें- 9630990940 (1485)

बेचना है- श्यामा विहार कालोनी बोदरी परसदा नया बस स्टैण्ड के पास 22x50=1100 वर्गफीट डायवर्टेड प्लाट प्राईम लोकेशन में तत्काल बेचना है संपर्क करें 8839278711 (39798)

सूचना

पाठकों से अनुरोध है कि वे समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का कदम उठाने (पैसे भेजने, कोई भी खर्च उठाने, चिकित्सकीय सलाह, विवाह संबंधित) या किसी भी वादे-दावे पर अमल करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। पाठक पूर्ण जानकारी लेवें व स्वविवेक से निर्णय लेकर ही लेन देन करें। किसी भी उत्पाद या सेवाओं के संबंध में किए किसी भी विज्ञापनदाता के किसी प्रकार के दावों की हरिभूमि (प्रेस प्रबंधक व कर्मचारी) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। प्रकाशक, संपादक, कर्मचारी और हरिभूमि के स्वामी किसी विज्ञापन के संबंध में उठाए किसी कदम के नतीजे और विज्ञापन दाताओं के अपने वायदों पर खरा न उतरने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

Medicare Specialists
गुप्त रोगी स्वयं मिले
शादी से घबराहट गुप्त रोग
■ शीघ्र पतन से शारीरिक कमजोरी ■ शारीरिक एवं मानसिक नपुंसकता ■ लिंग में ढीलापन, छोटापन, पतलापन ■ लिंग में टेढ़ापन ■ वीर्य में शुक्राणु की कमी ■ बढ़ती उम्र में सेक्स की कमी ■ पेशाब में धातु जाना ■ शुगर से सेक्स में आई हुई कमजोरी
संपर्क जे.जे. अहमद दवाखाना
सरकारी आई.टी.आई. पॉवर हाउस अंबेडकर चौक, सी मार्ट के सामने बस स्टैण्ड, भिलाई
प्रतिदिन - सोम से शनि समय - 9 बजे से 5 बजे तक रविवार - 9 बजे से 2 बजे तक
9098889899
छोटा लिंग निराश क्यों? जोश जगा दे धूम मचा दे।
18 से 80 वर्ष तक लाभदायक लिंग को 8-9 ईन्च लम्बा मोटा, कठोर बनाये। सेक्स टाइम 30 से 45 मिनट बढ़ाये। नसों की कमजोरी नामर्दी, धातु का पतलापन, शुगर, बी.पी. में भी जबरदस्त लाभदायक। घर बैठे मंगवाये। लाभ नही तो पैसे वापिस।
8515825081 9083218330

हरिभूमि में लघु विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें

- जिला कार्यालय कोरबा:- बी.ब्लॉक, कॉमर्शियल काम्पलेक्स, ट्रांसपोर्ट नगर, जिला कोरबा (छ.ग.) मो. 9644018888, 7581808267
- जिला कार्यालय मुंगेली:- थाना के सामने गली, गोल बाजार, जिला- मुंगेली (छ.ग.) मो. 9303508230
- शिवम एड एजेंसी & पब्लिसिटी:- मो. 9993567380, 8770837744
- एड प्रयास:- मो. 9826701269, 9926003943
- श्यामनानी एडवरटाईजर्स:- मो. 9827168452, 9300625174
- रिद्धीसिद्धी एडवरटाइजर्स & पब्लिसिटी:- मो. 9826129386, 8319503386
- जे.जे. एडवरटाइजर्स:- मो. 9300659628
- भार्गव एडवरटाइजर्स:- मो. 9827167997
- श्रीसिद्धि विनायक एडवरटाइजर्स:- मो. 9826705603
- एम.जी.आर. एडवरटाइजर्स:- मो. 9827180896, 9131155033
- रौनक पब्लिसिटी:- मो. 9300328290, 9981658490
- श्री श्याम पब्लिसिटी:- मो. 9425540759
- अमित पब्लिकेशन:- मो. 9826304304, 9827124304
- विप्रा विज्ञापन सेवा:- मो. 9302462506
- माधवास & कम्पनी:- मो. 9977185123, 9893115084
- बालाजी एडवरटाइजर्स:- मो. 9827466133, 9907047586

रणजी ट्रॉफी: विदर्भ और आंध्र ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, झारखंड ने ओडिशा को हराया

एजेंसी ▶▶| नागपुर

गत चैंपियन विदर्भ ने उत्तर प्रदेश को चार विकेट से हराकर ग्रुप ए से आंध्र के साथ एलीट रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विदर्भ की टीम ग्रुप ए में आंध्र के बाद दूसरे स्थान पर रही। दोनों टीम ने सात मैच में समान 31 अंक हासिल किए लेकिन आंध्र की टीम बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर रही। उत्तर प्रदेश के 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विदर्भ की टीम ने चौथे और अंतिम दिन चार विकेट पर 91 रन से आगे खेलते हुए छह विकेट गंवाकर 58.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज अमन मोखाडे 150 गेंद में 83 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके मारे। दानिश मालेवार ने भी 54 रन की पारी खेली। उत्तर प्रदेश की तरफ से बाएं हाथ के स्पिनर शिवम शर्मा ने 55 रन देकर चार विकेट चटकाए। सोविमा में अपने अंतिम मैच में नगालैंड के खिलाफ ड्रॉ खेल आंध्र की टीम शीर्ष पर रही। नगालैंड ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 85 रन से आगे खेलते हुए 342 रन बनाए। चेतन बिष्ट ने 100 जबकि नगाहो चिषी ने 79 रन की पारी खेली। आंध्र को 173 रन का लक्ष्य मिला लेकिन टीम 8.3 ओवर में चार विकेट पर 64 रन बनाने के बाद मैच ड्रॉ कराने को राजी हो गई क्योंकि उसे तालिका के शीर्ष पर जगह दिलाने के लिए ड्रॉ काफी था।

तमिलनाडु और बड़ौदा का मैच ड्रॉ

ग्रुप ए के एक अन्य मैच में नॉकआउट की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके तमिलनाडु और बड़ौदा का मैच नीरस ड्रॉ रहा। तमिलनाडु ने अंतिम दिन सात विकेट पर 411 रन से आगे खेलते हुए 449 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज विमल कुमार 182 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। इसके जवाब में पहली पारी में 375 रन बनाने वाले बड़ौदा ने दूसरी पारी में शिवालिक शर्मा (नाबाद 59) और ज्योत्सनिल सिंह (नाबाद 55) के अर्धशतक से बिना विकेट खोए 124 रन बनाए। ग्रुप ए में ही जमशेदपुर में मेजबान झारखंड ने ओडिशा को चार विकेट से हराया। ओडिशा ने दूसरी पारी की शुरुआत आठ विकेट पर 202 रन से करते हुए मैच के अंतिम दिन 226 रन बनाए। झारखंड को 246 रन का लक्ष्य मिला, जो उसने 71.3 ओवर में छह विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज शरणदीप सिंह (64) और रोबिन मिन्ज (63) ने अर्धशतक जड़े जबकि अनुकूल रॉय (45) ने भी उम्दा पारी खेली।

जम्मू-कश्मीर ने मुंबई के साथ बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह

मुंबई। कप्तान आयुष दोसेजा की नाबाद 159 रन की पारी की बदौलत दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप डी में तालिका में शीर्ष पर काबिज मुंबई के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ करा लिया। इसी ग्रुप से जम्मू-कश्मीर ने भी 42 बार की चैंपियन मुंबई के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दोसेजा ने एमसीए-बीकेसी ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में 230 गेंदों में 11 चौकों और दो छक्कों की मदद से 159 रन बनाए और मुंबई को जीत से दूर रखा। दोनों टीमों ने चाय के विश्राम से करीब आधा घंटा पहले मुकाबला बराबरी पर समाप्त करने पर सहमति जता दी। दिल्ली ने दूसरी पारी छह विकेट पर 407 रन बनाकर घोषित की। उस समय उसकी कुल बढ़त 311 रन की थी। दिल्ली ने पहली पारी में 96 रन से पिछड़ने के बाद पिछले दो दिनों में मुंबई को कड़ी चुनौती दी। मुंबई ने सात मैचों में चार जीत और दो ड्रॉ से ग्रुप डी में 33 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया।

छत्तीसगढ़ और हैदराबाद का मैच ड्रा

छत्तीसगढ़ की टीम मेजबान हैदराबाद के खिलाफ अपनी दूसरी पारी में आठ विकेट पर 411 रन बनाकर 63 रन की बढ़त हासिल कर मैच ड्रॉ करने में सफल रही। हैदराबाद ने पहली पारी में 631 रन बनाने के बाद छत्तीसगढ़ को 283 रन पर आउट कर 348 रन की बड़ी बढ़त कायम की थी। पुडुचेरी ने इस बीच राजस्थान को पांच विकेट से शिकस्त दी। टीम ने आर श्रीराम के 57 और अजय रोहेरा के नाबाद 49 रन की पारी से जीत के लिए मिले 172 रन के लक्ष्य को पांच विकेट गंवा कर हासिल कर लिया।

खबर संक्षेप

महिला अंडर-17 टीम के सामने बांग्लादेश की चुनौती

पोखरा। भारतीय टीम सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के अपने दूसरे मुकाबले में सोमवार को जब पोखरा रंगशाला स्टेडियम में मजबूत बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश एक मैच शेष रहते फाइनल में जगह पक्की करने की होगी। इस साल के आखिर में चीन में होने वाले एएफसी अंडर-17 महिला एशियाई कप की तैयारियों में लगी पामेला कॉन्टी की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत मेजबान नेपाल के खिलाफ कड़े मुकाबले में 1-0 की जीत के साथ की थी। भारतीय टीम अगर इस मैच को जीतने में सफल रही तो फाइनल के लिए उसका दावा लगभग पक्का हो जाएगा। भारत को इससे पहले मेजबान नेपाल से कड़ी चुनौती मिली लेकिन पर्ल फर्नांडिस ने 49वें मिनट में गोल कर मैच में बड़ा अंतर पैदा किया।

जूनियर पुरुष स्कीट टी2 ट्रायल में पंजाब के निशानेबाज शीर्ष पर

नई दिल्ली। पंजाब के हरवीराज सिंह, हरजीज सिंह अटवाल और गुरफतेह सिंह संधू ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल कर शॉटगन राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स एक और दो में जूनियर पुरुष स्कीट टी2 के फाइनल में क्लीन स्वीप किया। अनंतजीत सिंह

नरूका ने पुरुष वर्ग के ट्रायल दो फाइनल में 36 में से 36 का परफेक्ट स्कोर कर ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया को एक अंक से पछाड़ते हुए खिताब जीता। यशस्वी राठौड़ ने महिला ट्रायल्स दो में सिर्फ एक निशाना चूकते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। क्वालीफिकेशन में 120 अंक के साथ शीर्ष पर रहने वाले अनंतजीत ने फाइनल में सटीक प्रदर्शन किया। ज्योतिरादित्य ने भी 34वें टारगेट तक परफेक्ट स्कोर बनाए रखा, लेकिन 35वें निशाने में चूकने के कारण 36 में से 35 अंक ही हासिल कर सके। अभय सिंह सेखों ने 30 निशाने के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

खिलाड़ियों को करना होगा दिनचर्या में बदलाव : सैंटनर

तिरुवनंतपुरम। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा कि उनकी टीम टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उपमहाद्वीप में अपने पिछले अनुभव और विभिन्न परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की अपनी

क्षमता पर भरोसा करेगी। न्यूजीलैंड ने सात फरवरी से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले भारत के खिलाफ तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। सैंटनर ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने हाल आईपीएल में या अपने करियर के दौरान चेन्नई में मैच खेले हैं। उन्होंने कहा, 'दिन का खेल थोड़ा अलग होने वाला है। खिलाड़ियों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। उन्हें थोड़ा जल्दी जागने की कोशिश करनी होगी। लेकिन फिर भी यह हमारे लिए एक नई चुनौती है।

22 साल के अल्कारेज ने एक सेट गंवाने के बाद की वापसी, जोकोविच को दी शिकस्त

अल्कारेज ने कम्पलीट किया कॅरियर स्लैम, तोड़ा जोकोविच का सपना, जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन

एजेंसी ▶▶| मेलबर्न

कार्लोस अल्कारेज रविवार को फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम करके कॅरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम- ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे कॅरियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

रिकॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच की मेलबर्न पार्क में फाइनल में यह पहली हार है। इससे पहले उन्होंने यहां अपने सभी 10 फाइनल में जीत दर्ज की थी। शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी अल्कारेज ने रविवार को पहला सेट गंवाया लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की। 22 साल के स्पेन के खिलाड़ी ने 38 साल के जोकोविच पर दबाव बनाए रखा।

कोच को गले लगाने दौड़े कार्लोस

जीत पक्की करने के बाद अल्कारेज ने हाथ से रैकेट छोड़ दिया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर गए और अपने हाथ सिर पर रख लिए। जोकोविच से हाथ मिलाने के लिए नेट पर जाने से पहले वह कुछ सेकेंड वहीं रुके। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ बातें कीं और जोकोविच स्पेन के खिलाड़ी को बधाई देते हुए मुस्कुराए। इसके बाद नया चैंपियन कोर्ट के एकतरफ लगी कुर्सियों पर बैठे अपने कोच को गले लगाने के लिए दौड़ा और बाद में स्टैंड में अपने पिता और टीम के दूसरे सदस्यों को भी गले लगा।

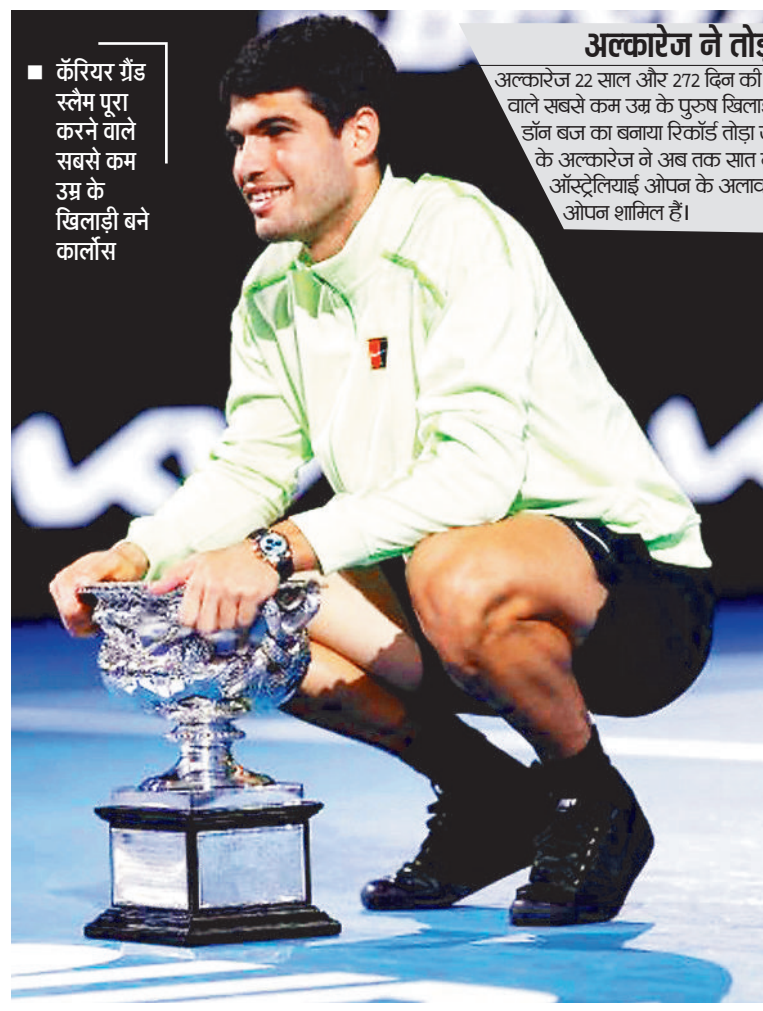

■ कॅरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने कार्लोस

अल्कारेज ने तोड़ा डॉन बज का रिकॉर्ड

अल्कारेज 22 साल और 272 दिन की उम्र में चारों ग्रैंडस्लैम का एकल खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बने। उन्होंने 1938 की फ्रेंच चैंपियनशिप में डॉन बज का बनाया रिकॉर्ड तोड़ा जब वह 22 साल और 363 दिन के थे। स्पेन के अल्कारेज ने अब तक सात ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन के अलावा दो-दो विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन शामिल हैं।

जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम पर अल्कारेज ने लगाई रोक

दोनों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पांच सेट में कड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों की तलाश में तीन घंटे से अधिक समय तक दोनों ने जबरदस्त फिटनेस, खेल और स्टेमिना का नजारा दिखाया। कोई भी खिलाड़ी बड़े अंकों पर हार मानने को तैयार नहीं था। स्पेन के खिलाड़ी ने 16 ब्रेक प्वाइंट में से पांच का फायदा उठाया जबकि जोकोविच छह ब्रेक प्वाइंट में से सिर्फ दो को ही अंक में बदल सके। जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब जीतने के अभियान पर एक बार फिर अल्कारेज और यानिक सिनर में से एक ने रोक लगाई। इन दोनों ने मिलकर पिछले नौ ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं। जोकोविच ने सेमीफाइनल में सिनर को हराया था और ओपन युगल में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनने की राह पर थे लेकिन अल्कारेज ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

आयरलैंड ने किया विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई

थाईलैंड को 62 रन से हराया

एजेंसी ▶▶| कीर्तिपुर

आयरलैंड ने ग्लोबल क्वालीफायर के सुपर सिक्स स्टेज में थाईलैंड को 62 रन से हराकर आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी जगह पक्की कर ली है। यह टूर्नामेंट इस साल जून-जुलाई के बीच खेला जाना है।

आयरलैंड ने इस स्टेज में खेले गए पांच मुकाबलों में से तीन में जीत हासिल की। इसी के साथ बांग्लादेश और नीदरलैंड के बाद क्वालीफायर से चुनी जाने वाली तीसरी टीम बन गई। आयरलैंड 2023 के बाद अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार को खेले गए इस मुकाबले में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए 8 विकेट खोकर 121 रन बनाए। इस टीम की तरफ से टॉप-3 बल्लेबाजों ने सर्वाधिक रन बनाए। एमी हंटर ने 24 रन और कप्तान गैबी लुईस ने 25 रन बनाए, जबकि ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने टीम के खाते में 24 रन का योगदान दिया। विपक्षी खेमे से सुलेपॉर्न लेओमी ने 24 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि सुनीदा चतुरोंगरताना ने 2 विकेट निकाले। एक सफलता ओनीचा कामचौम्फू के हाथ लगी।

59 रन पर सिमटी थाईलैंड

इसके जवाब में थाईलैंड की टीम 16.1 ओवरों में महज 59 रन पर सिमट गई। यह टीम 8 के स्कोर तक अपने 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से नन्नापत कोंचारोएनकाई (15) ने कप्तान नारुएमोल चायवाई (22) के साथ तीसरे विकेट के लिए 26 रन जुटाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस जोड़ी के टूटते ही थाईलैंड ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आलम ये रहा कि इस टीम के 9 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। आयरलैंड की तरफ से अर्लीन केली ने महज 7 रन देकर 4 विकेट हासिल किए, जबकि लारा मैकब्राइड ने 3 सफलताएं प्राप्त कीं।

स्क्वैश ऑन फायर

सबरीना को 3-1 से हराकर फाइनल में पहुंचीं अनाहत

एजेंसी ▶▶| वाशिंगटन

अनाहत सिंह ने वाशिंगटन में स्क्वैश ऑन फायर ओपन में अमेरिका की सबरीना सोमी को 3-1 से मात दी। इसी के साथ अनाहत ने पीएसए ब्रॉन्ज-लेवल इवेंट के अपने पहले फाइनल में जगह बना ली है। अनाहत सिंह ने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 23 सबरीना को 11-9, 11-3, 9-11, 11-5 से शिकस्त दी। खिताबी मुकाबले में 17 वर्षीय अनाहत का सामना टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 10 इंग्लैंड की जॉर्जीना कैनेडी से होगा। इससे पहले, शनिवार को अनाहत ने 0-2 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए नंबर 2 सीड सना इब्राहिम को शिकस्त देकर स्क्वैश ऑन फायर ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय वर्ल्ड नंबर 31 और सातवीं सीड खिलाड़ी ने मैच में वापसी करते हुए, तीसरे और चौथे गेम दोनों में 6-5 के घाटे को पलट दिया, और पीएसए ब्रॉन्ज-लेवल इवेंट में मिस्र की वर्ल्ड नंबर 17 सना इब्राहिम को 8-11, 8-11, 11-7, 11-8, 11-7 से मात दी थी।

पीएसए टूर में बनाई अलग पहचान

अनाहत ने इस सीजन पीएसए टूर पर अपनी अलग पहचान बना ली है। खासतौर पर अक्टूबर में सिल्वर-लेवल कैनेडियन विमेंस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचकर उन्होंने सभी का ध्यान खींचा था, जिसके बाद वह जल्द ही विश्व की टॉप-30 खिलाड़ियों में शामिल हो गईं। पिछले कुछ महीनों में अनाहत शानदार फॉर्म में रही हैं।

बल्लेबाजी में बदलाव से मिली फॉर्म में वापसी में मदद: सूर्यकुमार

तिरुवनंतपुरम। भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के बाद मिले ब्रेक और बल्लेबाजी में किए गए कुछ बदलाव से उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मदद मिली। सूर्यकुमार ने शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड पर भारत की 4-1 से जीत में आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए कुछ उम्दा पारियां खेली। सूर्यकुमार पिछले साल रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। वह इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए थे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करके न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाए और उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के बाद सूर्यकुमार ने आत्मचिंतन किया और अपने खेल में कुछ बदलाव किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार पारियों में वह केवल 34 रन बनाए थे, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 12 रन था। सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत की 46 रन से जीत के बाद कहा, 'दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के बाद मुझे ब्रेक मिला। मैंने घर लौटने पर अपना किट बैग एक तरफ रखा और नौ-दस दिन तक आराम किया।'

वेस्टइंडीज ने द.अफ्रीका को हराया, सीरीज की अपने नाम

एजेंसी ▶▶| बजोहानिसबर्ग

वेस्टइंडीज ने बारिश से प्रभावित तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुइस पद्धति के आधार पर छह रन से हराकर विश्व कप से पहले मनोबल बढ़ाने वाली जीत दर्ज की। पहले दोनों मैच जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह से तीन मैच की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की।

बारिश के कारण मैच लगभग दो घंटे देर से शुरू हुआ और इसे दोनों टीमों के लिए 16-16 ओवरों का कर दिया गया। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जब छह ओवर में एक विकेट पर 66 रन बनाए थे तभी बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा और बाद में इसे दोनों टीमों के लिए 10-10 ओवरों का कर दिया गया।

होप और हेटमायर ने जड़े 10 छक्के

वेस्टइंडीज ने तीन विकेट पर 114 रन बनाए। उसकी तरफ से कप्तान शाई होप ने 25 गेंदों में 48 रन और शिमरोन हेटमायर ने 22 गेंदों में नाबाद 48 रन का योगदान दिया। इन दोनों ने मिलकर 10 छक्के जड़े। दक्षिण अफ्रीका को डकवर्थ लुईस पद्धति से 125 रन का लक्ष्य मिला लेकिन उसकी टीम छह विकेट पर 118 रन ही बना पाई। क्विंटन डीकॉक ने 14 गेंद पर 28 और जेसन स्मिथ ने 10 गेंद पर 26 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से गुडाकेश मोती ने 17 रन देकर तीन विकेट लिए। भारत और श्रीलंका में हो रहे विश्व कप में वेस्टइंडीज शनिवार को कोलकाता में स्कॉटलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। दक्षिण अफ्रीका इसके दो दिन बाद अहमदाबाद में कनाडा के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

देविका ने जीता अपना पहला सुपर 300 खिताब

एजेंसी ▶▶| बैंकॉक

युवा शटलर देविका सिहाग ने 250,000 डॉलर इनामी थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीता।

हरियाणा की रहने वाली 20 वर्षीय खिलाड़ी देविका तब 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी, जब विश्व में 68वें नंबर की खिलाड़ी और दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह ने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इससे भारतीय खिलाड़ी अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने में सफल रही।

देविका के लिए फाइनल रहा शानदार

देविका के लिए फाइनल शानदार रहा लेकिन उनकी प्रतिद्वंदी गोह को पीड़ा झेलनी पड़ी। वह फाइनल से पहले तीन गेम तक चले चार मैच खेलने के बाद थकी हुई लग रही थीं और उन्हें कोर्ट को कवर करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पिछले दो वर्षों से फॉर्म और फिटनेस के लिए संघर्ष कर रही गोह ने शनिवार को भी थकान की शिकायत की थी और उन्हें कोर्ट में चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी। उनका बायां पैर हिल नहीं पा रहा था और वह लगातार परेशान दिख रही थीं। देविका ने फाइनल में शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपने दमदार रिटर्न और बेहतरीन स्ट्रोक के दम पर 4-0 की बढ़त बना ली।

मलेशियाई खिलाड़ी लग रही थीं थकी हुई

मलेशियाई खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी के खेल को समझ ही नहीं पा रही थी। मलेशियाई खिलाड़ी थकी हुई लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि उनमें ऊर्जा नहीं बची है। देविका ने शानदार क्रॉस के दम पर 13 गेम प्वाइंट हासिल किए और बैकहैंड क्रॉस से पहला गेम अपने नाम किया।

जन सुचना

एतद द्वारा सर्व साधारण आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि हमारी कंपनी वी. एम. टेक्नो-सॉफ्ट प्रा. लि. को खसरा क्रमांक 359/2 का भाग, ग्राम- बरबसपुर, तहसील एवं जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ में संयुक्त जैविक चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के अंतर्गत इंसीनेरेशन सिस्टम (तेल चालित) क्षमता – (100 किग्रा प्रति घंटा), ऑटोक्लेव क्षमता – (100 लीटर प्रति बैच), श्रेडर क्षमता – (100 किग्रा प्रति घंटा) की स्थापना के लिए राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र क्र. OL/EC/BIO-MED/KORBA/3356 दिनांक 22th January, 2026. के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिया गया है। जिसकी प्रति छत्तीसगढ़ एनवायरनमेंट कंसर्वेशन बोर्ड (CECB) की ऑफिस में ओर उसकी अधिकृत वेब साइट http://parivesh.nic.in पर उपलब्ध है।

वी. एम. टेक्नो-सॉफ्ट प्रा. लि.
जी-3, सेक्टर -1, अवन्ती विहार, रायपुर (छ.ग.)
इमेलः info@vmtspl.com, फ़ोन नंबर – 0771-4089634

ये था दुनिया का सबसे अमीर आदमी! हज यात्रा में लेकर गया था 18 टन सोना

दुनिया में आज जब सबसे बड़े रईसों में शामिल एलन मस्क और मुकेश अंबानी जैसे अरबपतियों की दौलत की चर्चा होती है तो लोगों को लगता है कि यही इंसान अब तक के सबसे अमीर हैं लेकिन इतिहास गवाही देता है कि एक समय ऐसा भी था जब एक राजा की संपत्ति इतनी अधिक थी कि आज के किसी अरबपति के मुकाबले उसे नापना भी मुश्किल पड़ जाए। इस राजा का नाम था मानसा मूसा, जो माली साम्राज्य का सम्राट था। मूसा को इतिहास का सबसे अमीर इंसान कहा जाता है, जिसकी दौलत के आगे आज के अमीरों की दौलत तिनका भर भी नहीं है।

सोने की खदानों पर बसा साम्राज्य

मानसा मूसा का जन्म 1280 ईस्वी में हुआ था और 1312 में वो माली साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। मूसा के शासन के दौरान माली पश्चिम अफ्रीका का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। यह क्षेत्र आज के माली, सेनेगल, आइवरी कोस्ट और बुर्किना फासो तक फैला हुआ था। मानसा मूसा की दौलत का मुख्य कारण सोना और नमक की खदानें थी, इन्हीं की वजह से इतिहास में माली दुनियाभर में व्यापार के एक प्रमुख केंद्र बन गया था।

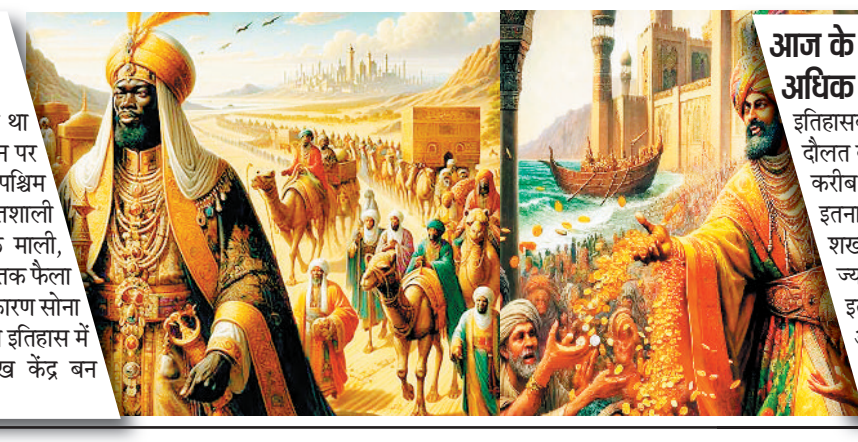

आज के अरबपतियों से करोड़ गुना अधिक दौलत

इतिहासकारों के अनुसार अगर मानसा मूसा की दौलत को आज गिना जाए तो उसकी कुल संपत्ति करीब 400 अरब डॉलर के बराबर होगी है। ये इतना बड़ा नंबर है जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कुल संपत्ति से भी कहीं ज्यादा है। सम्राट मूसा के पास सोने के भंडार इतने विशाल थे कि उसके व्यापार से पूरे अफ्रीका और अरब देशों की अर्थव्यवस्था तक प्रभावित हो जाती थी।

हज यात्रा में साथ लेकर गया 18 टन सोना

मानसा मूसा की सबसे चर्चित कहानियों में उसकी हज यात्रा का जिक्र जरूर आता है। 1324 में मूसा ने मक्का की यात्रा की थी। कहा जाता है कि मूसा अपनी यात्रा के दौरान जिन रास्तों से गुजरा वहां महंगाई बढ़ गई। बताया जाता है कि उसके काफिले में 100 ऊंट थे. जिन पर लगभग 18 टन सोना लदा हुआ था। साथ में 12000 नौकर और काफिले में करीब 60000 लोग शामिल थे। इतिहासकार लूसी दुरान के अनुसार, मानसा मूसा सिर्फ अमीर ही नहीं था बल्कि बेहद दयालु सम्राट भी था। उसके शासनकाल में टिंबकटू जैसी नगरी ज्ञान और इस्लामी शिक्षा का केंद्र बन गई थी।

रोचक खबरें

दुनिया की सबसे बड़ी ठोस सोने की मूर्ति, बैंकाक में है स्थापित

बैंकाक। दुनिया भर में बौद्ध धर्म को कई लोग मानते हैं। हर देश में इस धर्म के लोग फैले हुए हैं। दुनिया में ऐसे कई बड़े देश हैं जिनमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित हैं। दरअसल, भगवान बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है। आज हम आपको एक ऐसी बुद्ध मूर्ति के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस मूर्ति ने इतिहास, कला और अध्यात्म का नजरिया बदल दिया है। दरअसल, यह मूर्ति थाईलैंड के बैंकॉक में स्थापित है, जिसे गोल्डन बुद्ध के नाम से जाना जाता है।

पूरी ठोस सोने से बनी है यह मूर्ति: यह मूर्ति बेहद खास है क्योंकि यह कोई आम मूर्ति नहीं, बल्कि सोने से बनी हुई है। इस मूर्ति पर सोने की परत नहीं चढ़ाई गई है, बल्कि यह पूरी ठोस सोने से बनी है। दरअसल, जिस मूर्ति की हम बात कर रहे हैं, उसे सैकड़ों सालों तक मिट्टी और प्लास्टर की परत के भीतर छुपाया गया था ताकि इसे कोई लूटकर न ले जाए। इस मूर्ति को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और इसमी वास्तुकला को सराहते हैं।

दुनिया का वो अजीबोगरीब गांव, जहां न जन्म लेने की इजाजत है न मरने की...!

नॉर्वेजियन। दुनिया में 195 देश हैं और हर जगह की अपनी अलग पहचान है। इन्हीं में एक जगह ऐसी भी है जहां न तो किसी बच्चे को जन्म लेने की इजाजत है और न ही किसी व्यक्ति को मरने की। यह सुनकर हैरानी होना स्वाभाविक है लेकिन यह सच है। यह गांव लोगों की सोच से बिल्कुल अलग नियमों के साथ चलता है। यहां की व्यवस्था और जीवनशैली दुनिया के बाकी हिस्सों से काफी अलग मानी जाती है। यही वजह है कि यह जगह अक्सर चर्चा में रहती।

कहां स्थित है यह अनोखी जगह : नॉर्थ पोल से करीब 1300 किलोमीटर दूर स्वालबार्ड नाम का एक नॉर्वेजियन द्वीपसमूह है। यह जगह नॉर्वे का हिस्सा है लेकिन यहां जाना बिना वीजा के संभव नहीं है। हाल ही में ट्रैवल इंफ्लुएंसर राधिका नोमलर्स ने बताया कि यहां आना आसान है लेकिन यहां बच्चे को जन्म देना और किसी का मरना लगभग नामुमकिन है। यही बात इस जगह को दुनिया के सबसे अजीब गांवों में शामिल करती है।

इस कारण है यहां जन्म और मौत पर पाबंदी : जानकारी के अनुसार स्वालबार्ड में कोई अस्पताल नहीं है और यहां भीषण ठंड रहती है। यहां की जमीन पर्माफ्रॉस्ट है यानी साल भर जमी रहती है। इसकी वजह से यहां दफन किए गए शव सड़ते नहीं हैं। पहले इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हुई थीं। इसी कारण यहां दफनाने पर रोक लगा दी गई। अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए या बहुत बूढ़ा हो जाए तो उसे द्वीप छोड़कर नॉर्वे के मेन लैंड जाना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को भी डिलीवरी से पहले यहां से भेज दिया जाता है क्योंकि यहां उन्नत मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं. यहां कोई रिटायरमेंट होम भी नहीं है।

धरती के 88 मीटर नीचे 4000 करोड़ में बना वॉटर फॉल होटल, खूबसूरत ही नहीं सभी सुख सुविधाओं से है लैस

बीजिंग। या में ऐसी कई इमारतें हैं, जो अपनी अनोखी आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती हैं। इस लिस्ट में चीन के एक खास होटल का नाम भी शामिल है। यह होटल एक खदान के अंदर बना है और वॉटर फॉल होटल के नाम से जाना जाता है। आइए जानें क्यों इसे यह नाम मिला और इस होटल की खासियत क्या है। चीन के शंघाई शहर के सोंगजियांग जिले में स्थित इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड होटल आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। यह अनोखा होटल एक पुरानी खदान के अंदर बना है, जिसकी वजह से इसे 'क्वारी होटल' या 'खदान होटल' के नाम से भी जाना जाता है।

इसलिए कहलाता है वॉटरफॉल होटल

होटल की सबसे खास बात इसकी संरचना है, जो 88 मीटर गहरी खदान की दीवारों में बनाई गई है। इसमें कुल 18 मंजिलें हैं, जिनमें से 16 भूमिगत और दो मंजिलें पानी के नीचे स्थित हैं। इसके सामने 90 मीटर ऊंचा कृत्रिम झरना होटल की खूबसूरती में चार चांद लगाता है, जिसके कारण इसे 'वॉटरफॉल होटल' भी कहा जाता है।

आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण

युद्ध के दौरान बनाया गया था बंकर, अब बन गया होटल

इस होटल का इतिहास काफी दिलचस्प है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में हुई और इसे पूरा करने में करीब 4 हजार करोड़ रुपये की लागत आई। इस खदान को 1950 के दशक में जापानियों ने युद्ध के दौरान बंकर बनाने के लिए खोदा था। बाद में इसे आंशिक रूप से पानी से भरकर एक आर्टिफिशियल झील में बदल दिया गया। साल 2006 में शंघाई के एक प्रॉपर्टी ग्रुप ने इस जगह में संभावना देखी और इसे एक लग्जरी होटल में तब्दील करने का फैसला किया।

इनवर्टेड ग्राउंडस्क्रेपर के नाम से भी जाना जाता है

इस होटल को डिजाइन करने के लिए कई मशहूर आर्किटेक्चर फर्म्स को चुना गया। होटल की डिजाइन में फेंगशुई के प्रिंसिपल्स को अपनाया गया है और इसे 'इनवर्टेड ग्राउंडस्क्रेपर' कहा जाता है, क्योंकि यह ऊपर की बजाय नीचे की ओर बना है। ऊपर से देखने पर इसका आकार 'एस' जैसा दिखता है।

होटल में 337 कमरे, वॉइस कंट्रोल सिस्टम

इस होटल में कुल 337 कमरे हैं, जिनमें से हर एक में वॉइस-कंट्रोल सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।इस होटल में ठहरना केवल आराम का नहीं, बल्कि रोमांच का भी अनुभव है। यहां क्लिफ के किनारे बने विला और पानी के नीचे बने सुइट्स हैं, जहां कांच की दीवारों से मेहमान सीधे झील के भीतर का नजारा देख सकते हैं।

हर सुख-सुविधा का सामान मौजूद है इस होटल में

खाने-पीने के लिए होटल में पानी के नीचे बना सीफूड रेस्टोरेंट, कैंटोनीज फाइन डाइनिंग और क्वारी बार जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। इसके अलावा, होटल में वॉटर स्पोर्ट्स एरिया, इंफिनिटी पूल और स्पा की सुविधा भी है। रोमांच पसंद करने वालों के लिए पास के थीम पार्क में जिपलाइन, बंजी जंप, रॉक क्लाइम्बिंग और ग्लास वॉकवे जैसी गतिविधियां मौजूद हैं।

जापान की कुछ फेमस चीजें जिनकी कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश

जापान न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में बल्कि और भी कई मामलों में दुनिया भर का आकर्षण का केंद्र है। बता दें कि इन चीजों को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिली है। आज हम आपको जापान की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे लेकिन उन्हें खरीदने वाले आज भी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।

युबारी किंग मेलन, एक जोड़ी 22 लाख में

जापान में "युबारी किंग मेलन" पाया जाता है। इसकी कीमत 27,000 डॉलर यानी लगभग 22 लाख रुपए होती है। दरअसल, यह एक जोड़ी की कीमत है। खास तौर पर यह खरबूजा युबारी क्षेत्र में उगाया जाता है। इसकी इतनी कीमत की वजह इसका आकार और लाजवाब मिठास है। अक्सर इन खरबूजों की नीलामी होती है।

ब्लूफिन टूना मछली, 23 करोड़ से ज्यादा में बिकी

बता दें कि जापान की ब्लूफिन टूना मछली भी बेहद महंगी है। यह दुनिया की सबसे महंगी चीजों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। साल 2019 में 278 किलोग्राम वजनी एक टूना मछली को 31 लाख डॉलर यानी करीब 23.5 करोड़ रुपए में बेचा गया था। इस मछली का इस्तेमाल जापान की सबसे महंगी डिश "सुशी" और "सशिमी" बनाने में किया जाता है। इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है।

1968 होंडा सीबी 750 मोटरसाइकिल

जापान में 1968 होंडा सीबी 750 मोटरसाइकिल की नीलामी को जापान की सबसे महंगी बाइक में गिना जाता है। साल 1968 में होंडा द्वारा सिर्फ चार ही ऐसी बाइक बनाई गई थीं। हर एक बाइक को 1.45 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया था। यह बाइक अब जापान की सबसे महंगी चीजों में शामिल है।

जापान की व्हिस्की, 50 लाख रुपए बोतल

जापान के "यामाजाकी" और "हिबिकी" जैसे प्रमुख व्हिस्की ब्रांड सबसे पुराने और लिमिटेड एडिशन के लिए जाने जाते हैं। इन एडिशन्स की नीलामी बेहद महंगी होती है। बता दें कि जापान में इन व्हिस्की की कीमत लगभग 50 लाख रुपए प्रति बोतल तक पहुंच जाती है। इस व्हिस्की की कीमत की वजह दुनिया भर में बढ़ती मांग और इसकी बेहतरीन क्वालिटी है।

गुफा में मिला 60000 साल पुराना जहरीला तीर

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में वैज्ञानिकों को शिकार में इस्तेमाल होने वाले ऐसे जहरीले तीर मिले हैं, जो लगभग 60,000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। इस खोज ने यह साबित कर दिया है कि उस दौर का मानव न केवल औजार बनाना जानता था, बल्कि उसने प्रकृति में मौजूद जहर का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका के शोधकर्ताओं ने क्वाजुलु-नताल इलाके की उम्लातुजाना रॉक शेल्टर नाम की गुफा से क्वार्ट्ज के बने इन तीरों को ढूंढ निकाला है।

प्राचीन शिकार की अनोखी तकनीक : वैज्ञानिकों के मुताबिक इन तीरों पर लगाया गया जहर शिकार को तुरंत नहीं मारता था, बल्कि उसकी रफ्तार को धीमा कर देता था ताकि उसे आसानी से पकड़ा जा सके। जांच में पता चला है कि यह जहर दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय जहरीले पौधे 'बूफोन डिस्टिका' के कंद से तैयार किया गया था। यह पौधा इतना खतरनाक है कि यह चूहे को महज 20-30 मिनट में मार सकता है और इंसानों में कमजोरी और धुंधली नजर जैसी दिक्कतें पैदा करता है। खास बात यह है कि यही जहर बाद के ऐतिहासिक

हरिभूमि कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक प्रियंक सिंह परिहार द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशन्स, रिंग रोड नं. 2, गौरवपथ, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495001 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, रिंग रोड नं. 2, गौरव पथ, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495001 से प्रकाशित। प्रधान संपादक : डॉ. हिमांशु द्विवेदी, : RNI No. CHHHIN/2001/03764, फोन : 07752-401050, फैक्स : 07752-401052. e-mail :